₹ 20
www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
अगस्त 2026

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

बिहार का 'बीएमडब्ल्यू बिन्स' घोटाला:

कूड़ेदान के नाम पर सरकारी खजाने में 276 करोड़ की सुनियोजित लूट

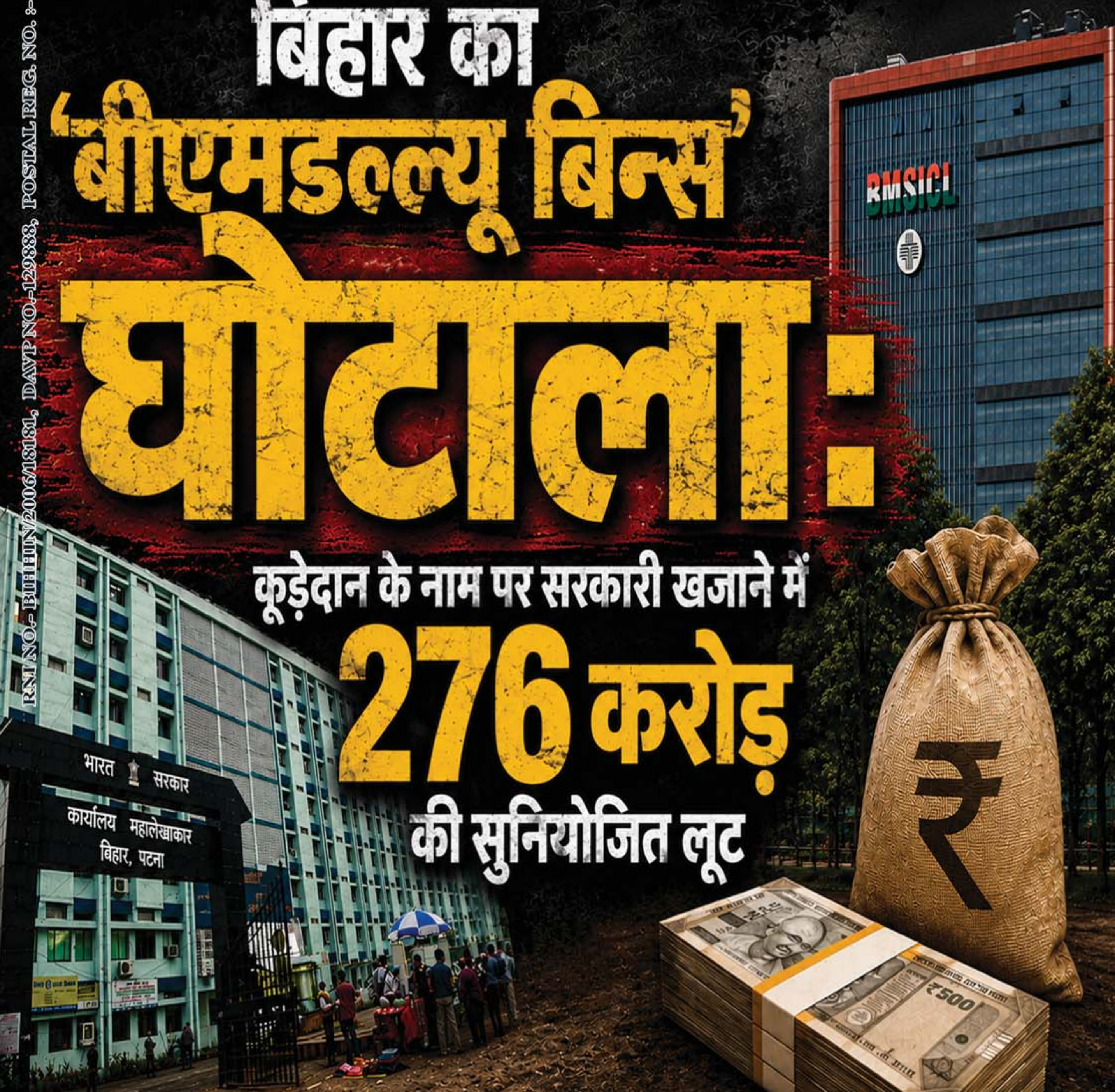

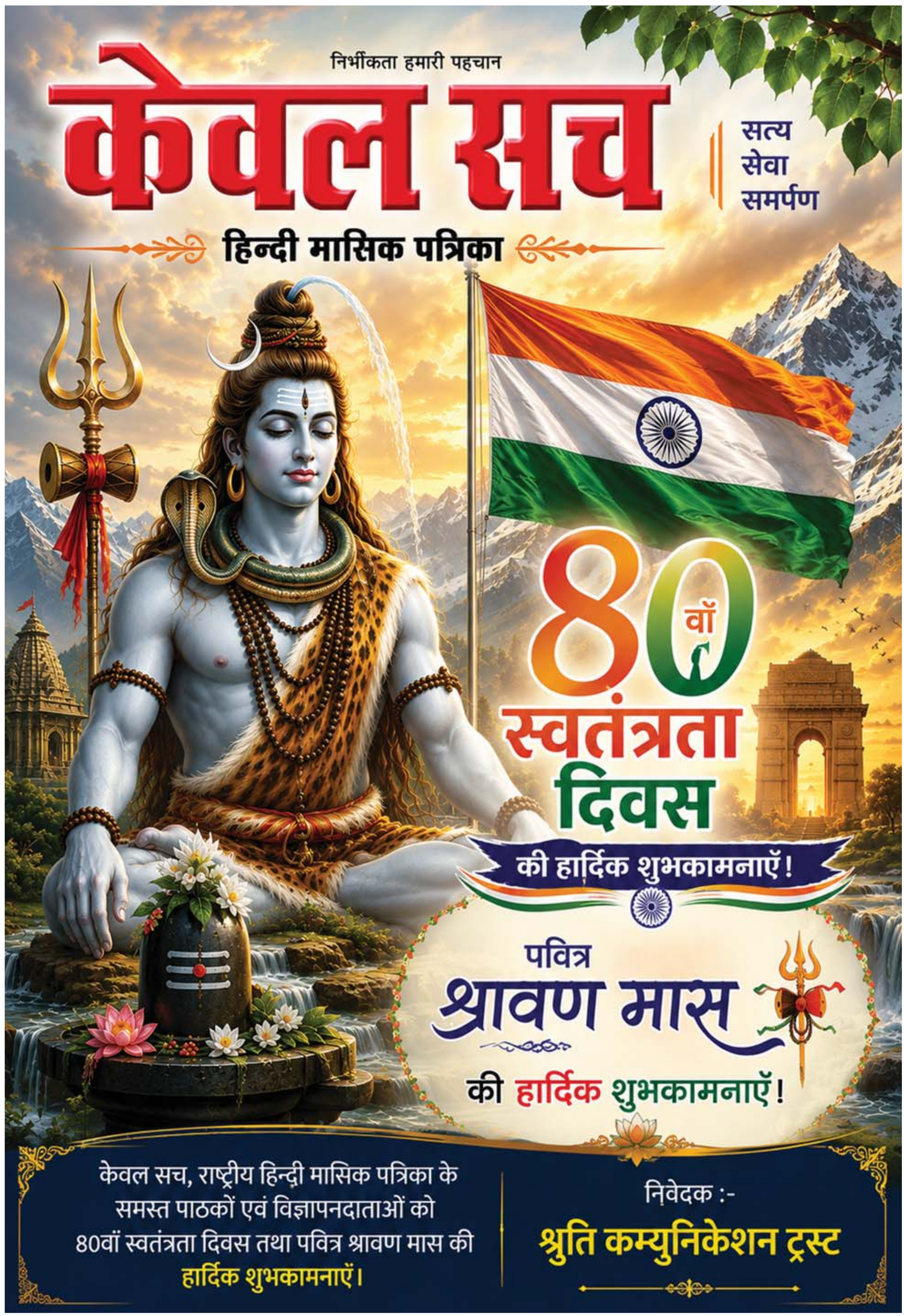

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
सत्य
सेवा
समर्पण
हिन्दी मासिक पत्रिका
80 वाँ
स्वतंत्रता
दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएँ!
पवित्र
श्रावण मास
की हार्दिक शुभकामनाएँ!
केवल सच, राष्ट्रीय हिन्द्री मासिक पत्रिका के
समस्त पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं को
80वां स्वतंत्रता दिवस तथा पवित्र श्रावण मास की
हार्दिक शुभकामनाएं।
निवेदक :-
श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

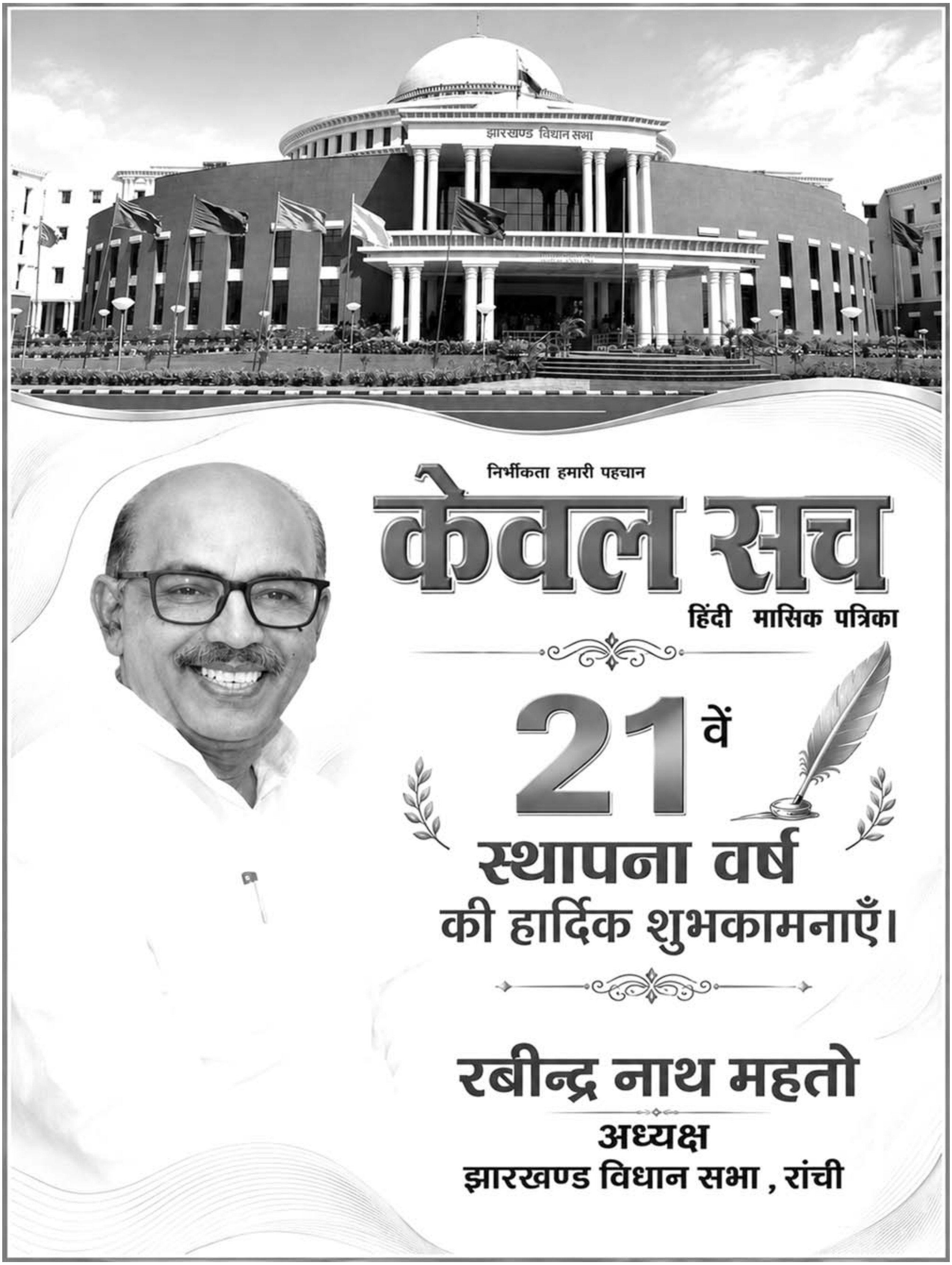
झारखण्ड विधान सभा
निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिंदी मासिक पत्रिका
21 वें
स्थापना वर्ष
की हार्दिक शुभकामनाएँ।
रबीन्द्र नाथ महतो
अध्यक्ष
झारखण्ड विधान सभा , रांची

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna- 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave,
Second Floor, Flat No. 2B,
Near-firing range,
Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha,
A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla
Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991,
09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near- md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880
09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेबसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेबसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

80वां महापर्व है आजादी

खूनी संघर्ष, जेल की यातना, फाँसी पर झूलते युवा, जालियावाला बाग की खूनी शहादत जैसे सैकड़ों घटनाएं एवं चिखती - बिलखती आवाजों के बीच लगभग 200 वर्षो की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली और आजादी का जश्न 15 अगस्त 1947 को पहली बार बड़े ही धूम-धाम से मनाया गया। 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस) को भारत का संविधान भी लागू हो गया और देश धीर - धीरे आगे बढ़ता गया और हम आज आजादी के मूल महत्व को समझते हुए 2026 में यात्रा कर रहे हैं जहां आजादी का जश्न देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खुलेआम सोसल मीडिया पर गाली देने में कामयाब हो चुके हैं। आजाद होते ही आरक्षण की व्यवस्था ने देश को गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया और एक खेमा गरीब नहीं रहने के बाद भी आरक्षण का लाभ लेकर भी विकसित नहीं हुआ और एक खेमा गरीब होकर भी जाति के कारण विकसित नहीं हो पा रहा है। मोदी सरकार आजादी का अमृत काल का दौर है का दावा कर रही है और लोग चंदाचोर का आरोप लगा रहे हैं। 2014 के बाद 2026 में दिल्ली में हुए आन्दोलन एवं उसमें भाषा का इस्तेमाल ने यह एहसास करा दिया कि देश फिर गुलामी की ओर जा रही है। लाखों लोगों का बलिदान को आंख दिखाती आजाद भारत की राजनीति पर क्या हम आजादी का 80वां राष्ट्रीय महापर्व को अमृत काल को समझ सकते हैं।

— — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769

भारत आजाद भले ही हो गया लेकिन आजादी का मूल तात्पर्य से आज भी राजनीतिक दृष्टिकोण से भ्रमित ही है। आजादी के नाम पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को खुल्लेआम गाली देने की मानसिकता धीरे-धीरे विकसित होने लगी है तथा राजनीतिक पार्टी का नाम भी कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया जाता है। आरक्षण के नाम पर देश के भीतर जातिवाद का कूटनीति करके गृहयुद्ध का माहौल बनाना, आपस में विचारो का विवाद एवं झगड़ा होने पर एससी/एसटी एक्ट लगाना (कई झुठे मामले प्रकाश में आ चुके हैं) तथा अब शिक्षण संस्थानों में यूजीसी 2026 काला कानून आजादी के अमृत काल का गंगाजल पिलाने की कोशिश किया जा रहा है को साबित किया जा रहा है। आजादी के पूर्व अंग्रेजी हुकूमत ने जनता को खुले में विकास करने के लिए कई बुनियादी चीजों को दिया है। आजादी के बाद जितनी तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ उसके दोगुनी स्पीड से भ्रष्टाचार ने अपनी जड़े देश के विभिन्न राज्यों में फैला चुकी है। 80 साल में हजारों घोटाले हो चुके हैं और सरकारी योजना सिर्फ कागजों एवं पदाधिकारी और राजनेताओं के बंगले की इर्द-गिर्द ही घुमते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है और ना ही कोई प्रोडक्ट जिसमें घोटाला नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि आजादी के महापर्व में जलेबी का भी घोटाला हो जाता है और हम ''जय हिंद'' के नारे में फंसे हुए हैं। ''बहुत हुई मंहगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार'', ''बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अबकी बार मोदी सरकार'', ''बहुत हुई बेरोजगारी की दर,अबकी बार मोदी सरकार'', ''काला धन वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15 -15 लाख डाले जायेगे'', ''अच्छे दिन आने वाले है, मंहगें दिन जाने वाले हैं'', ''पहली ही मीटिंग में किसानो का कर्ज माफ और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशे लागू'', ''जैसे-जैसे रुपया गिरता है, वैसे-वैसे देश की ईज्जत गिरती है'', ऐसे बयान को विपक्ष टारगेट करके पीएम मोदी को घेरता है। विपक्ष कुछेक मामलों में मोदी के बयान पर सटीक वार करता है इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन आजादी के इस महापर्व को आवाम किसी को खुलेआम गाली देता है। जिस प्रकार आजादी के बाद सरकार ने अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेद-भाव करके अपमानित करने का अधिकार सौंप दिया तथा उसपर मुआवजा अलग से प्रावधान कर दिया। क्या आजाद भारत में सवर्णो को रहने का अधिकार नहीं है? क्या सवर्ण के बच्चे जन्मजात अपराधी होंगे? क्या सवर्ण के बच्चे 90 अंक लाकर अयोग्य रहेंगे? सरकार किसी भी दल की हो लेकिन सबके टारगेट पर सवर्ण ही रहते हैं और जाति एवं धर्म के नाम पर आपस में लड़वाकर अंग्रेजी हुकूमत की ''फूट डालो, राज करो'' वाली नीति अपनाई जा रही है। देश की आजादी का मतलब जातिय उन्माद फैलाना और अपने ही देश की जनता को आपस में लड़वाना महापर्व का उद्देयश है? ''तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'' नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बयान अब मायने नहीं रखते। ''आराम हराम है'' कहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अब सबसे बड़े अपराधी घोषित किये जाते हैं। ''करो या मरो'' का नारा देने वाले महात्मा गांधी आज सबसे अधिक गाली सुनते हैं और देश का बंटवारा करके भारत को कमजोर करने का काम किया है का भी आरोप लगाया जा रहा है। वहीं देश को स्थिर एवं मजबूत सरकार जो भेदभाव से उपर उठकर प्रत्येक भारतीय के लिए काम करे का नारा देकर देश की आवाम को आंमत्रित किया था। ''दिल्ली चलो'' का विचार देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ किताबों के पन्नों में सिमट चुके हैं। ''स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा'' की बात को कहने वाले बाल गंगाधर तिलक की भूमिका भी आज संदिग्ध नजरों से देखा जाने लगा। है। ''सत्यमेव जयते'' को मजबूत पहचान देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय के वंशजों को खुलआम गाली दिया जा रहा है। आजादी का मतलब यही है कि आपको गाली सुनना है और चुप रहना है अन्यथा आपको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया जायेगा। ''जय जवान-जय किसान'' का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सादगी सिर्फ उनके जन्मदिवस एवं पुण्यतिथि पर याद किये जाते हैं। ''मनुष्य स्वभावत: एक राजनीतिक प्राणी है'' महान दार्शनिक अरस्तू ने ब्लिकुल सही बात कही लेकिन भारत की राजनीति 1947 में मिली आजादी के बाद बिल्कुल बदल चुकी है।' 2047 में भारत विश्वगुरू बनने की राजनीतिक बयानबाजी करने वाली भाजपा खुद 2026 में ही भारत के भीतर ही यूजीसी 2026 को लेकर गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर चुकी है। चारो तरफ 80 वर्षो से चल रही आरक्षण नीति को आथिक आरक्षण हो, आन्दोलन चल रहा है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद भारत देश के सामने देश का विभाजन, भीषण शरणार्थी संकट, 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण और नए राष्ट्र का निर्माण जैसी बड़ी चुनौतियाँ थीं लेकिन इसके बावजूद देश ने अपना संविधान बनाया, लोकतंत्र की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की। आजादी को राष्ट्रीय महापर्व के रूप में मनाया जाता है लेकिन जातिवादी आरक्षण ने देश के तरक्की को रोक दिया है। चुनाव में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, नामांकन में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, बोलचाल में आरक्षण से क्या इसे आजादी का महापर्व मनाया जायेगा? आजादी का अमृत काल, कुछ समुदाय के लिए विषकाल बन चुका है।

जुलाई 2026

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

खंड

ब्रजेश जी,

जुलाई 2026 अंक का संपादकीय ''अखंड, खंड-खंड में'' में आपने भारत की गुलामी एवं आजादी के बीच के संघर्षों का वास्तविक विचारों को एकत्रित करके लिखा गया है। कब कौन देश आजाद हुआ और वह देश आज विकास की कैसी पटकथा लिख रहा है और भारत अखंड होकर भी कैसे खंड-खंड में बंटता जा रहा है। आजादी के बाद सरकार नहीं चाहती कि भारत के लोग एकसाथ मिलकर रहें और विकास की गति को तेज करें। हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति में आरक्षण के कारण देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है।

✦ शंकर जैन, बाबू बाजार, कोलकात्ता, पं. बं

सियासी जंग

ब्रजेश जी,

केवल सच पत्रिका के जुलाई 2026 अंक में प्रकाशित वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार की खबर यूपी में 2027 से पहले राम के नाम पर छिड़ी नई सियासी जंग में चढ़ावा चोरी से लेकर धर्म की कूटनीति की जा रही है। वोट हासिल करने के लिए योगी एवं शाह का गुट सक्रिय हो चुका है। अमित कुमार की खबर **''हे राम! कैसे किया यह काम? जब चौकीदार ही चंपत तो फिर खजाना कैसे बचेगा?''** शीर्षक सबकुछ बता रहा है। संजय सक्सेना की खबर भी पठनीय है। सटीक खबरों का समावेश है।

✦ जयप्रकाश गुप्ता, करमटोली चौक, राँची

न्याय

मिश्रा जी,

जुलाई 2026 अंक के केवल सच पत्रिका में प्रकाशित अमित कुमार की खबर 'भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर या हत्या, कब मिलेगा न्याय?' में सरकार एवं पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहे कार्रवाई पर सटीक समीक्षात्मक खबर को पाठकों के बीच रखकर उन बिंदुओं पर जांच करने का ध्यान पुलिस विभाग को आकृष्ट कराया है जिससे मामला स्पष्ट हो जाएगा कि यह एनकाउंटर था या हत्या?. सही मायने में यह खबर बिहार पुलिस के कारनामे को उजागर करता है और ऐसे ही पत्रकारिता करने वाले लोग न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं. स्पष्ट, सटीक एवं दमदार खबर के लिए साधुवाद.

✦ संजय वर्मा, अशोक नगर, नई दिल्ली

क्रांतिकारी युवा

मिश्रा जी,

अमित कुमार का जुलाई 2026 अंक के विशेषांक **''देश की आजादी एवं क्रांतिकारी युवा''** खबर में गुलाम भारत एवं आजादी के लिए किये गये संघर्ष को पूरे विस्तार से लिखा है जो संग्रह करने योग्य है। 1857 का सैनिक विद्रोह एवं मंगल पाण्डेय के अदम्य साहस का इतिहास को जीवंत करने का कार्य किया है। इस अंक में अन्य क्रांतिकारी को भी उचित स्थान देने की सफल कोशिश की है। विशेषांक की विभिन्न खबरें भी पढ़ने योग्य है। केवल सच, पत्रिका सिर्फ खबर हीं नहीं लिखती है बल्कि सामाजिक मूल्यों पर काम करती है। यह विशेषांक युवाओं को प्रेरित करती है। यह अंक सच में विशेष है।

✦ सुनील यादव, रामकृष्णा नगर, पटना, बिहार

संदेश

संपादक जी,

मैं आपकी पत्रिका केवल सच पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसकी सभी खबरों को पढ़ता हूं। जुलाई 2026 अंक विशेषांक के रूप में मिला और इसमें प्रकाशित देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का शुभकामना पत्र बिहार की छवि एवं केवल सच पत्रिका का सार्थक प्रयास को सराहा है। आपकी पूरी टीम का नियमित प्रयास की वजह से **केवल सच** मीडिया देश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है। मंगल पाण्डेय एवं क्रांतिकारियों पर लिखा गया खबर पठनीय एवं संग्रहनीय है। भीड़ से हटकर आपकी पत्रिका काम करती है जो बधाई की पात्र है।

✦महेन्द्र सक्सेना, संगम बिहार कॉलोनी, नई दिल्ली

सरकार

संपादक जी,

शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की संयुक्त खबर **''कुलाधिपति कार्यालय की छाया में फल फूल रहा भ्रष्टाचार''** में सटीक जानकारी एवं प्रमाण के साथ लिखा जाना पत्रकारिता को मजबूत बनाता है. बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर सरकार भले ही राजनीतिक मंचों से बड़ी-बड़ी बात कर ले परंतु राज भवन की राह में भटकती बिहार की उच्च शिक्षा बड़ी चुनौती बनकर सरकार के सामने आ चुका है. आरिफ मोहम्मद खा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन धारण करके भ्रष्टाचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से जिसकी वजह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।

✦ प्रेम कुशवाहा, टावर चौक, भागलपुर, बिहार

अन्दर के पन्नों में

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, **DAVP No.- 129888**

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 21	अंक:- 243	माह:- अगस्त 2026	मूल्य:- 20/- रू.

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र
श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204
सुरजीत तिवारी 9431222619
निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854
सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917
डॉ० शशि कुमार 9507773579
चंद्र शेखर कुमार 9931965035

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350
अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000
triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819
गीतांजलि 9279599313, 8294636307

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय 7488696914
ललन कुमार 7979909054, 9334813587

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212
राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565
काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829
कुमार अनिकेत 9431914317
शंकरानंद ठाकुर 9971103281

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

सोनू यादव 8002647553, 9060359115
संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

श्रुति मिश्रा 8340360961

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-		
	:-		
गया (श०)	:-		
(ग्रा०)	:-	मो० सईद	6299169764
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9162664468
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-	रमेश कुमार	8298588504
जमुई	:-	अजय कुमार	9430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:- .		
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
................................., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

................................., स्टेट हेड
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 38003315950
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

....

....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023
....

संयुक्त संपादक

....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672
....
....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :-
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140
मुकेश कुमार	9473038020

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	7766081555

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो

राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

Prof. Ashim Kumar Ghosh
Governor, Haryana

सत्यमेव जयते

प्रो० असीम कुमार घोष
राज्यपाल, हरियाणा

HLB/PRO-MSG/2026-89
Dated-23 .07.2026

MESSAGE

It is a matter of great delight to learn that *Kewal Sach*, a monthly Hindi magazine, is bringing out a special edition on the theme *Desh Ki Aazadi Evam Krantikaari Yuva*. The theme is both timely and inspiring, as it reminds us of the invaluable sacrifices, courage and unwavering commitment of the young freedom fighters who dedicated their lives to India's struggle for independence. Their patriotism, resilience and spirit of selfless service continue to inspire us and serve as a guiding light for the youth of today.

As India marches towards the vision of a Viksit Bharat by 2047, marking the centenary of our Independence, the role of young people has become more significant than ever. The aspirations of a developed nation can be realized only through the active participation of an enlightened, skilled, innovative and socially responsible youth. Today's young citizens must draw inspiration from the ideals of our freedom fighters and channel their energy towards nation-building.

Equally important is the commitment to building an inclusive India where every citizen, irrespective of caste, creed, gender, language, region or socio-economic background, has equal opportunities to contribute to national progress. The youth must become ambassadors of unity, constitutional values, mutual respect and compassion, fostering a society that celebrates diversity as its greatest strength.

I am confident that this special edition of *Kewal Sach* will not only pay a fitting tribute to the revolutionary youth who shaped our nation's destiny but will also motivate today's generation to become active partners in realizing the dream of an inclusive, prosperous, self-reliant and developed India by 2047.

Congratulations and best wishes!

(Prof Ashim Kumar Ghosh)

रबीन्द्र नाथ महतो
अध्यक्ष
झारखण्ड विधान सभा
राँची

RABINDRA NATH MAHATO
SPEAKER
JHARKHAND LEGISLATIVE ASSEMBLY
RANCHI

सत्यमेव जयते

पत्रांक / Letter No. : ....

दिनांक / Date : 08/07/2026

–ःशुभकामना संदेशः–

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है कि राष्ट्र की प्रखर एवं निष्पक्ष आवाज, राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका 'केवल सच' आगामी 19 जुलाई 2026 को अपनी गौरवमयी भाषाई एवं पत्रकारिता यात्रा के सफल 21 वर्ष पूर्ण कर अपना '21वां स्थापना दिवस' मनाने जा रही है। दो दशकों से भी अधिक समय तक निरंतर पत्रकारिता के उच्च आदर्शों, शुचिता और निर्भीकता को अक्षुण्ण रखना किसी भी संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक और असाधारण उपलब्धि है। इस गरिमामय और गौरवशाली अवसर पर, मैं पत्रिका के यशस्वी संपादक सह प्रबंधक तथा बिहार विधान परिषद (पटना) की प्रेस सलाहकार समिति के माननीय सदस्य श्री ब्रजेश मिश्रा जी सहित 'केवल सच' परिवार के समस्त पत्रकार बंधुओं, तकनीकी सहयोगियों और सुधी पाठकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 'केवल सच' पत्रिका ने बीते 21 वर्षों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। श्री ब्रजेश मिश्रा जी के कुशल, दूरदर्शी और प्रबुद्ध नेतृत्व में इस पत्रिका ने मूल्य–आधारित पत्रकारिता का एक नया मानदंड स्थापित किया है। मैं 'केवल सच' पत्रिका के इस ऐतिहासिक 21वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर संस्थान के उत्तरोत्तर विकास और उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

सद्भावनाओं और उज्ज्वल भविष्य की अनंत आकांक्षाओं के साथ।

रबीन्द्र नाथ महतो
08.07.26
(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्षीय कार्यालय : दूरभाष : 0651-2440400, फैक्स : 0651-2441712, मोबाईल : 9431370329, 8002513007
आवासीय कार्यालय : दूरभाष : 0651-2281884, फैक्स : 0651-2284046
e-mail : speaker.jla@gov.in

नैयर हसनैन खान, भा०पु०से०
Nayyar Hasnain Khan, I.P.S.

सत्यमेव जयते

अपर पुलिस महानिदेशक
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना
Additional Director General of Police
Bihar Special Armed Police, Bihar, Patna

पटना, दिनांक–20.07.2026

अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या....51..../गो0

–: शुभकामना संदेश :–

यह जानकार अत्यंत प्रसन्नता हुई कि **"केवल सच"** हिन्दी मासिक पत्रिका दिनांक–19 जुलाई, 2026 को अपने 21वें स्थापना वर्ष के अवसर पर **"देश की आजादी एवं क्रांतिकारी युवा"** के विशेषांक का प्रकाशन कर रही है, जिसका विमोचन देश–प्रदेश के कई गणमान्य एवं प्रबुद्धगणों की उपस्थिति एवं उनके हाथों सम्पन्न होना है। इस अवसर पर विभिन्न सेवा के उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मयोगियों को **"क्रांतिकारी मंगल पाण्डेय केवल सच सम्मान–2026"** से सम्मानित किया जा रहा है। जो नई–पीढ़ी के लिए प्रभावी एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

मैं उक्त समारोह एवं विशेषांक के सफल एवं निरंतर प्रकाशन हेतु मंगल कामना करता हूँ।

विश्वासभाजन

20.7.26

(नैयर हसनैन खान)

सेवा में,

श्री ब्रजेश मिश्र जी,
सम्पादक–सह–प्रबंधकर्त्ता
"केवल सच"।

धूमधाम से संपन्न हुआ केवल सच का 21वाँ स्थापना वर्ष समारोह

● **अमित कुमार/मिथिलेश कुमार**

दिनांक 19 जुलाई 2026 को श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के बैनर तले ''केवल सच'' राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका ने बड़े धूमधाम के साथ राष्ट्र प्रेम से सराबोर होकर अपना 21वां स्थापना वर्ष राजधानी पटना के अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन सचिवालय कैम्पस में मनाया। विदित हो की उक्त स्थापना वर्ष के अवसर पर ''केवल सच'' स्वाधीनता आंदोलन के अग्रदूत, सिपाही विद्रोह के नायक, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 'शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडेय' की जीवनी और संघर्ष पर उनकी जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

केवल सच के 21वें स्थापना वर्ष के कार्यक्रम में मुख्य एवं विशिष्ठ अतिथियों में बिहार विधान सभा अध्यक्ष, डॉ० प्रेम कुमार, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार श्री अशोक चौधरी, खान एवं भूतत्व तथा कला एवं सस्कृति मंत्री, बिहार श्री प्रमोद कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार श्री मिथिलेश तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मजदूर यूनियन कांग्रेस (इंटक) श्री चंद्रप्रकाश सिंह एवं सहरसा विधायक आई-पी- गुप्ता शामिल हुए।

कार्यक्रम का विधिवत् उद्‌घाटन बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार एवं मजदूर यूनियन कांग्रेस (इंटक) श्री चंद्रप्रकाश सिंह एवं केवल सच के संपादक सह संस्थापक ब्रजेश मिश्र के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। उसके बाद मंचासीन अतिथियों ने क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केवल सच द्वारा प्रकाशित विशेषांक ''देश की आजादी एवं क्रांतिकारी युवा'' का विमोचन मंचासीन अतिथियों के हांथों संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान समाज में उत्कृष्ट कार्य से सेवा दे रहे कर्मयोगियों को ''क्रांतिकारी मंगल पांडे केवल सच सम्मान-2026'' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मंच पर उपस्थिति अतिथियों के हांथो दिया गया।

''क्रांतिकारी मंगल पांडे केवल सच

केवल सच द्वारा प्रकाशित विशेषांक ''देश की आजादी एवं क्रांतिकारी युवा'' का विमोचन करते अतिथिगण

सम्मान-2026'' से सम्मानित होने वाले कर्मयोगियों में जो शामिल थे, वे निम्नवत् हैं :-

01. डॉ. अजय कुमार सिंह, चिकित्सा सेवा, सहरसा।
02. श्री रंजन कुमार, पुलिस सेवा, एसडीपीओ-2, पटना सदर।
03. श्री सुधीर कुमार गिरी, वित्त सेवा, वरीय कोषागार, जमुई।
04. श्री अमित कुमार पटेल, प्रशासनिक सेवा, एसडीओ, हिलसा, नालंदा।
05. प्रो. डॉ. गजेन्द्र प्रसाद गडकर, उच्च शिक्षा सेवा, प्राचार्य।
06. श्री चन्द्रशेखर आजाद, समाज सेवा, बैंक की नौकरी छोड़ समाजसेवा।
07. श्री लव कुमार मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार।
08. कुमार अभिषेक, इंजीनियरिंग सेवा, EE लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण।
09. अभिनव कुमार, नगर सेवा/प्रशासनिक सेवा, EO खगौल नगर परिषद्।
10. कृष्ण मुरारी प्रसाद, पुलिस सेवा, ASP कोतवाली।
11. निलेन्दु कुमार झा, प्रधान संपादक।
12. शशि रंजन सिंह, पत्रकार।
13. राजीव कुमार शुक्ला, पत्रकार।
14. सोनू यादव, पत्रकार।
15. बेंकटेश कुमार, पत्रकार।
16. कुमार अनिकेत, पत्रकार
17. ओमेन्द्र कुमार पाण्डेय, पत्रकार सह शिक्षक।
18. अभिषेक कुमार सिन्हा।
19. सुश्री सैलजा, भारतीय पुलिस सेवा, IPS सिटी एसपी पूर्वी।
20. दीपक राज, पत्रकार।
21. डॉ निखिल रंजन चौधरी, चिकित्सक, आईजीआईएमएस, पटना।
22. सुश्री शांभवी झा, बाल गायिका।

केवल सच के स्थापना वर्ष और क्रांतिकारी मंगल पांडे पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने कहा की, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध खुला विद्रोह किया। यह केवल एक सैनिक का विद्रोह नहीं था, बल्कि यह उस राष्ट्र की आत्मा की पुकार थी, जो वर्षों से स्वतंत्रता के लिए तड़प रही थी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल 1857 को फाँसी पर चढ़ा दिया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक विचार को फाँसी दे रहे हैं। वह विचार आगे चलकर पूरे भारत में फैल गया और 1857 की महान क्रांति का रूप लेकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बन गया। मंगल पाण्डेय का बलिदान हमें यह सिखाता है कि साहस, स्वाभिमान और

डॉ० प्रेम कुमार

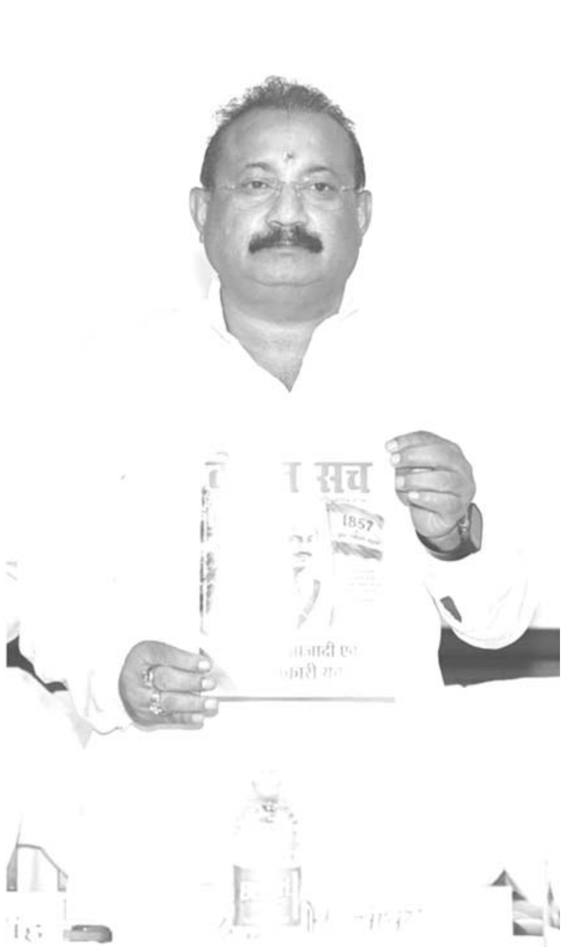

राष्ट्रभक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी होती है। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर यह संदेश दिया कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।

कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री

डॉ० अशोक चौधरी

डॉ० अशोक चौधरी ने कहा की आज हम जिस स्वतंत्र भारत में खुली हवा में साँस ले रहे हैं, उसके पीछे ऐसे असंख्य वीरों का त्याग और बलिदान छिपा है। आज के समय में हमें हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें सत्य, ईमानदारी, संवेदनशीलता और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का परिचय देना है। विशेष रूप से पत्रकारिता, शिक्षा, प्रशासन, न्याय और सामाजिक जीवन से जुड़े लोगों का दायित्व है कि वे समाज में सत्य और नैतिकता की मशाल जलाए रखें। यही शहीद मंगल पाण्डेय के आदर्शों का वास्तविक सम्मान होगा। केवल सच सम्मान समारोह केवल सम्मान देने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों को सम्मानित करने का अभियान है, जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सत्य, साहस, राष्ट्रहित और जनसेवाये चारों मूल्य मंगल पांडे के जीवन की पहचान थे और यही इस समारोह की भी आत्मा है। हम सभी संकल्प लें कि अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व को सर्वोच्च स्थान देंगे। हम अपने कार्यो से ऐसा भारत बनाने में योगदान देंगे, जिसका सपना शहीद मंगल पाण्डेय और हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। उन्होंने कहा की बिहार ने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने केवल सच के स्थापना दिवस पर प्रो० गजेंद्र प्रसाद गडकर, डॉ० अजय कुमार, चंद्रशेऽर आजाद, कृष्ण मुरारी प्रसाद, कोतवाली एएसपी, सुनील कुमार गिरी, अमित कुमार पटेल, एसडीपीओ सहित दर्जनों पत्रकारों को 'मंगल पाण्डेय केवल सच सम्मान-2026' से सम्मानित किया एवं केवल सच के सभी पत्रकारों एवं संपादक ब्रजेश मिश्रा को शुभकामनायें एवं बधाई दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि खान एवं भूतत्व तथा कला एवं सस्कृति मंत्री, बिहार श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि कलम चलाना आसान काम नहीं है, वह भी पत्रकारिता की और आज केवल सच पत्रिका 20 वर्ष पूरा कर 21वाँ स्थापना वर्ष इतने पत्रकारों के बीच मना रही है। यह काफी खुशी की बात है। आज जहां लोग प्रिंट मीडिया से दूर होते जा रहे हैं और डिजीटल होते जा रहे हैं। ऐसे में केवल सच लगातार 20 वर्षों से अपना प्रकाशन कर रहा है। इसके लिए मैं ब्रजेश जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। क्रांतिकारी मंगल पांडे की जयंती पर केवल सच

स्थापना दिवस

21वां स्थापना दिवस

स्थापना दिवस

विकास वैभव (आई.जी. मगध रेंज) को सम्मानित करते संपादक ब्रजेश मिश्र

मनोज कुमार (आई.जी. मु.) को सम्मानित करते संपादक ब्रजेश मिश्र

डॉ० सुनील कुमार (शिशु रोग विशेषज्ञ) को सम्मानित करते संपादक ब्रजेश मिश्र

द्वारा ''देश की आजादी एवं क्रांतिकारी युवा'' प्रकाशित विशेषांक हमारे इतिहास को बताने का काम कर रही है। मंगल पांडे के संघर्ष और अंग्रेजों के विरोध में स्वाधीनता के लिए किया गया विद्रोह ने आजादी की लड़ाई की नीव रखी और वह प्रथम अग्रदूत बने। उनके जयंती पर केवल सच द्वारा कराया जा रहा कार्यक्रम प्रशंसनीय है।

कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने केवल सच के 21वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी मंगल पांडे जी पर किये जा रहे कार्यक्रम की शुभकामना देते हुए संपादक ब्रजेश मिश्र जी को धन्यवाद दिया और कहा कि 20 वर्षों का सफर तय करना कम नहीं होता और केवल सच ने 20 वर्षों का प्रकाशन कर अपना 21वाँ स्थापना वर्ष मना रहा है इसमें समस्त संपादक ब्रजेश मिश्र जी के साथ सारे पत्रकारों की मेहनत का नतीजा है। मैं ब्रजेश जी को विधायक बनने के पूर्व से ही जानता हूं, इनका जुनून और तेवर बिल्कुल क्रांतिकारी मंगल पांडे जी जैसा है। आप अपने तेवर को कभी नहीं बदलीयेगा, यही आपकी सफलता की पूंजी है। क्रांतिकारी मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इसलिए शुरू किया, क्योंकि उन्हें बंदूक में डालने वाले कारतूस गाय और सुअर के चर्बी से बना होता था। अंग्रेज धार्मिक प्रभाव डालना चाह रहे थे, जिसका मंगल पांडेय ने विरोध किया और उन्हें फांसी दे दी गई। उनके फांसी से सिपाहियों में विद्रोह फैला और 1857 का यह सिपाही विद्रोह स्वाधिनता का चिंगारी बना। आगे शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बहुत जल्द बिहार में शिशु मंदिर विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा साथ ही जिस प्रकार संस्कृत विद्यालय और संस्कृत की पढ़ाई विलुप्त हो रही है उसपर काम किया जा रहा हैं। मैंने कई राज्यो में घूमकर वहां की शिक्षा नीति को समझा है और उसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली पर कार्य किया जायेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित सहरसा विधायक श्री आई-पी- गुप्ता ने केवल सच को 21वें स्थापना वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि आज के समय में पत्रकारिता कठिन हो गई है। अगर आप कोई सच्ची खबर लिखते हैं तो पत्रकारों और उनके परिवार में भय रहता है कि

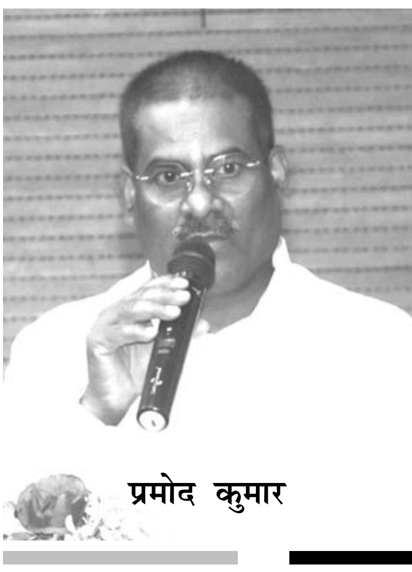

प्रमोद कुमार

मिथिलेश तिवारी

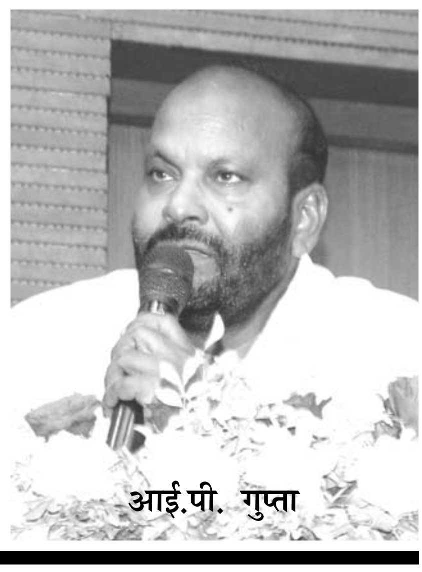

आई.पी. गुप्ता

विवेक कुमार सिंह (डीपीएम) को सम्मानित करते संपादक ब्रजेश मिश्र

चंद्रप्रकाश सिंह

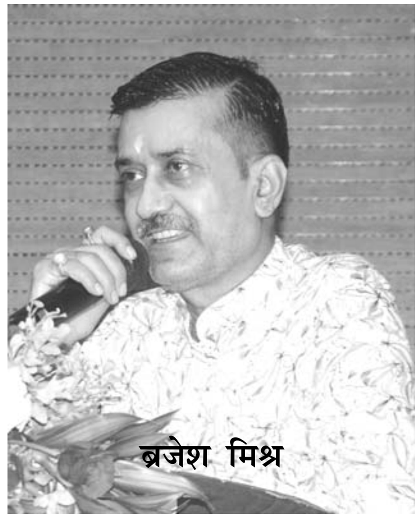
ब्रजेश मिश्र

कही कुछ हो न जाये। कई मामलों में पत्रकारों की जाने गई, जो सच्ची पत्रकारिता करते थे। आज यूट्यूब के जवाने में प्रिंट मीडिया विलुप्त होती जा रही है, लेकिन ब्रजेश जी जैसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने उसे जिंदा रखा है और इसका सबूत है इनके 20 वर्षों का प्रकाशन। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण होता है और अगर ना मिले तो प्रकाशन कर पाना मुश्किल होता है, इस कठिनाई को समझना होगा। आज केवल सच अपने स्थापना वर्ष पर क्रांतिकारी मंगल पांडे की जयंती मना रहा है और ''देश की आजादी एवं क्रांतिकारी युवा'' नाम के विशेषांक को प्रकाशित किया गया है साथ ही ''क्रांतिकारी मंगल पांडे केवल सच सम्मान-2026'' के तहत कर्मयोगियों को सम्मानित किया जा रहा है, जो अति प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं संपादक ब्रजेश मिश्र जी को बधाई एवं शुभकामना देता हूं।

नैना तिवारी

शांभवी झा

अनन्या प्रकाश

कार्यक्रम में उपस्थित मजदूर यूनियन कांग्रेस (इंटक) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं केवल सच के मुख्य संरक्षक श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने केवल सच के 21वें स्थापना वर्ष पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए संपादक ब्रजेश मिश्र और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि मैं केवल सच के इन 21 वर्षों को देखते आ रहा हूं। जब केवल सच 2006 में इसका प्रथम अंक का प्रकाशन हुआ था तो ब्रजेश जी काफी चिंतित थे कि आगे का सफर पूरा कैसे होगा? किंतु हमलोगों ने विश्वास दिलाया की आप सक्षम हैं और निरंतर पत्रिका का प्रकाशन होगा और आज 20 वर्ष पूरे होने के बाद 21 वर्ष में प्रवेश के साथ गर्व से कह सकते हैं कि केवल सच अपने मुकाम पर पहुंच चुका है और आपने करके दिखा दिया कि हौसला अगर मजबूत हो तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। आपके साथ जुड़ा पत्रकार एक परिवार है और परिवार हमेशा साथ देते हैं और इसी के बदौलत निरंतर प्रकाशन हो पाया है और आगे भी जारी रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि आज 19 जुलाई को क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की जयंती है और मैं जो देख रहा हूं कि इस सभागार को आपने देशभक्ति के माहौल में बना दिया है। हरेक युवाओं में देश के प्रति आदर सम्मान सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है। मंगल पांडे जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता की चिंगारी जलायी, उसका परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं। केवल सच द्वारा प्रकाशित विशेषांक ''देश की आजादी एवं क्रांतिकारी युवा'' को पढ़कर आजादी में क्रांतिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। एक बार फिर से मैं इसके लिए संपादक ब्रजेश मिश्र और उनकी टीम को बधाई देता हूं।

अंत में संपादक सह संस्थापक ब्रजेश मिश्र ने उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का एवं सभागार में बैठे दर्शक एवं श्रोताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपकी उपस्थिति ही हमारा मनोबल है और ये मनोबल हमेशा बना रहे इसके लिए आप हमारा साथ सदैव दिजीएगा। केवल सच प्रत्येक वर्ष बिहार, झारखण्ड और दिल्ली में कार्यक्रम कराता है और किसी महान व्यक्तित्व पर विशेषांक का प्रकाशन करता आया है। बहुत जल्द झारखण्ड में केवल सच का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। जिस प्रकार आज क्रांतिकारी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें समर्पित ''देश की आजादी एवं क्रांतिकारी युवा'' विशेषांक का प्रकाशन तथा ''क्रांतिकारी मंगल पांडे केवल सच सम्मान-2026' का आयोजन हुआ, ठीक वैसा ही कार्यक्रम कराया जायेगा। इसमें आपका सहयोग सदा बना रहे यही कामना करते हैं।

केवल सच के स्थापना वर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत होकर दर्शकों ने देशभक्ति गानों का आनंद लिया। अपनी प्रस्तुति से गायिका अनन्या प्रकाश, सांभवी झा, नैना तिवारी ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्र गीत के साथ संपन्न हुआ। ●

● अमित कुमार

'सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है'। आज पूरा देश जेन-जी बना बैठा है, खुद को कॉकरोज कहकर उग्र आंदोलन किया और अभी तक कर ही रहा है। इस छात्र आंदोलन में छात्र और पुलिस दोनो ही गंभीर रूप से चोटिल भी हुए किन्तु जब ये सब हो रहा था तब देश का चौकीदार चुपचाप यह देख रहा था। अब सियासत पर बात करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर बात कर लेना जरूरी है और इस चुप्पी को समझने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वह मनमोहन सिंह, जिन्हें दस साल तक देश ने 'मौनमोहन' सिंह कहकर मजाक उड़ाया। क्योंकि वह 2जी घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे। हर बड़े मसले पर खामोश थे और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं हैं? आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। आज भी जनता पूछ रही है कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो तीस-पचास साल में दिखा नहीं था। अफरा तफरी चारों तरफ थी। लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिसवालों को भी चोट आ रही थी। भीड़ में पत्थर चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था, उसकी झलकियां दिखाई पड़ रही थी। मेट्रो से लेकर सड़क तक

अफरा तफरी थी और ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वो सड़क से होकर जाता है, इसके बाद जो तस्वीरें आईं वो ऐतिहासिक थीं। वो ये बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही न पहुंचे। इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो न सुन पाए। अगर नहीं सुन पा रहे तो फिर क्या शोर मचाना जरूरी है? और क्या वो शोर जानबूझकर नहीं सुना गया या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया? या वो आवाजें पहुंची नहीं, क्योंकि सड़क पर गुस्सा था। प्रधानमंत्री को सब पता था और प्रधानमंत्री संसद में थे भी। लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वो सिर्फ अट्ठाईस साल के हैं, किसी छप्पन साल के नौजवान की बात नहीं हो रही! वहीं से यह सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आप बात कर सकते थे। आप क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से 12 साल हो गए। 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए, वो भी अमित शाह बोलते रहे। आप हर बड़े मसले पर खामोश होते हैं और इस बार तो बच्चे थे। अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से वो बात करते थे। वो दुश्मन थे। ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे। ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे?

आज सवाल एहसास का है। वो एहसास जो टपरी से उठकर सड़क संसद तक पहुंचा। वो एहसास जो सरकार के विरोधियों के साथ-साथ सरकार के अपने लोगों में भी पहुंचा और आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी बात तो कर सकते थे, इसमें क्या ऐसा था? कितने सारे लोगों की खून बहा। कितने लोग चोटिल हुए। कितना नुकसान हुआ। देखिए शुरुआत

में मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि यह प्रोटेस्ट राजनीतिक है। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी, आयसा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ और समाजिक संगठन जो है वह मिलकर सीजेपी की भीड़ में आ रहे हैं। लेकि वो जो नीचे भीड़ थी, लाखों की भीड़, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है इस देश के छात्र इतने बेवकूफ हैं। किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे। अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे। आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे। हफ्ता भर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है और जो बनी रहती है ना वह दर्द वाली होती है और दर्द किराए पर नहीं मिलता। बहुत सारे वहां पर अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती। वह आग देखकर हाथ सेकने आती हैं और आग किसने लगाई? उस पेपर लिक ने जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में यह मंच केवल राजनीतिक था तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में कई सारे पेपर लिक हुए हैं, उनको हटा देते। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खामोश क्यों रहते हैं हर महत्वपूर्ण विषयों पर? यह सवाल केवल आज NEET को लेकर नहीं है। पिछले दस बारह सालों का पैटर्न है और यह पैटर्न अब देश को परेशान कर रहा है कि मोदी जी चुप क्यों हैं? आप याद कीजिए मणिपुर। महीनों जला। लंबा दौरा नहीं, लंबा संबोधन नहीं। कोविड में आपको थाली बजाने का सीन याद होगा। लेकिन कोविड में जब दूसरी लहर आई थी, भाषण आए थे। ऑक्सीजन के सीधे सवाल पर सीधा जवाब कभी नहीं आया। किसान आंदोलन। साल भर वो सीमा पर बैठे रहे। ऊपर से सीधी बातचीत महीनों बाद की गई। अग्निपथ,

नरेन्द्र मोदी

जब नौजवान सड़कों पर उतरे। मंत्री बोले। प्रधानमंत्री नहीं आए। संसद में विपक्ष ने एक अंबानी-अडानी को लेकर बार बार सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कई बार जवाब दिए, लेकिन उन नामों पर एक शब्द नहीं लिया, पेपर लीक। यह तो अब एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है। हर बार मंत्री, हर बार एजेंसी लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं।

जिस जंतर मंतर पर यह हंगामा हो रहा था, इसी जंतर मंतर पर 2023 में देश की बेटियां जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहलवान थी, वो महीनों बैठी थी। जब वो लड़कियां मेडल जीतकर आई थीं तो ट्वीट हुए थे, फोटो खिंचाई गई थी, घर बुलाया गया था और हर बार होता है। कोई भी क्रिकेट टीम जीतकर आती है, मोदी जी घर बुलाते हैं। लेकिन जब वो बेटियां इंसाफ मांगने सड़क पर बैठीं तो चुप्पी। और सबसे दुखद बात है कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उन बेटियों को सड़क पर घसीटा गया। हर बार एक परसेप्शन डाल दिया जाता है कि यह विपक्ष के लोग हैं, इनका ऐजेंडा है। नई संसद जिसकी ऊंची दीवारें उस दिन भी ऊंची थी जब महिला पहलवानों को घसीटा गया था, आज बस दिखाई पड़ी हैं। कुल मिलाकर कहें तो पैटर्न बड़ा साफ है कि जहां तालियां हैं, वहां पर माइक जाता है। लेकिन जब सवाल आते हैं तो वहां खामोशी आ जाती है। लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद है। जब सरकार संवाद छोड़ देती है, तब लोकतांत्रिक संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। आसान भाषा में अगर कहें और मेंल समझाने के लिए। तो जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं तो सड़क पर शोर आता है। आज जंतर मंतर के बाद सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वह इसलिए दिखा क्योंकि सरकार ने संवाद करना छोड़ दिया था और सरकार को यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सरकारें टियर गैस से नहीं संवाद से चलती हैं। अगर सरकार यह सोचती है कि जनता ने आपको वोट देकर सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर पहुंचा दिया और यह पांच साल का ब्लैंक चेक है तो आपकी सोच गलत है। मोदी जी हमेशा थे कि हम जनता के चौकीदार हैं, तो चौकीदार की जवाबदेही तो होती है मोदी जी। जनता सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ी है। वोट के बदले जवाबदेही। 22 लाख बच्चे थे। 10 से ज्यादा मौत हो गई है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। बच्चा से लेकर पुलिस वाला तक पीटा है। कहते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इंदिरा गांधी को भी घमंड था। इतिहास में आप तुलना करते हैं नेहरू जी से, इंदिरा जी से। इतिहास की सिर्फ अच्छी घटनाओं से तुलना नहीं की जाती। इतिहास में जाकर वो भी देखिए आप। क्योंकि चोरी मुफ्त नहीं होती। उसकी कीमत अफवाह होती है और भरोसा चुकाता है देश।

गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर पर NEET पेपर लिक को लेकर पहले से जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगे शांतिपूर्ण ढ़ंग से मांग रहे थे, उसे हाइजेक करके उपद्रवी रंग दे दिया गया। सवाल है कि क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच के प्रोटेस्ट ने छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर दिया? मतलब यह सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट को देखने के बाद यह समझ में नहीं आ रहा कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा था? यह छात्र आंदोलन था, राजनीतिक रैली थी या कुछ और? मतलब अगर आपने वहां का कार्यक्रम नहीं देखा और आपको सिर्फ फोटो

विडियो दिखाया जाए तो समझ नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि यह NEET और CBSE के नाम पर छात्रों को बुलाया गया प्रदर्शन था। कभी ढपली वाला प्रोटेस्ट देखकर लग रहा था कि जेएनयू का रेगुलर प्रोटेस्ट है। कहीं पर राजनीतिक लोग नजर आ रहे थे, कहीं गरीब किसान नजर आ रहे थे। कुछ आंदोलनजीवी यहां नजर आ रहे थे। प्रोटेस्ट में आजादी, आजादी चल रहा था। कोई उमर खालिद का जिक्र कर रहा था। मंच पर जो अमेरिका से यहां आए थे वो जय भीम, जय भीम, जय भीम कह रहे थे। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता अपने पीछे बुर्जुग से पंखा हिलवा रहे थे और बैठकर कॉफी पी रहे थे। गर्मी में सांस नहीं ले पा रहे थे। अमेरिका वाले भैया भी दो चार घंटा बैठकर सीधे ए.सी. गाड़ी में बैठ गए। फिर आरएसएस मुर्दाबाद चल रहा था। कोई बुद्धिजीवी आए वो समझाने लगे कि इवीएम को हैक किया जा सकता है। एक आदमी लाल डायरी लेकर आ गया जो कह रहा है कि यह संविधान है, खोलो। लाल डायरी के अंदर उनकी अपनी शेरो शायरी लिखी पड़ी थी। 22 मिलियन फॉलोवर लेकर जिस कॉकरोच मुवमेंट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। वह शिक्षा मंत्री जिनकी अगुवाई में इस देश में कितने ऐसे शिक्षा को लेकर कुव्यवस्थाएं हुई, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़ा जनाक्रोश दिखा, बड़ी हैरानी हुई कि उन धर्मेंद्र प्रधान का नाम यहां आए लोगों को पता नहीं था। आधे लोग कह रहे थे अमित प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं। धर्मेन्द्र प्रधान और सरकार वाले हंस रहे होंगे कि हमारी सारी मुसीबत इन लोगों ने खत्म कर दी। मतलब NEET और CBSE के छात्रों के सवाल इतने जायज थे, उनका दर्द इतना जायज था उसको तमाशा बना दिया गया। क्योंकि इनके नाम पर मंच सजाया गया और सच कहें तो मंच पर छात्र के सिवा सब था। जिस मंच से पेपर लिक, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल उठाना चाहिए था। जहां पर छात्रों को आगे करके, उनके मां बाप को आगे करके मंच से कहना चाहिए था कि लाखों छात्र और उनके परिवार महीनों नहीं सालों साल मेहनत करते हैं कि निष्पक्ष परीक्षा हो। क्या इस देश में उन्हें निष्पक्ष परीक्षा नहीं मिल सकती?

वहां पर जय भीम, आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद, हमें चाहिए आजादी..। मतलब क्या यह आंदोलन छात्रों की आवाज को मजबूत करने के लिए था या छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए? जिस आंदोलन को उनकी आवाज बनना था, वह कुछ लोगों के दिखावे तक सीमित रह गया। छात्रों के नाम पर दुकान सजाई गई थी। इन चेहरों को देखकर सरकार को मौका मिल जाता है यह कहने का कि देखो, इनकी वजह से परीक्षा व्यवस्था का सच में शोर दब गया। प्रेस कांफ्रेंस में जो लड़का चार घंटा बैठ कर ज्ञान दे रहा था, वो लोग जो सरकार को हिलाने की बात कर रहे थे, चार घंटा धूप में खड़े नहीं हो पाए। सच कहें तो जंतर मंतर पर राजनीतिक कार्यकर्ता थे, कैमरे थे, पुलिस वाले थे, नारे थे, भाषण थे। सबके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ था। लेकिन वो लड़का जिसने सालों साल मेहनत करके NEET की तैयारी की थी, CBSE की तैयारी कर रहा है उसकी कहानी कहीं नहीं थी। वो लड़की जिसने जवानी टेस्ट सिरीज और किताबों में निकाल दी, उसकी आवाज नहीं थी। वो पिता जिसने कोचिंग फी भरने के लिए कर्जा लिया था, पेपर कैंसिल हो गया, अब कहां से पैसा लाएगा, उसकी बारे में कोई बात नहीं थी। वो मां जो दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि परीक्षा हो जाए, लड़का तैयार बैठा है। भगवान ईमानदारी से परीक्षा करा दो, लड़का निकल जाएगा। उसका दर्द नहीं था और ना वो बच्चा वहां दिख रहा था। क्या छात्र आंदोलन, छात्रों की समस्या, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यह सारे मसले जो थे, शिक्षा व्यवस्था में जो कुव्यवस्थाएं हैं, पेपर ईमानदारी से हो। यह सारे मसले गायब हो गए।

बहरहाल, सीजेपी के इस आंदोलन का नेतृत्व मिलने के बाद दिल्ली का जंतर मंतर रणक्षेत्र बन गया। सीजेपी द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान अचानक स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई, जब प्रदर्शनकारी संसद मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस की कड़ी घेराबंदी और वॉटर कैनन की गाड़ियों की तैनाती के बावजूद माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्राउंड रिपोर्टर्स के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोपहर में माहौल तब बदला

जब कुछ युवा कार्यकर्ताओं के समूह ने पुलिस द्वारा लगाए गए दूसरे स्तर के बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास किया। स्थिति को हाथ से निकलता देख दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं और सुरक्षाबलों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और जंतर-मंतर और आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बीच सपा नेता डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज समेत सभी सपा सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर की ओर निकल पड़ीं। सभी उनके हाथ में पोस्टर थे, जिन पर लिखा था 'नीट है या चिट है'। कई सांसदों के हाथ में 'पेपर लिक' वाले पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया।

डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक और छात्र आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर संवाद शुरू करने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। मार्च के दौरान डिंपल यादव ने कहा कि देश के युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने और संवाद करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक भी लगातार सरकार से बातचीत की अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। उनके मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों और युवाओं को हो रहा है, जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। छात्र बस निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर दिल्ली सड़क से संसद तक बवाल मचा। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर झड़प की देखने को मिली। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज करती दिखाई दे रही है। जंतर मंतर के इस वीडियो में युवक चिल्लाते हुए कहता है कि 'मारो मुझे मारो और मारो'। धारा 163 का उल्लंघन कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने में फिलहाल पुलिस ज्यादा सफल नहीं रही है। जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों को करने के लिए लाठियां भांजते

नजर आए। जंतर मंतर से निकले कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंच गए। इन्हें रोकने के लिए भी पुलिस ने आंसूगैस के गोले दागे।

छात्र आन्दोलन का दूसरा हिंसक प्रदर्शन जंतर मंतर के बाद बिहार की राजधानी पटना की सड़कों एवं अन्य जिलों में भी देखने को मिला। 22 जुलाई को 6 घंटे तक पटना की सड़कें युद्ध क्षेत्र बना रहा। इस हिंसक प्रदर्शन में छात्र आन्दोलन का अलग ही रूप देखने को मिला। गांधी मैदान से शुरू हुआ राजभवन मार्च दिनभर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना रहा। छात्रों की रणनीति और अचानक बढ़ते हुजूम के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया। हुआ यह कि पुलिस जैसे ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रही थी। उसे भीड़ उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। बैरिकेडिंग हटने के बाद प्रदर्शन में शामिल लोग एक साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे, जिसे पुलिस रोक नहीं पा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़कर पुलिस बल को लगभग छह घंटे तक छकाया। इस दौरान राजधानी का डाकबंगला चौराहा, जेपी गोलंबर, सीएम हाउस और बेली रोड अंडरपास युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए। सुबह करीब 10.30 बजे छात्रों ने गांधी मैदान के गेट नंबर 12 को तोड़ते हुए राजभवन के लिए अपना मार्च शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले 11 बजे जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। यहां पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बावजूद छात्र पीछे नहीं हटे और बैरिकेडिंग तोड़कर डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़ गए। डाकबंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने करीब एक घंटे तक सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाजी की। इसके बाद छात्र सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजभवन और सीएम हाउस की दिशा में निकल गए। मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के समीप पहुंचे प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें खदेड़-खदेड़ कर पीटा। इस दौरान कई छात्र विरोध जताते हुए सड़क पर लेट गए, जिन्हें पुलिस घसीटकर गाड़ियों में लादती दिखी। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वे दोबारा संगठित होकर डाकबंगला चौराहे पर जुट गए। प्रदर्शन के उग्र होने के साथ ही डाकबंगला और बेली रोड इलाके में जमकर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पटना आइजी की एस्कार्ट गाड़ी, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार की गाड़ी और कई थाना पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की। हमले में भागलपुर से भाजपा विधायक रोहित पांडे की गाड़ी को पलटने का प्रयास किया गया। उनके साथ मारपीट की गई, जिससे वे घायल हो गए। इसके अलावा भाजपा विधायक विनय बिहारी और पार्टी नेता अजय सिंह की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। पथराव की चपेट में आने से आइजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, एसडीएम कृतिका

मिश्रा, टाउन डीएसपी-2 कामाख्या नारायण प्रसाद, और गांधी मैदान थानाध्यक्ष समेत 17 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 20 से अधिक अन्य को चोटें आई हैं। पथराव और लाठीचार्ज में घायल 37 छात्र-छात्राओं को पुलिसकर्मियों ने उपचार के लिए पीएमसीएच, आइजीआइएमएस, एलएनजेपी और गार्डिनर रोड अस्पताल में भर्ती कराया। शाम लगभग पांच बजे पुलिस ने हड़ताली मोड़ और डाकबंगला के पास अंतिम बार लाठीचार्ज कर और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को पूरी तरह खदेड़ा। पटना आइजी जितेंद्र राणा के आदेश पर दर्जनों छात्रों को हिरासत में लेकर बसों से थाने भेजा गया है। बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अलग-अलग स्थानों पर लाठीचार्ज से लेकर हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। वही राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए 1975 के छात्र आंदोलन की याद फिर से ताजा हो गई है। क्या बिहार के युवा फिर से एक बड़े आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। बिहार के जहानाबाद, दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय तथा अन्य जिलों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों पर कथित तौर पथराव किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। अधिकारियों के अनुसार, जहानाबाद में

बड़ी संख्या में छात्रों ने कारगिल चौक से काको मोड़ तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी कथित तौर पर उग्र हो गए और पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों को तोड़ने का प्रयास किया। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कोटा किरण कुमार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के उग्र हो जाने के कारण पुलिस को स्थिति के अनुरूप 20 से 30 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। नगर थाना प्रभारी तथा कुछ अन्य पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। दरभंगा के लोहिया चौक पर प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के पथराव में सिटी एसपी और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि करीब एक दर्जन पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई राहगीर भी घायल हुए। घटना की पुष्टि करते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि प्रदर्शन के आयोजकों की पहचान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कुमार ने बताया कि पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। कटिहार में नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने जिलाधि

सिवान में छात्रों पर चला AK-47

कारी कार्यालय परिसर के सामने प्रदर्शन किया और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने संवाददाताओं से कहा कि हर व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही स्थिति उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी और कई छात्र घायल हो गए। मुंगेर और मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों से भी कथित नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में विरोध-प्रदर्शन की खबरें मिली हैं। इन जिलों में प्रदर्शन एक दिन पहले राज्य की राजधानी पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हुए, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पटना में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करने के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। इसके साथ ही देश भर में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बिहार का सिवान जिला चर्चा में रहा। 25 जुलाई को सिवान में प्रदर्शन के दौरान एके 47 राइफल का इस्तेमाल हुआ था। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एके 47 के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट सरकार बिहार को 'पुलिस स्टेट' बना रही है, वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था, 'दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में एके 47 । पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स के खिलाफ जानलेवा है।

वही दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हिंसक प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि आज लोकतंत्र के इतिहास में ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस की आंखों में भी शर्मिंदगी दिख रही थी। कुछ पुलिसकर्मी गुंडे बने हुए थे। कुछ पुलिसवाले बिना वर्दी के आए और बच्चों को मारा। बच्चों को करंट दिया। जहां नियम होता है कि आपको पैरों पर मारना है, वहां बच्चों के सीने पर मारा है, ये आघात भारत माता के सीने पर किया है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को हटाएं, सरकार जिम्मेदारी ले। इतनी अहंकारी कठोर और निर्दयी सरकार शायद ही देश के इतिहास ने देखी हो। सपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रहीं लोकसभा सांसद डिंपल यादव एवं अन्य सपा सांसदों को पुलिस द्वारा डिटेन किया जाना, साथ ही छात्रों पर

राहुल गांधी

तेजस्वी यादव

डिंपल यादव

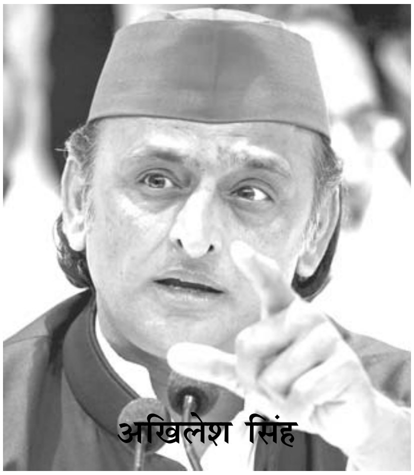

अखिलेश सिंह

लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया, जबकि बाहर बच्चों को पीटा जा रहा है। यह कैसी सरकार है? आप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते। अगर NEET परीक्षा हुई और उसमें गड़बड़ी हुई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि आप 'विश्वगुरु' बनना चाहते हैं; आप दावा करते हैं कि दुनिया 'अमृत काल' में है, फिर भी आप अपने मंत्रियों को नहीं हटा सकते। आपने नौकरियां या रोजगार नहीं दिया। अगर नौकरियां दी गई होतीं, तो क्या बच्चे सड़कों पर उतरते? अभी मुख्य सवाल यह है कि NEET छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और यहां विरोध कर रहे छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। जब लोग विरोध प्रदर्शन करते थे, तो अंग्रेज भी उनकी बात सुनते थे। इसीलिए आज पूरी दुनिया में गांधी का सम्मान किया जाता है। उन्होंने विरोध का रास्ता दिखाया। जिस तरह से वे प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार को अंत में 'सम्मानजनक विदाई' न मिल जाए।

वही इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा नीति को लेकर गंभीर सवाल हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने के बजाय छात्रों पर बल प्रयोग कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, 'हम सभी शिक्षा नीति पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसमें कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार बातचीत करने के बजाय छात्रों पर आंसू गैस छोड़ रही है और उनकी पिटाई कर रही है। आखिर क्यों? ये हमारे ही बच्चे हैं।'

ज्ञात हो कि दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च की शुरुआत परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग से हुई थी। लेकिन समय के साथ यह प्रदर्शन केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन में शामिल कई छात्र इसे सरकारी जवाबदेही, संस्थागत भरोसे और युवाओं के भविष्य से जुड़े व्यापक सवालों से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नागरिकता कानून, किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन जैसे कई बड़े आंदोलन हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा छात्र आंदोलन को अलग क्यों माना जा रहा है? मुद्दा केवल शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं रहा। शुरुआत में प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय करने और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन अब प्रदर्शन में शामिल कई छात्र सरकार की समग्र शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि जब किसी मंत्री का सार्वजनिक रूप से बचाव किया जाता है, तो उस विभाग से जुड़े विवाद केवल मंत्रालय तक सीमित नहीं रहते बल्कि सरकार की व्यापक राजनीतिक जवाबदेही का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं सरकार का कहना रहा है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं और अनियमितताओं पर कार्रवाई की जा रही है। इस आंदोलन की एक खास बात यह भी है कि इसका संचालन किसी एक राजनीतिक दल, छात्र संगठन या प्रमुख चेहरे तक सीमित दिखाई नहीं देता। सोशल मीडिया के जरिए अलग-अलग शहरों के छात्र एक-दूसरे से जुड़े और विरोध प्रदर्शनों का समन्वय करते दिखे। ऐसे विकेंद्रीकृत आंदोलनों को पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से अलग माना जाता है क्योंकि इनमें निर्णय लेने का केंद्र स्पष्ट नहीं होता। वही प्रदर्शन का मुख्य फोकस परीक्षा

प्रियंका गांधी

प्रणाली, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर रहा है। ये ऐसे विषय हैं जिनका असर अलग-अलग राज्यों, जातियों और सामाजिक समूहों के युवाओं पर पड़ता है। इसी वजह से आंदोलन को किसी एक पहचान आधारित राजनीति के दायरे में रखना अपेक्षाकृत कठिन माना जा रहा है। हालांकि सरकार समर्थक कुछ समूहों ने आंदोलन की मंशा और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सवाल भी उठाए हैं। प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का कहना है कि उन्हें अदालतों, जांच एजेंसियों और अन्य संस्थागत प्रक्रियाओं से अपेक्षित राहत नहीं मिली। इसी वजह से उन्होंने सार्वजनिक विरोध को अपनी बात रखने का प्रभावी माध्यम माना। हालांकि न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं समय-समय पर ऐसे मामलों में सुनवाई और हस्तक्षेप करती रही हैं। इसलिए यह धारणा सभी पक्षों द्वारा समान रूप से स्वीकार नहीं की जाती। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग यह रही है कि बार-बार सामने आने वाले पेपर लीक और भर्ती संबंधी विवादों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए। वही विश्लेषकों का कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और युवाओं के भविष्य से जुड़े व्यापक सवाल उठा रहा है। सरकार की ओर से अब तक प्रशासनिक कदम, जांच और कुछ मामलों में कार्रवाई की जानकारी दी गई है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी इसे अपर्याप्त बताते हुए

लगातार विरोध जारी रखे हुए हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार सरकार के सामने चुनौती केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की नहीं, बल्कि युवाओं के बीच भरोसा कायम रखने की भी है। आने वाले समय में सरकार बातचीत, नीति सुधार या प्रशासनिक कार्रवाई-किस रास्ते को प्राथमिकता देती है, इस पर भी नजर रहेगी। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद इसका सामाजिक और पीढ़ीगत स्वरूप है। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र इसमें शामिल हैं जो पहली बार किसी सार्वजनिक आंदोलन का हिस्सा बने हैं। दुनिया के कई देशों में हाल के वर्षों में छात्रों और युवाओं ने जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है। भारत में भी कुछ विश्लेषक इस प्रदर्शन को उसी व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति के संदर्भ में देख रहे हैं, हालांकि इसकी दिशा और राजनीतिक प्रभाव का आंकलन अभी जल्दबाजी होगा। दिल्ली का यह छात्र आंदोलन फिलहाल केवल परीक्षा प्रणाली के विरोध तक सीमित नहीं दिखाई देता। यह युवाओं की आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और सरकारी जवाबदेही से जुड़े व्यापक प्रश्नों को सामने ला रहा है। हालांकि यह कहना अभी जल्द होगा कि इसका दीर्घकालिक राजनीतिक असर क्या होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने युवाओं की चिंताओं और सार्वजनिक संस्थानों में भरोसे के सवाल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। आने वाले समय में सरकार की प्रतिक्रिया और आंदोलन की दिशा, दोनों ही इसके महत्व को तय करेंगे।

गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे धरने पर बैठे। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सभी ने खरगे के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी से बात की। कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास दोपहर करीब साढ़े 3 बजे से धरने पर बैठे। कांग्रेस का यह प्रदर्शन बेहद सीक्रेट रहा। सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब ये लोग 100 मीटर दूर थे तब मीडिया को जानकारी दी गई। इधर, कांग्रेस के प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद वे गृह मंत्री अमित शाह के पास गए। शाह से बातचीत के बाद फिर धरनास्थल पहुंचे हैं। हिरासत में लिए जाने पर पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह बीजेपी का आतंकवाद है। वे छात्रों की बात नहीं सुनते। कांग्रेस प्रमुख खरगे ने कहा कि जंतर-मंतर पर किए गए बल प्रयोग का सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारी एक सीधी-सी मांग है। हमारे विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में यह मांग उठाई है। मांग यह है कि गृह मंत्री संसद में इस पर स्पष्टीकरण दें और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि वे इस बात पर बयान दें कि किस तरह लोकतंत्र और हमारे संविधान की हत्या की जा रही है और छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम 45 दिनों से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए युवाओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री' हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कथित रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने में भी असफल रही है। वही राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में 152 पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिनसे करीब 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी कीमत मेहनत करने वाले छात्रों को चुकानी पड़ी है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, जबकि अपने अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने वाले छात्रों को विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जब छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए तो उन्हें जवाब के तौर पर 'लाठी और हिरासत' मिली। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार केवल युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने में असफल नहीं हो रही, बल्कि उन पर दबाव भी बना रही है। उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। हालांकि, केंद्र सरकार पहले भी पेपर लीक और परीक्षा सुधारों को लेकर कई कदम उठाने का दावा कर चुकी है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। वही पेपर लीक विवाद पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ कायरता और क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से पुलिस कार्रवाई रोकने और संवाद शुरू करने की अपील की। सोनिया गांधी ने समाचार पत्र हिंदू में लिखे अपने आलेख में कहा कि देश भर में परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में आ रही

गिरावट के खिलाफ छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें बहुत स्पष्ट हैं, सरकार अपनी जवाबदेही तय करे और शिक्षा में सुधार लाए। 20 जुलाई 2026 का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दबाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का हिंसक इस्तेमाल किया। इस हिंसा में कई निर्दोष छात्र घायल हुए। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पैलेट के इस्तेमाल को जरूर उनकी मंजूरी मिली होगी। उन्होंने कहा इस सरकार में हिंसा की यह पहली घटना नहीं है। 2020 में सीएए-एनआरसी प्रदर्शनों के दौरान भी पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी थी और महिला पहलवानों के साथ भी बदसलूकी की गई थी।

बहरहाल, आधी रात को देश के प्रधानमंत्री पहली बार शायद अपने फोन से वीडियो बना रहे थे। प्रधानमंत्री मित्रों कहकर सम्बोधित करते है, वो जेन जी को फ्रेंस कह कर सम्बोधित कर रहे थे। फ्रेंस इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में वीडियो बना रहे थे। ताकि रील पर वायरल हो, शॉर्ट्स में वायरल हो, लोग जानें। उन्होंने फास्ट कोर्ट का ऐलान किया, शिक्षा की सेक्रटरी को हटा दिया। जो बच्चे इस दुनिया में नहीं, उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया और यह भी कहा कि हम इसको लेकर बहुत सीरियस है। और ये लड़ाई आगे चलेगी बहुत कड़ी सजा देंगे। अब जनता के मन में सवाल है। ये भीड़ को देख कर मोदी जी का डर है या मोदी जी को फाइनली रिलाइज हुआ कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जेनविन है। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी कि क्या सोनम वांगचुक के जाने से धरना खत्म होगा या ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक से आगे निकल चुका है। क्योंकि सोनम के आने के पहले से यह प्रोटेस्ट था। ये अलग बात है की मीम से आंदोलन बने। काकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक ने ही बड़ा किया।

आधी रात इंस्ट्राग्राम पर लाइव हुए पीएम मोदी

सोनम वांगचुक के आने से क्रेडिबिलिटी बढ़ी। लेकिन फिर भी अगर सोनम के आये बगैर ये शुरू हो सकता है तो क्या सोनम के जाने के बाद ये हट जाएगा और आखिरी सवाल की इस देश में आज तक कोई भी आंदोलन किसी मंत्री कुर्सी हिला नहीं पाया है। क्या इतिहास इस बार भी खुद को दोहरा रहा है। सारी मांगे मान ली गयी। ये वो सवाल हैं जो जंतर मंतर से लेकर देश के सारे घरों में फिलहाल चल रहा है। सरकार ने जब कहा की दोपहर में छात्रों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद अब बच्चों की जीत हो गयी तो ये सवाल की क्या ये आंदोलन का दी एंड है या फिर इंटरवेल भी नहीं हुआ। आधी रात को प्रधानमंत्री का आना बताता है कि इस मामले को लेकर सरकार परेशान हुई है। इसको लेकर वो सीरियस है वो इसे खत्म करना चाहती है। सोनम वांचुक मान जाते हैं हैप्पी तस्वीरें आती है, एक मेसेजिंग दी जा रही है। सरकार की तरफ से सरकार के चाहने वालों की तरफ से बच्चों की मांग हमने मान ली है। सोनम वांगचुक को बना लिया है। अब जो बचे हैं वो वो एलिमेंट है जो

हिंसा करवाना चाहते हैं। सोनम वांचो खुद ट्वीट कर रहे है की पीसफुल होना चाहिए इसमें कुछ गए है। सलमान खान से लेकर बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे अपील कर रहे हैं की प्रोटेस्ट को एंड कर दिया जाए और अब बच्चे पढ़ाई लिखाई करे घर लौटे। सोना वांगचुक भी एंड करे। और यही ऐसे सवालों के बीच में वो सवाल आ रहा है की क्या इस प्रोटेस्ट का दी एंड हो गया?

क्या सोनम बेवफा निकले या समझदार? वे नीट आंदोलन को लेकर जब सोनम वांगचुक ने 26वें दिन सरकार के मंत्रियों से मिलकर अपने अनशन को खत्म किया तो ये कड़वा सवाल देश के बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि क्या सोनम वांगचुक ने छात्रों के साथ गद्दारी कर दी, बिक गए? सोनम वांगचुक को जो लोग गालियां दे रहे थे आज वो कह रहे है कि क्या महान व्यक्ति है। असली लड़ाई तो यही लड़ रहे थे, चेहरा थे। कह रहे है की बच्चों का हित होगा और जो सोनम वांगचुक के नाम पर दुनिया भर में लोगों को बुला रहे थे वो दबी जुबान में कह रहे की सोनम सर आपने क्या बेवफाई कर दी। आपने सरकार से डील कर ली है। जो आदमी 26 दिन से देश के लिए भूखा बैठा था, जिसके लिए देश दुआएं कर रहा था, अब उसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे की भाई साहब डील किस से पूछ कर ली, क्या बेवफाई कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोज शब्द देते हैं। एक आदमी कॉकरोज के नाम से मीम पेज बनाता है, फॉर्म भरवाता है, इंडिया आता है। 4, 507 सौ लोग नजर आते हैं। 8 दिन बाद सोनम जैसा चेहरा आता है। अचानक एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। देश दुनिया में सबकी निगाहें जाती है, भीड़ बढ़ने जा लगती है। हालत ये होती है की जनता सड़क से संसद जाने को तैयार हो जाती है, फिर आदमी को ठग लिया आता है। लेकिन 26 दिन बाद यही आदमी अनशन तोड़ता है और ये सवाल उठता है, क्या सोनम बेवफा है? और ये सवाल जंतर मंतर पर भी उठ रहा है। यह सवाल देश भर में भी उठ रहा है। सवाल नंबर एक जो देश के मन में आ रहा है। क्या सोनम ने आंदोलन को आधे रास्ते पर छोड़ दिया, जिस मांग के लिए हजारों बच्चे, धूप में बैठे लाठी खाये, पीटे बरसात में नहाये खाली, पेट आए, देश दुनिया से ट्रैवल कर के यहाँ बैठे रहे, क्या उनकी मांग के बगैर समझौता कर लिया गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान को न हटाना सरकार की जीत है, कॉकरोज जनता पार्टी की हार या दूसरा सवाल कहानी उलटी है। सोनम वांगचुक वहाँ बैठे सभी ज्यादा लोगो ऐसे समझदार निकले और सरकार ऐसे छात्रों के हित की सारी बातें बना। ये सुनिश्चित किया की जैसे लद्दाख में 6 लोगों के मरने के

बाद एन.एस. लाकर उनको जेल में ठूंस दिया गया था। किसी बच्चे को जेल में नहीं डाला जाएगा। एक बच्चे पर एफआईआर नहीं होगा, उसका करियर खराब नहीं होगा। जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें मुआवजा मिलेगा, शिक्षा, सचिव का इस्तीफा भी करवा दिया। यह भी कह दिया। संसद में मामला उठेगा और यहाँ तक सुनिश्चित किया कि भविष्य में अगर पेपर लीक होता है तो फास्ट ट्रैक में जाएगा। तो क्या सोनम ने आंदोलन को बचा लिया? इन दो सवालों के बीच फिलहाल देश बंटा हुआ है। एक सवाल और भी है कि इस देश में आज तक एक भी आंदोलन नहीं हुआ है, जो ऐसे हुआ, क्या सोनम यह समझ रहे थे? क्या 2011 में अन्ना आंदोलन में अन्ना, हजारे और केजरीवाल में जो हुआ था, वही कहानी सोनम वांगचुक और दीपक में हुई है। सवाल है कि सोनम पर बेवफाई का इलजाम क्यों है। तो सोनम पर बेवफाई का एग्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि सीजेपी का प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक के आने के 8 दिन पहले शुरू हुआ था। 20 जून से कुछ बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर बैठे थे, लाठी खाए, बरसात में रहे। भूखे पेट भी रहे होंगे। कई सारे बच्चे थे। उन बच्चों की मांग को लेकर जिनका पेपर लीक हुआ था, कई बच्चों की जान भी गई। अब ये मांग जिद्द नहीं थी, दर्द था। लेकिन इसको गंभीरता से लिया नहीं जा रहा था। फिर सोनम वांगचुक का और इस आंदोलन को चेहरा मिल गया। सारे कलाकार, अभिनेता, नेता सब इस मंच पर जाने लगे। ये प्रोटेस बड़ा हो गया। नॉन सीरिज से काफी सीरियस हो गया। लेकिन अब जब अनशन टूटा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। क्योंकि पहली शर्त थी बच्चों पर एफआईआर न हो, दूसरी शर्त थी मुआवजा दिया जाए, तीसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, संसद में चर्चा हो और आखिरी हो सके तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसे लेकर बच्चा सोच रहा है की क्या हमारी लड़ाई का सौदा हुआ और हमें पता नहीं चला और यहीं से सोनम की बेवफाई का सवाल और हम ये स्पष्ट कर दे की जो ये सोच रहे हैं वो गद्दार नहीं है, दुखी होना गद्दार होने में फर्क होता है। सोनम को डर लग रहा है कि आंदोलन में हिंसक लोग आ रहे हैं और आंदोलन अब धीरे-धीरे सी जे.पी. वालों से आगे निकल रहा है। एक बिना चेहरे की जनता तैयार हो रही है, ऐसा हो सकता है कि कल को कोई घटना हो जाए और जैसे लद्दाख में कुछ नहीं मिला, यहाँ भी न मिले। क्योंकि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो 26 दिन की तपस्या मिट्टी मिल जाती है और सरकार को बैठे बिठाए, बहाना जैसे लद्दाख में मिला, तो जो लोग बेवफाई का इल्जाम लगा रहे हैं क्या अगर सोनम अड़े रहते तो सोनम तो खुद शहीद होते, आप मोमबती लगाते और हिंसा होने के बाद कुछ लोग जेल जाते। क्या वो सही था या बिना इस्तीफे के छात्रों पर कोई एफआईआर न हो ताकि किसी छात्र का भविष्य खराब न हो। वो जो पुलिस को पीटे वो भी बचे रह गए। दूसरा जो शहीद पहले हो चुके हैं उनको पैसा मिल गया। तीसरा फास्ट ट्रैक बन गया की अब पेपर लीक का मामला उतना लंबा नहीं जाएगा और चौथा नरेंद्र मोदी सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ की किसी आंदोलन को इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया। सरकार की तरफ से कोशिश की गई। क्योंकि इससे पहले सरकार की टैक्टिक होती थी कि डिले करो, डिले करते जाओ। अब सवाल फिर वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात को झुका कर ये सारी मांगे मनवा लेना, समझदारी है या ये सोनम की बेवफाई है?

सोनम वांगचुक

बहरहाल, सरकार ने सारी शर्तें मानते हुए आखिर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तिफा ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। धर्मेंद्र प्रधान के स्थान पर अब प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रहलाद जोशी अभी अपने पहले से संभाल रहे विभागों के साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी देखेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है। प्रहलाद जोशी लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इससे पहले आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। प्रधान ने कहा कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। प्रधान ने कहा कि युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा। अब सवाल है कि क्या 12 सालों की नरेंद्र मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का पहला इस्तीफा हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? भारत के लोकतंत्र में ऐसी जवाबदेही क्या ये सुखद लग रही है? बात उन बच्चों की करें तो उनके पास क्या था, जो अपने मुद्दों को लेकर लगातार प्रोटेस कर रहे थे। जिनकी पीठ को कितनी बार अलग अलग राज्यों की पुलिस ने पायदान बना लिया था। उनकी लड़ाई शुरू हुई। जंतर मंतर पर उसे मुकाम मिला। लेकिन सोच कर देखिये की उनके पास क्या था। न नेता, न पार्टी, न पैसा, न कोई टी वी एंकर जो सुबह शाम प्राइम टाइम में के लिए चीख चिल्लाए और सवाल उठाए। इनके पास बस एकता थी, वो एकता जो तमाम सेलिब्रिटीज को झुका ले गई। मजबूर कर दिया

की उनके मुद्दे पर वो कमेंट करे और उनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो सरकार जिसके सामने 13 महीनों तक किसान बैठे रहे लेकिन कुर्सी नहीं हिला पाए। जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां बैठी रही लेकिन इस्तीफा नहीं ले पाई। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ, मणिपुर महीनों तक चलता रहा लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ। क्योंकि हर कोई यह मान चुका था कि मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, यही इनकी पॉलिसी है, वो बात नहीं करते। आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और कहना होगा की ये उन बच्चों की बड़ी जीत है। आज सियासत में 12 साल बाद एक शब्द लौटा है जवाबदेही और ये उसकी भी जीत है। इस देश में जवाबदेही के नए दौर की शुरुआत हुई। 12 साल में पहला इस्तीफा, ये किसी चैनल की वजह से नहीं हुआ है, किसी रिपोर्टर की वजह से नहीं हुआ है, यह उन लाखों करोड़ों बच्चों की वजह से हुआ है जो 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे और जो हफ्तों ऐसी सड़कों पर सोए है। हमने भी हमारा काम किया, सवाल पूछा।

गौरतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी को डिकोड करेंगे क्या उन्होंने कहा है क्या छिपाया है, मोदी सरकार ने क्यों ये इस्तीफा लिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब पड़ोस के दो देशों से भी जुड़ा हुआ है। वही इस इस्तीफे का क्या फायदा देश की डेमोक्रेसी को होगा? क्या नुकसान बीजेपी को होगा? क्योंकि हर सिक्के का 2 पहलु होता है। अब शुरुआत करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को हम डिकोड करें उस चिट्ठी के अन्दर घुसे उससे पहले एक इंटरस्टिंग बात आपको बताते हैं जिस धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पेपर लीक ने ली है। क्या आप जानते है की इस इंसान की कहानी पॉलिटिक्स आज से 30 साल पहले एक पेपर लीक से शुरू हुई थी। 1997 में ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी और जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री थे, तब पेपर लीक हुआ था।

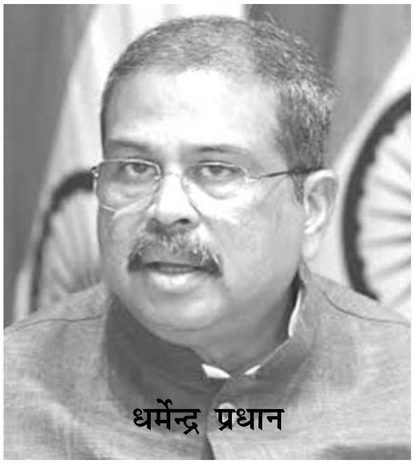

धर्मेन्द्र प्रधान

भुवनेश्वर में सरकारी दफ्तर के सामने 1500 बच्चे आकर बैठ गए और उस भीड़ में ये भी थे एबीवीपी से। लाठियां खूब पड़े थे और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही है। लेकिन एक सवाल जो लड़का पेपर लीग के खिलाफ लाठी खाकर मंत्री बना, उसी के रहते उसी उम्र में जिस उम्र में उसे लाठी पड़ी थी, बच्चों को लाठी को मतलब, वो भी वही मांग रहे थे, ये भी वही मांग रहे थे। वो 1997 में बैठे थे या आज बैठे थे। ये थोड़ी कड़वी बात है। लेकिन खैर इस बात को धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए था और सोचा होता तो शायद इस्तीफा न देना पड़ता। लेकिन अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा जो हुआ है वो क्या लिख कर हुआ है। वो समझना जरूरी है। अब धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी पढ़कर पहली बात यह लगती है कि ये कागज गलती से नहीं अपनी तारीफ से शुरू होता है। यानि धर्मेंद्र प्रधान जो प्रोटेस्ट में बच्चे उन्हें गलतियां गिना रहे थे, उन गलतियों को नहीं मानते। वो अपनी तारीफ ऐसी शुरुआत करते हैं। वो अपने 40 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को बताते हैं, वो पेपर लीक की बात करवाई का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि देखिये परीक्षा दोबारा कराई गई, 20 लाख बच्चे बैठे नतीजे आये, गरीब घर के बच्चे पास हुए यानि चिट्ठी शुरू में तो पूरी कामयाबी से। अब यहाँ सोचने वाली बात ये की अगर सब कुछ धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छा किया जैसा चिट्ठी में लिखा है तो फिर इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात ये लगती है कि इस चिट्ठी में जिम्मेदारी नहीं ली गई है, जिम्मेदारी किसी और के सिर डाली गई है। चिट्ठी में इशारा हुआ है की जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे कुछ लोगों ने बच्चों को बहकाया। अब ये इशारा सीजीपी के लोगो पर भी हो सकता है। ये इशारा अरविन्द केजरीवाल, अखिलेश यादव या फिर राहुल गाँधी पर भी हो सकता है तो धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती नहीं मान रहे है, किसी तीसरे पर उँगली उठा रहे है, नाम नहीं लिखा है लेकिन इशारा किया है। इस्तीफा देते वक्त जो सबसे बड़ी बात है, पूरे कागज में कहीं भी उन्होंने एपोलोजी का जिक्र नहीं किया है। माफी कहीं नहीं मांगी है। जिस देश के 22 लाख बच्चों का साल हिल गया और पहली बार नहीं, दूसरी बार था। बीते कई सालो में तो कई पेपर लिक हुए हैं, उन्होंने एक सौरी नहीं कहा। तो चिट्ठी पढ़कर यही लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ये कहना चाह रहे हैं की मैंने सब कुछ ठीक किया। यह प्रोटेस्ट आया, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, दूसरे कुछ प्लान कर रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो इसे अगर आप कंक्लूड करे तो ये इस्तीफा नहीं है, ये इस्तीफे की शक्ल में लिखी गई सफाई है और एक बात आपको और याद दिलाते है जो कोई नहीं बताएगा। जब ये मामला शुरू हुआ था तब इन्ही शिक्षा मंत्री ने कैमरे के सामने इस बात को कबूला था की पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। बाद में कहा रक्षक भक्षक बन गए और आज उसी मामले में कुर्सी छोड़ कर जा रहे है।

अब धर्मेन्द्र प्रधान को आत्म मंथन

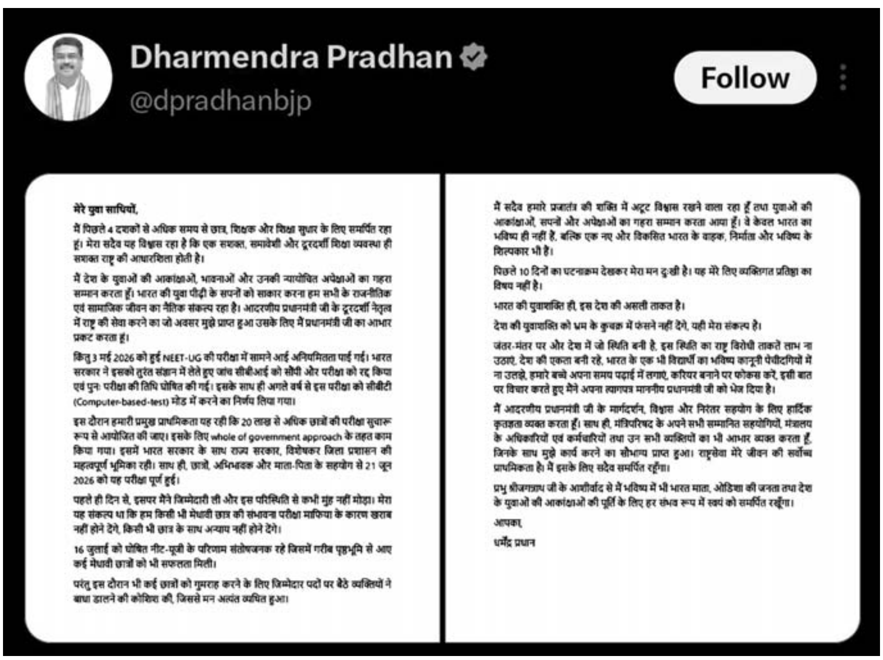

Dharmendra Pradhan
@dpradhanbjp
Follow

मेरे युवा साथियों,

मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।

मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

किंतु 3 मई 2026 को हुई NEET-UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी (Computer-based-test) मोड में करने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए whole of government approach के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही, छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई।

पहले ही दिन से, इसपर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली।

परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ।

मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं हैं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं।

पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।

भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है।

देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है।

जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही, मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा।

प्रभु श्रीजगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूँगा।

आपका,

धर्मेंद्र प्रधान

करना चाहिए की कौन सा वाला सच था। अगर कुछ दिन वाला सच था तो आज इस्तीफा किस बात का और अगर आज वाला सच है तो उस दिन देश से क्या कहा गया था। खैर ये धर्मेन्द्र प्रधान की कहानी है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे बढ़ कर बात करते हैं। मोदी सरकार का यह पहला इस्तीफा है और इसलिए सवाल उठ रहा है की ये इस्तीफा क्यों हुआ? क्या सरकार डरी? अब इसका जवाब समझना है। तो आपको हिंदुस्तान के पड़ोस के जो देश हैं उनमें बीते कुछ सालो में हुए घटनाओं को देखना पड़ेगा। क्यूंकि साल 2022 में श्रीलंका के नौजवान सड़क पर उतरे थे और राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा था। 2024 में बंग्लादेश में जो कुछ हुआ था, उसकी शुरुआत भी सरकारी नौकरी के कोटे से हुई थी। यानि वही चीज, जो यहाँ है। परीक्षा और बच्चों के भविष्य और बंग्लादेश में यही चीज आगे बढ़ गयी थी। पंद्रह साल से जमी शेख हसीना को सरकार छोड़नी पड़ी थी। पिछले साल नेपाल में भी जेन जी के प्रदर्शन ने प्रधान मंत्री कुर्सी ली थी, तो तीन देशों में सेम कहानी जा चुकी थी। वहाँ एक बात और भी कॉमन थी कि वहाँ कोई लीडर नहीं था और यही चीज हर सरकार को डराती है। लीडर हो तो सरकार के पास तीन रास्ते होते है- या तो उसे खरीद लो या लीडर कोई फंसा दो या बदनाम कर लो। लेकिन अगर लीडर नहीं होता है तो फिर तीनों बंद हो जाते हैं। आप किसे खरीदोगे, किसे अन्दर करोगे, किस पर विदेशी पैसे का ठप्पा लगाओगे। जंतर मंतर पर सरकार को यही दिक्कत है, जंतर मंतर पर अभिषेक दहिया या एक्स वाई जो भी थे। यह ना भी रहे तो भी प्रोटेस चलता और आपने देखा सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी प्रोटेस रुका नहीं। अब ये तो पड़ोस की बात थी, घर के अन्दर की बात करते है। असली वजह केवल विदेश में नहीं थी, दिल्ली में भी बैठी थी। पहली वजह ये कि इस बार ठप्पा लगाने के लिए कोई गिरबान नहीं मिला। किसान

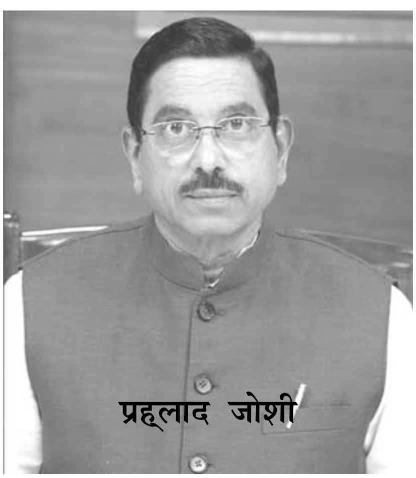
प्रह्लाद जोशी

को कह सकते थे की एक राज्य के हैं, वहाँ पर खालिस्तान वाला एंगल मिल गया था, पहलवान वे कह सकते हैं, गिनती के हैं। बच्चों को आप क्या कहेंगे। ये हर राज्य में है, हर जाति में है, हर पार्टी के वोटर में है। आई टी सेल चलाने वालों के घर में भी बच्चा तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बीजेपी के लिए भी आने वाले समय का वोटर था। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, या तो उसने 12 बार वोट दिया है, 2 बार, 1 बार वोट दिया होगा या अगली बार, ऐसी पहली बार वोट देगा और पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। इस बार यह परसेप्शन बन गया था की मोदी साहब सुनते नहीं है, मोदी साहब इस्तीफा नहीं लेते है। उनको लेकर बार बार बताया जा रहा था की डेमोक्रेसी में वो तानाशाह है, तानाशाही करते है, जिसको मन करता है, दबा देते है, लाठी चला देते हैं, संवाद नहीं करते हैं और अगर नोटिस किया हो तो मोदी जी ने ये सारे परसेप्शन तोड़ने की कोशिश की है, संवाद भी किया, सारी बात भी मानी और इस्तीफा भी दिलवाया। भारत पूरी तरह से हमारे पड़ोस के देशों की तरह नहीं रहा है। जैसे बंग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उन तीनों के जो हेड ऑफ स्टेट थे, उनसे मोदी जी थोड़े ज्यादा स्मार्ट है, उन्हें झुकना कब है, कब संभलना है, कब करना है। ये शायद बेहतर समझ में और इंस्टाग्राम वाला मूव ऐक्चवली बहुत शानदार था। जिस इंस्टाग्राम पर लोग पानी पी पी कर गाली दे रहे थे, वही पर उनको लेकर फनी फनी मीम्स बनाए जा रहे है।

अब सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसका फायदा किसे होगा? तो बता दें कि सबसे बड़ा फायदा हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को हुआ है और यह मैं इसलिए कहा जा रहा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से 12 साल बाद हिन्दुस्तान में एक शब्द की वापसी हुई है, जिसका नाम है जवाबदेही। भारत की डेमोक्रेसी में 12 सालो में हम ये मान चुके थे कि कुर्सी अलग चीज है, जिम्मेदारी अलग चीज है। आप याद कीजिये हिंदुस्तान में ट्रेन पलटी, पेपर लिक हुआ, पुल गिरा, जवाब हमेशा किसी अफसर पर, किसी एजेंसी पर। मणिपुर जलने से लेकर लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ने तक, बड़ी बड़ी घटनाओं में भी मंत्रियों से इस्तीफे नहीं लिए गए। आज पहली बार जवाब उस आदमी तक पहुँचा जो फैसला लेने वाली कुर्सी पर बैठा था और इसलिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दिन है। कुर्सी वाले को भी यह याद रहे की उसका मकान नहीं है, किरायदार हैं। जब तक तरीके से काम होगा तब तक कुर्सी है। दूसरा फायदा यह हुआ कि समाज को भी पता चल गया की हर बार नेता के सहारे जंग नहीं जीती जाती। अगर आपके पास मुद्दा है, आप संगठित है तो बिना पार्टी, बिना झंडा, बिना चन्दा, बिना स्टेज भी आप मजबूत से मजबूत सरकार को झुका सकते हैं और इस बार क्योंकि सड़क पर बच्चा बैठा था तो बच्चे ने जिद करके ये काम करवा लिया। ये बहुत बड़ी चीज है। ये अलग-अलग संगठनों को जिनके साथ नाइंसाफी होती है, भविष्य में उन्हें बहुत ताकत देगा। अब वो बात जो शायद कोई नहीं बोलेगा। अब इस इस्तीफे का फायदा सरकार को भी हुआ है। लेकिन सरकार के फायदे पर जाए उससे पहले समझते हैं। सरकार ने क्या किया, तो बता दें पेपर लिक पर सख्त कानून का मसौदा नई कैबिनेट से पास हुआ, जिसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक के जुर्माने की बात कही गयी, फास्ट्रेक कोर्ट का एलान किया गया, वांगचुक को भरोसा दिया गया।

अब सरकार को इससे क्या फायदा होगा? तो बता दें कि आंदोलन का एक बड़ा सिरा आज से सरकार के हाथ में चला गया। क्योंकि आंदोलन की एक बड़ी खतरनाक बात होती है की जब एक बार वो वायरल हो जाता

दतिया में कांग्रेस की जीत

बांकीपुर में जनसुराज की जीत

है तो फिर वो हर दिन एक नए शहर, एक नए गाँव और लाखों नए लोगों को जोड़ता है और यह हो रहा था। बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वो सीजेपी जिसको मजाक में शुरुआत में लिया गया था, वो अगर कल को प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगने लगती तो! ज्ञात हो कि कई प्रोटेस्ट में लोग खुद को आग लगा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है। जिस इंटेंसिटी के साथ पूरा देश इस प्रोटेस्ट में जुड़ा था, मोदी सरकार की हवा टाइट हो जाती है। वहाँ तक बात पहुँचे, उससे पहले सरकार ने रोक लिया और ये सरकार के लिए एडवांटेज हो गया। यह फायदा हुआ है। अब इसकी कीमत क्या सरकार ने दी? एक ऐसा मंत्री जो शायद इस वक्त सरकार की कमजोर कड़ी था। तो सरकार ने एक आदमी खोया, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो सरकार के खिलाफ जा रहा था, उसे फिलहाल काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। आगे क्या परसेप्शन बनता है, वो देखने वाली बात हो गया। दूसरा फाइनल सरकार का ये है की सरकार के पास आज से एक नई

लाइन आ गई है। सरकार आज से कह सकती है कि हम जनता की सुनते हैं। आगे आने वाले चुनावों में बार-बार लाइन रिपीट की जाएगी। मोदी जी कहेंगे कि देखिये जनता कुछ कहें तो हम मान लेते हैं, आपके लिए करते हैं। मतलब ये वाला परसेप्शन जो है की वो तानाशाह है, उसको बीजेपी तोड़ने की कोशिश करेगी। नौजवान वोटरों के सामने ये लाइन मजबूत हो सकती है, क्योंकि उन्हीं से संवाद है। अगली बार के वोटर वही है।

बहरहाल, देश में जो अस्थिरता जो छात्रों के आंदोलन से आयी उसमें जितने छात्र गलत हैं तो उतने ही सरकार द्वारा देर से लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री में विकसित भारत की बात करते हैं जिसके लिए पढ़े-लिखे लोगों का होना जरूरी है। जो छात्र देश के भविष्य निर्माता हैं, उन्हें शिक्षा में भ्रष्टाचार दिखाकर बाधित नहीं किया जा सकता। आज के ये जेन जी ने छात्रों की ताकत क्या होती है, सरकार को दिखाया। लाठियां खाई, हिंसक भी हुए और हिंसा में बेकसूर पुलिस वालों को भी गंभीर चोटे आयी किन्तु यह आन्दोलन सरकार की आंखों से पहले काले चश्मे को उतारना भी उतना ही जरूरी था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तिफे के बाद प्रह्लाद जोशी नये शिक्षा मंत्री बनाये गये हैं किन्तु उनके पर शिक्षा नीती में सुधार और शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार को खत्म करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही एक आंदोलन शिक्षा से ही जुड़ा यूजीसी का है, जो जारी है। उसे तत्काल खत्म करना होगा, वरना जो हालात अभी राजधानी दिल्ली समेत बिहार और अन्य प्रदेशों में देखने को मिला, पुनः दोहरा सकता है। फैसला सरकार के हांथों में है कि उन्हें क्या करना है। 12 साल की मोदी सरकार 15 साल तो पूरी कर लेगी पर क्या उसके बाद भाजपा का विरोध जिस प्रकार देश की जनता कर रही है, सत्ता में फिर से आने देगी! उदाहरण के लिए बांकीपुर और दतिया विधानसभा पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने हैं और यह भाजपा के लिए मंथन का विषय है।●

● **संजीव कुमार झा**

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर पर आंदोलन ने देश को एक ऐसा सबक सिखाया, जिसे भारत के 79 वर्षों के लोकतांत्रिक राजनीति के इतिहास में सियासी दल कभी नहीं सीख पाए। कह सकते हैं कि जंतर-मंतर ने भारतीय राजनीति के नए दौर की शुरुआत कर दी है। इसे आप सियासत के 'नए व्याकरण' के रूप में भी व्याख्यायित कर सकते हैं। क्या इसे एक अभूतपूर्व घटना नहीं मानी जाएगी कि एक ऐसा संगठन, जिसकी न सदस्यता है, न पंजीकरण, न घोषित नीतियां और न ही किसी राजनीतिक दल जैसी खास विशेषताएं... फिर भी महज 35 दिन के विरोध-प्रदर्शन के जरिये इसने न केवल दो कैबिनेट मंत्रियों को बातचीत के लिए मजबूर किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने पर मजबूर करते हुए सरकार से लिखित आश्वासन भी ले लिए!

यह तो हो गई पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के परिणाम की बात, लेकिन इसके बाद का अहम सवाल है कि नए शिक्षा मंत्री का कार्यकाल ही नहीं, बल्कि शिक्षा-परीक्षा की व्यवस्था क्या और कैसी होगी। दरअसल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को सौंपी है। शिक्षा मंत्रालय के साथ वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी गई है, जब देश में शिक्षा-व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा चल रही है। यानी, हकीकत यह है कि शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी इस वक्त किसी कांटों के ताज से कम नहीं है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रह्लाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहते हुए आभार जताया कि पीएम ने उन पर भरोसा जताते हुए जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए वह पीएम का धन्यवाद करते हैं और प्रधनमंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारियों को वह पूरी निष्ठा, लगन, विनम्रता और ईमानदारी के साथ निभाते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जोशी के ऐसे आश्वासन से लोगों को थोड़ा बल तो जरूर मिलता है, लेकिन क्या यह बल वाकई दीर्घजीवी साबित होगा?

दरअसल, यह सवाल इसलिए, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय देश के भविष्य से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ऐसे में नए शिक्षा मंत्री के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान को भी नई गति देने महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंतर-मंतर पर हुए इतने बड़े आंदोलन के बाद नए शिक्षा मंत्रालय के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा छात्रों को भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। शिक्षा मंत्री के सामने नई शिक्षा नीति को ठीक से लागू करने, आगे की सभी परीक्षाओं को ठीक से संपन्न करवाने, सीबीएसई और एनसीईआरटी में बदलाव करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन लूप होल्स को भी पता लगाना होगा, जहां से पेपर लीक की आशंका होती है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ देश के करोड़ों विद्यार्थियों की नजर भी अब इस बात पर टिकी रहेगी कि नए शिक्षा मंत्री इन चुनौतियों से किस प्रकार निपटते हैं और शिक्षा-व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को किस गति से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन, एक अहम आशंका यह भी कुलबुलाती है कि क्या चेहरे बदलने से नीयत और नीतियां बदल जाएंगी? क्योंकि, मंत्रालय में चेहरे बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीतियों की नीयत बदलना असली चुनौती है। हालांकि, प्रह्लाद जोशी के पास प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन उनके नए मंत्रालय की कसौटी फाइलों पर नहीं, बल्कि देश के 25 लाख छात्रों के चेहरों पर लौटने वाले भरोसे से तय होगी। अगर जल्द ही परीक्षा प्रणाली की सेंधमारी का पक्का इलाज नहीं किया गया, तो यह सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का संकट बन सकता है।

फिलहाल प्रह्लाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की परीक्षा-प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत करना है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चल रहे सुधारों को गति देना भी उनकी प्राथमिकता में है। इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा, डिजिटल शिक्षा का विस्तार और कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहने की उम्मीद है। संभवत: यही वजहें रही होंगी कि शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने के तत्काल बाद उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया। नीट जैसे बड़े विवादों के बाद छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा-प्रणाली से डगमगाया हुआ भरोसा वापस लाना जोशी के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। अब तक केंद्र और राज्य स्तर पर कई प्रशासनिक फेरबदल सभी ने देखे हैं, लेकिन देश के 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों और अभिभावकों का डगमगाया हुआ भरोसा बहाल करना शायद इस मंत्रालय के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना भी बेहद जरूरी है। पेपर लीक के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर पिछले कुछ समय में गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अब नंदन नीलेकणि की अगुवाई में गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू करना और पेपर-पेन मोड से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर सुरक्षित ट्रांजिशन सुनिश्चित करना शिक्षा मंत्रालय के लिए बड़ी चुनौती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आंतरिक तंत्र से 'काली भेड़ों' को बाहर निकाल कर एजेंसी को पूरी तरह पारदर्शी बनाना ही पहली और सबसे प्राथमिक परीक्षा है।

साथ ही देशभर के छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक सवालों का प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सामना करना भी बड़ी चुनौती है। जंतर-मंतर पर 35 से अधिक दिनों तक चले 'कॉकरोच जनता पार्टी' और अन्य छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब स्थिति को सामान्य करना जरूरी है। अब विपक्षी नेताओं और सीनियर वकीलों की सलाह के अनुसार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज सभी गैर-वाजिब मुकदमों को

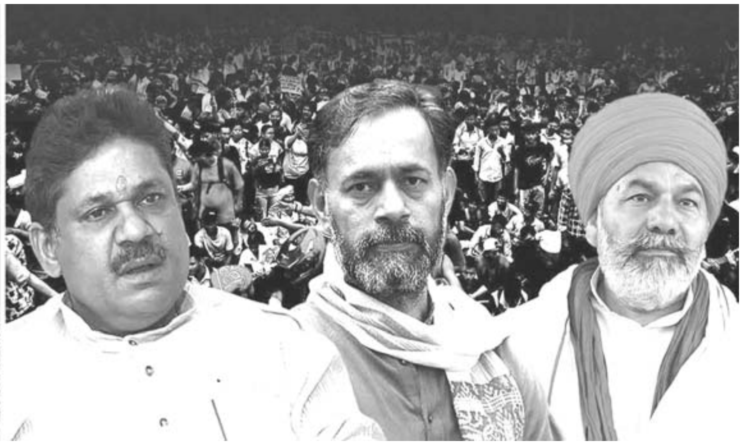

वापस लेने का समझौता हुआ है। इसके साथ ही, छात्र संगठनों द्वारा सौंपे गए '5-पॉइंट एजुकेशन रिफॉर्म चार्टर' पर ठोस और समयबद्ध रोडमैप पेश करना भी चैलेंज है। ऐसा देखा गया है कि केवल अधिकारियों पर गाज गिराने या परीक्षा रद्द करने से माफिया का दुस्साहस कम नहीं हो रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए एंटी-पेपर लीक कानून के तहत विशेष टास्क फोर्स और फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स का त्वरित गठन सुनिश्चित करना भी चुनौती है। दोषी पाए जाने जाने वाले अंतरराज्यीय नकल माफियाओं पर ऐसी नजीर पेश करना, जिससे भविष्य में कोई देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। खास बात यह भी है कि नीट और यूजीसी-नेट में हुई गड़बड़ियों के बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे कई राज्य अपनी राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं वापस शुरू करने और केंद्रीयकृत परीक्षा का विरोध करने लगे हैं। संघवाद के ढांचे को बचाते हुए एक चुनौती यह भी है कि अब सभी राज्य सरकारों को यह विश्वास दिलाना होगा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष, सुरक्षित और तकनीकी रूप से अभेद्य हैं। एक बड़ी समस्या यह भी है कि परीक्षा के दबाव और कोचिंग कल्चर के चलते कोटा और देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार मानसिक तनाव और छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। आज एक चुनौती राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सिलेबस और एक्सेसमेंट में ऐसे बदलाव लाना, जो 'रटने' और 'कोचिंग पर निर्भरता' को कम करना है। साथ ही, देश के शैक्षणिक संस्थानों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट और काउंसलिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाना है।

वैसे, इन चुनौतियों के बावजूद जहां तक बात कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार पांच बार सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल प्रह्लाद जोशी की है, तो उन्हें केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में गिना जाता है। वह वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले से ही संभाल रहे हैं। इससे पहले वह संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री जैसे महत्वपूर्ण

विभागों का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी पहचान एक अनुभवी संसदीय रणनीतिकार और संगठनात्मक क्षमता वाले नेता के रूप में रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को देने पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर जो बुनियादी सोच है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रही है। इसकी वजह यह है कि प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय देने के बाद से ही आम सवाल हवा में तैर रहे हैं कि क्या यही कॉकरोच जनता पार्टी की जीत है कि एक संघी के बदले दूसरे संघी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया!

लेकिन, हमें याद रखना होगा कि यह आलोचना और तर्क अपने आप में भले ही सही प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें इस सच को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि यह कोई पहचान की लड़ाई नहीं थी। भाजपा में ऐसा कौन व्यक्ति है, जो संघी नहीं है? इसके बावजूद कहा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी की यह प्रतीकात्मक जीत है और किसी मजबूत सरकार के खिलाफ ऐसी जीत भी मायने रखती है। वह भी तब, जब इसी सरकार के एक दिग्गज मंत्री वर्षो पहले भरी सभा में ऐलान कर चुके हों कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते। दरअसल, युवाओं को पता था कि वह लड़ाई किस हद तक ले जा सकते हैं और कहां तक सरकार को झुका सकते हैं। उन्होंने इसीलिए मांग भी ऐसी रखी थी, जिसे मानना सरकार के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। यह एक कैलकुलेटेड लड़ाई थी, इसलिए इसके नतीजे को भी इसी आईने में देखना होगा। ऐसे में छात्रों की मांग को मानने के बावजूद केंद्र सरकार ने प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाकर यही संदेश दिया है कि चेहरा भले अभी दबाव में बदल दिया है, लेकिन उसकी नीति नहीं बदलने जा रही है, यानी युवाओं की मांग को लेकर अभी भी केंद्र सरकार बहुत गंभीर नहीं है। ऐसे में जो लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था में नीतिगत परिवर्तन आएगा, उसका जवाब भाजपा ने शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से दे दिया है। कह सकते हैं कि जब हर काम पीएमओ से हो रहा है, ऐसे में शिक्षा मंत्री कोई भी हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता है।●

मोदी सरकार के पहले मंत्री का बेआबरू इस्तीफा

● संजय सिन्हा

अपने देश में मंत्रियों के इस्तीफों का एक लंबा इतिहास देखा है। उसमें अभी अभी सबसे ताजा घटना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। उनके इस्तीफे पर मैं सबसे बाद में विशलेषण करुगां। सबसे पहले इस्तीफे की बात करते हैं। आजादी के बाद सन् 1952 के पहले आम चुनाव से तो स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री। दिसंबर 1956 में उस समय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। एक रेल दुर्घटना तमिलनाडु में हुई थी। जिसमें 44 लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा लेकर वे जवाहरलाल नेहरू के पास गए और कहा, 'मैं इस घटना का पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए।' जवाहरलाल नेहरू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तब से यह एक तरह का 'गोल्ड स्टैंडर्ड चौबीस कैरेट' बन गया। उन्होंने जो नैतिकता का मानदंड स्थापित किया, उसे बहुत लोगों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन वैसा हो न सका। लालबहादुर शास्त्री पुन: एक वर्ष बाद सन् 1957 में, फिर से नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। ऐसा नहीं था कि इस्तीफा देकर हमेशा के लिए चले गए। बाद में, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, वे देश के प्रधानमंत्री भी बने। वो अलग बात है कि लालबहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने के वजह से प्राण गवानी पड़ीं।

सन् 1958 में मुंद्रा कांड के वजह से हुआ। उस समय टी. टी. कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे। यहाँ दो अलग-अलग स्थितियाँ समझनी होंगी-एक, जब किसी ने स्वयं इस्तीफा दिया, और दूसरी, जब किसी को इस्तीफा दबाव में देना पड़ा। क्योंकि जाँच आयोग ने उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह माना। आरोप था कि मुंद्रा की आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों के शेयर एलआईसी के पैसे से खरीदे गए। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद टीटीके को पद छोड़ना पड़ा। इसलिए अंतर समझना होगा कि लालबहादुर शास्त्री ने स्वयं इस्तीफा दिया, जबकि टी. टी. कृष्णमाचारी को परिस्थितियों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अब माधवराव सिंधिया के मामले को भी समझते है। वे नागरिक उड्डयन मंत्री थे। पीवी नरसिम्हा सरकार में सन् 1993 में एक लीज एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन माधवराव सिंधिया को लगा कि मुझे भी नैतिकता का मानदंड स्थापित करना चाहिए। वे भी अंगराई लेते जोश के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के पास गए और कहा, 'ये मेरा इस्तीफा है, मैं इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ।' फिर उन्होंने इस्तीफा पत्र दिया। लेकिन नरसिम्हा राव ने माधवराव सिंधिया से बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने इस्तीफा लेने के लिए माधवराव सिंधिया के तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, 'अरे, इसकी क्या जरूरत थी?' माधवराव सिंधिया को लगा कि शायद इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। लेकिन जब वे प्रधानमंत्री आवास से अपने घर पहुँचे, तो टेलीविजन पर खबर चल रही थी कि राष्ट्रपति ने माधवराव सिंधिया का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। यानी जितनी देर में वे प्रधानमंत्री आवास से अपने घर पहुँचे, उतनी देर में उनका इस्तीफा राष्ट्रपति भवन पहुँच गया, मंजूर भी हो गया और उसकी खबर भी प्रसारित हो गई। ये लालबहादुर शास्त्री का और माधवराव

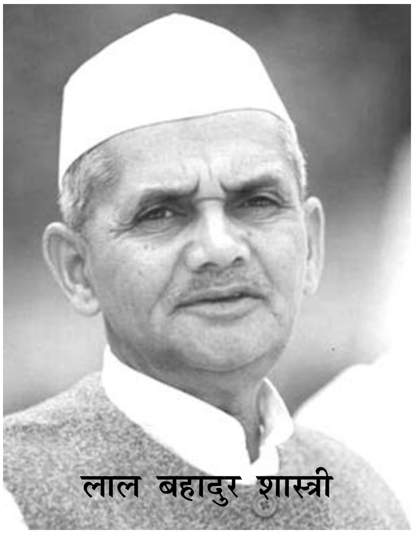

लाल बहादुर शास्त्री

माधव राव सिंधिया

ए. राजा

सिंधिया का उदाहरण है। दोनों ने इस्तीफा दिया था। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह सरकार के गृह मंत्री शिवराज पाटिल की सन् 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ। उस समय गृहमंत्री शिवराज पाटिल थे। उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया था, उसके लिए सिर्फ इस्तीफा लेने की बजाय उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

एनएसजी अगर देर से मुंबई पहुँची तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवराज पाटिल थे। पहले तो एनएसजी को जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। उस समय एनएसजी मानेसर में थी। मानेसर से दिल्ली एयरपोर्ट आने के लिए कोई विमान उपलब्ध नहीं था। किसी तरह व्यवस्था हुई। फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक इंडियन एयरलाइंस की सिविल फ्लाइट खाली कराई गई। एनएसजी के कमांडो उसमें बैठ गए, लेकिन दो घंटे से ज्यादा समय तक विमान एयरपोर्ट पर ही खड़ी रही। क्यों? क्योंकि गृहमंत्री ने कहा कि 'हम भी जाएंगे', और उनको तैयार होने में इतना समय लगा। आप समझिए, वह राष्ट्रीय संकट का समय था। उस समय गृहमंत्री का यह व्यवहार था। बाद में उनसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन इतनी बड़ी घटना के लिए उनकी वास्तविक जवाबदेही तय नहीं हुई। कुछ ही महीनों बाद उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। यानी एक तरह उन्हें परमोशन कर पुरस्कृत किया गया। क्योंकि उन्होंने सरकार को संकट से बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह मनमोहन सिंह सरकार में ए राजा,कपिल सिब्बल,शिबू सोरेन,पवन बंसल,अश्विनी कुमार ये सभी आर्थिक भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना पड़ा ऐसा नहीं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आपलोगो भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए इस्तीफा दिजिए। ब्लकि विपक्ष ने सबूत गवाह के अधार पर सुप्रीमकोर्ट गई और वहाँ से इन भ्रष्टाचारी मंत्रीयों को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो तेलचट्टा जनता पार्टी के आंदोलन थे, इसको आप समझिए। ये एक बीनालीडरशिप आंदोलन था। इसका कोई संगठन नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं थे और जमीन पर इसका कोई आधार नहीं था। इसका आधार सिर्फ सोशल मीडिया था। इन लोगों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि पूरे देश में अराजकता फैल सकती थी। अब सरकार के सामने दो विकल्प थे। पहला, सरकार सख्ती करे। सख्ती का मतलब अंततः पुलिस द्वारा गोली चलाना होता है। यही आंदोलनकारी चाहते थे। ऐसी कोशिश तथाकथित किसान आंदोलन के समय से चल रही थी कि सरकार को गोली चलाने के लिए मजबूर किया जाए, ताकि पूरे देश में अराजकता फैलाने का बहाना मिल जाए।

सरकार वह बहाना देना नहीं चाहती थी। इसलिए किसान आंदोलन में भी गोली नहीं चली। लाल किले पर चढ़ने के बाद भी नहीं चली। और इस आंदोलन में भी सरकार ने तय किया था कि गोली नहीं चलेगी। लेकिन पुलिस एक्शन नहीं होगा, यह कोई सरकार कैसे तय कर सकती है? दो स्थितियाँ होती हैं–पुलिस एक्शन और पुलिस इनएक्शन। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन 1984 में जो हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ, लोगों को जिंदा जलाया गया, तीन हजार से ज्यादा सिख मारे गए–वह पुलिस इनएक्शन का उदाहरण था। पुलिस ने लोगों को नहीं जलाया, लेकिन हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। सेना की तैनाती दो नवंबर

को रात में हुई, जबकि सेना की छावनी दिल्ली में ही थी। आदेश देने और सेना को सड़क पर उतारने में कुछ ही मिनट लगते हैं। शहर को नियंत्रित किया जा सकता था। पुलिस ने एक लाठी तक नहीं चलाई, गोली की बात तो दूर रही। किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। आजाद भारत के इतिहास में प्रशासनिक निष्क्रियता (इनएक्शन) का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही दूसरा मिले। उस समय गृहमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नियम के अनुसार कम से कम गृहमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था और प्रधानमंत्री की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर गृहमंत्री का इस्तीफा लिया जाता, तो और बातें सामने आतीं। एक नवंबर को ही प्रधानमंत्री कार्यालय से पी. वी. नरसिम्हा राव को कह दिया गया था कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी अब प्रधानमंत्री कार्यालय देखेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी उन्हें गृहमंत्री के पद से हटाया नहीं गया, लेकिन उनके अधिकार ले लिए गए। वे अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय के पास चले गए, यानी प्रधानमंत्री के पास। इसके बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हिंसा का जो नंगा नाच हुआ, वह सबने देखा,सिर्फ अभी के युवा पीढ़ी नहीं देखा जिसे जेन जी कहा जा रहा है। कांग्रेस ने उसे रोकने की कोई प्रभावी कोशिश नहीं की। लेकिन इस घटना के बाद करीब साढ़े छह साल तक राजीव गांधी जीवित रहे थे। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि क्या वे 1984 में हुए सिख नरसंहार के लिए माफी मांगेंगे। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं हुई, जबकि तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो इस सरकार के सामने भी यही विकल्प था कि जो हो रहा है, उसे होने दिया जाए। संसद पर हमला हो जाए तो हो जाए। अगर 2873 से ज्यादा संख्या में गंभीर अपराधों के आरोपी संसद में घुस जाएँ, तो क्या यह स्वीकार किया जा सकता है? क्या उनके साथ छात्र होने के कारण उन्हें संसद में घुसने, हंगामा करने, तोड़फोड़ करने या किसी की हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है?आश्वासन कौन दे सकता था कि ये लोग संसद में घुसेंगे तो कुछ नहीं करेंगे? संसद में घुसे बिना जो कुछ कर रहे थे, वो तो सिर्फ ट्रेलर था कि अंदर जाकर क्या करने वाले हैं। और कांग्रेस की सरकार तो, संतों पर गोली चलवा चुकी है क्योंकि वे संसद में जाने की कोशिश कर रहे थे। वे निहत्थे थे, उनके हाथ में पत्थर का एक छोटा-सा टुकड़ा भी नहीं था। उन पर गोली चली। जब देशभर में हंगामा मचा, उस समय गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। उनसे इस्तीफा लिया गया। तो इन दोनों के फर्क को देखते चलिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। गुलजारीलाल नंदा को हटा दिया गया, लेकिन बाद में वे फिर लौटकर आए। वे दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने। खैर अब धर्मेन्द्र प्रधान पर बातें करते हैं।

☞ **धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को किस कैटेगरी में रखते हैं? :-** मुझे लगता है कि यह उन दोनों कैटेगरी से बिलकुल अलग मामला है। धर्मेन्द्र प्रधान की प्रधान को उसी समय मंत्रीमंडल से कुछ दिनों के लिए हटा देना चाहिए था जब उन्होंने फालतू के कानून यूजीसी लागू करने के प्रस्ताव पेश किया था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के 12 वर्षो की सरकार में आधा दर्जन बेकार काम अगर हुये तो उसमें धर्मेन्द्र प्रधान के मंत्री रहते फालतू के कानून लाना जिसे कोई वर्ग की मांग नहीं थी भले वो एससी एसटी या ओबीसी हो। ये यूजीसी कानून ही बीजेपी को बांकीपुर पटना एवं दतिया मध्यप्रदेश में बुरी तरह हरा दिया। अगर बीजेपी संगठन इसमें उचित एवं समय पर जल्द निर्णय नहीं लेती और सरकार को सलाह नहीं देगी तो सन् 2029 के आमचुनाव मोदी सरकार के लिए बहुत खराब साबित होना बहुत संभव है। मोदी सरकार ने बहुत चतुराई से धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफा की पटकथा लिखीं। मोदी सरकार के सामने जो संकट था, वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना हल नहीं हो सकता था। ऐसी परिस्थिति बन गई थी। सरकार चाहती तो उन्हें बर्खास्त कर सकती थी, लेकिन बर्खास्त नहीं किया। उनसे इस्तीफा लिया गया। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि 'जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ।' उन्होंने लिखा कि छात्रों को भड़काया न जा सके, उन्हें भ्रमित न किया जा सके, इसलिए छात्रों के हित में मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उसके बाद की घटनाएँ भी देखिए। संसद में जब वे इस्तीफा देने के बाद पहुँचे, तो भाजपा सांसदों ने उनका स्वागत किया। लगातार सरकार और पार्टी की ओर से उनकी प्रशंसा की जाती रही हैं। जैसे लगता है उन्होंने ओलंपिक से कोई गोल्ड मेडल जीतकर लाया है। मतलब सरकार यह मानती है कि पेपर लीक का जो कांड हुआ, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं थे। परिस्थितियाँ ऐसी बनीं कि उनका इस्तीफा लेना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

☞ **अब अगला सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान की वापसी कब होगी? :-** आप यह मानकर चलिए कि उनकी वापसी होगी, यह तय है। केवल यह तय नहीं हुआ है कि कब होगी और किस रूप में होगी। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आ सकते हैं और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। दोनों विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को किनारे लगा दिया है या हाशिए पर धकेल दिया है, तो उसे जनता को दूर कर लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की मुख्यधारा में वापसी होना तय है। इतिहास भी यही बताता है। पहले जिन मंत्रियों के इस्तीफे हुए या जिनसे इस्तीफा लिया गया, उनके उदाहरण भी यही बताते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो राय धर्मेंद्र प्रधान के बारे में है, उसे देखते हुए भी उनका मानना है कि बड़े संकट से निपटने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का बलिदान देना पड़ा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पार्टी या सरकार में कुछ नहीं है। धर्मेन्द्र प्रधान की वापसी तय है।●

● **अमित कुमार**

बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर में भारी मतों से जीत दर्ज की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट पर उनकी जीत को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशांत ने बांकीपुर में 19 हजार 324 वोटों से जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले तो वही भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 44,827 मत मिले। मतगणना के दौरान प्रशांत किशोर ने लगातार बढ़त बनाए रखी। तीसरे नंबर पर रहीं राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता को 14,273 वोट मिले। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसमें मतदान प्रतिशत करीब 34.30 रहा। बांकीपुर सीट पिछले चार दशक से भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव को भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जन सुराज ने इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल दिया। इस जीत के साथ जन सुराज पार्टी बिहार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही है। प्रशांत किशोर ने इसे बिहार में बेहतर शासन, शिक्षा, रोजगार और विकास की मांग का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि एक विधायक अकेले रातोरात बड़े बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। मीडिया से बातचीत में प्रशांत

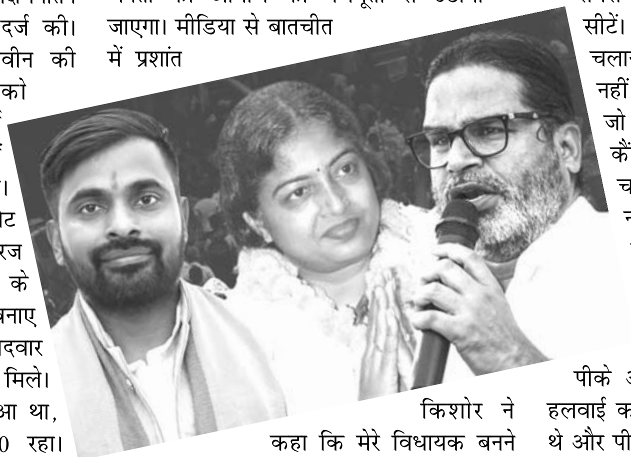

किशोर ने कहा कि मेरे विधायक बनने पर बांकीपुर बेंगलुरू नहीं बन जाएगा, लेकिन आप अगले दो-तीन महीनों में यहां कुछ सुधार जरूर देखेंगे। उन्होंने बांकीपुर की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, दोनों के लिए वे समान रूप से काम करेंगे।

बहरहाल, पीके को इस उपचुनाव में मिली जीत से जनसुराज के जश्न के बीच एक दृश्य सामने दिखाई देता है, नवंबर 2025 । याद है जब प्रशांत किशोर 2 साल से पदयात्रा कर रहे थे। धूल-मिट्टी, पदयात्रा हर टीवी चैनल पर यही छाया हुआ था। हर इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ही सबसे आगे थे और नतीजा 243 में से जीरो सीटें। लोग खूब मजाक उड़ाने लगे। दुकान चलाने वाला अपनी दुकान का शटर तक नहीं उठा पा रहा था। पीके वही आदमी थे जो 2014 में थे, जिन्होंने मोदी जी के लिए कैंपेन किया था। उस समय चाय पर चर्चा, 3डी रैली की बातें होती थीं। फिर नीतीश जी के साथ मिलकर जीते। बंगाल में दीदी जीतीं। पंजाब में अमरिंदर सिंह जीते। उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल जीते। वह दक्षिण भी गए, जहां अब विजय भी जीते। लेकिन पीके अपने लिए कुर्सी नहीं पा सके। यानी हलवाई की दुकान पर होने के बावजूद वह भूखे थे और पीके को ताने सुनने पड़ रहे थे। वोट वाले दिन ताने या डेटा मायने नहीं रखते। मायने यह रखता है कि इवीएम से क्या निकलता है और जब पीके इवीएम से जीते, तो पीके का वह बयान फिर याद आया कि 'हम अभी मरे नहीं हैं'। सवाल यह है कि पीके बीते वर्ष हुए चुनाव से 9 महीनों में क्या बदला? तो बता दें कि पीके ने तीन काम किए जिससे वह जीते। पहली बात,

इस बार उन्होंने सिर्फ जमीन पर काम नहीं किया, बल्कि पीके खुद मैदान में थे। नवंबर में वह खुद नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अब वह लड़ रहे थे। इस बार उनका चेहरा, उनकी इज्जत, उनका करियर, सब कुछ एक सीट पर दांव पर लगा था। अगर वह हार जाते, तो सब खत्म। दूसरी तरफ, वह और भी बड़े नेता बन सकते थे। लेकिन राजनीति में 'ज्वायंट किलर' की कीमत अलग होती है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा याद है? उन्होंने केजरीवाल को हराया था। बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। जब सरकार मुश्किल में हो और कोई व्यक्ति आकर मैदान में मुकाबला करे, तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। लोग कहते हैं, वाह! लोग हमेशा उसे पसंद करते हैं जो टीम में नहीं खेलता, जिसे मौका नहीं मिलता। जो 11 खिलाड़ियों की टीम में खेलता है, वह आम खिलाड़ी होता है। जो बाहर बैठा होता है, वह खास खिलाड़ी होता है। और पीके बाहर बैठे थे। उन्हें लोगों की सहानुभूति मिल रही थी। और पीके जानते थे कि उनके दोनों विचार अच्छे थे और उन्होंने उनके लिए काम किया। आखिरी बात यह थी कि पीके नवंबर में बहुत बातें कर रहे थे। वे हालात बदल देंगे, वे यह करेंगे, वे वह करेंगे। वे एक रात में बिहार बदल देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। इस बार इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं थीं। इतना कुछ नहीं था। इस बार एक सीधा-सादा कॉन्सेप्ट था। 15 साल पुरानी सत्ता के सामने एक नई जीत।

राजनीति हिसाब-किताब का खेल है। जब वोटर्स का उत्साह ठंडा हो और बदलाव चाहने वाले वोटर सुबह लाइन में लगें, तो अक्सर जीत उन्हीं की होती है। बिहार की राजनीति भी इससे अलग नहीं है और यह कमाल की बात है। वोटिंग सिर्फ 34% हुई, जो पिछले चुनाव से 7% कम है। यानी, 100 में से 66 लोग वोट देने नहीं आए। अब कम वोटिंग का फायदा को सही साबित किया? आंकड़े को देखे तो पता चलेगा कि सवर्ण वोटर्स के वोट 37% हैं। यह वोटों की एक बहुत बड़ी संख्या है और अगर इसे अलग-अलग जातियों में बांटें तो कायस्थ समुदाय, जिससे नितिन नवीन आते हैं, उनका वोट 14% है। अगर आप भूमिहारों को देखें, तो इस सीट पर उनका वोट प्रतिशत 8% है और अगर आप ब्राह्मणों को देखें, जिस जाति से प्रशांत आते हैं, उनका वोट प्रतिशत 7% है और राजपूत 5% हैं। यह उनका प्रभाव है। अगर आप इस सीट को देखें तो बांकीपुर में कुल वोट 3.7 लाख हैं और इसमें, जो 1.7 लाख वोट हैं, उन्हें बहुसंख्यक वोटर्स माना जाता है। अब सवाल है कि बीजेपी की हार का अंतर क्या है? मान लेते हैं कि यह 19,324 है। अब, मैं आपको यह बहुत महत्वपूर्ण डेटा बता रहा हूं। कि एक सीट जिसे बीजेपी जीत रही है, जहां बहुसंख्यक वोटर्स लगभग 37% हैं, अगर बीजेपी वहां हारती है, तो एक सवाल उठता है कि क्या बहुसंख्यक वोटर्स बीजेपी से नाराज हो सकते हैं? यूजीसी का मुद्दा। एक ऐसा मुद्दा था, जिसके बाद यह पहली तरह का लिटमस टेस्ट हो रहा था। वही NEET पेपर लीक और अन्य कारणों से छात्रों का सड़कों पर उग्र आंदोलन, भरत तिवारी फेक एनकाउंटर जैसे बहुत सारे मुद्दों से वोटर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इस परिणाम के बाद बीजेपी को सोचना और समझना चाहिए कि क्या सवर्णों ने कोई संदेश देने की कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का सवर्ण वोटर भी उनसे नाराज हो रहा है? या ऐसे चुनावों में जहां उन्हें लगता है कि बीजेपी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वे कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इससे बीजेपी को यह समझना चाहिए कि यूजीसी जैसे मुद्दों की वजह से आपके मुख्य वोटर आपसे दूर जा रहे हैं और बांकीपुर का वोट प्रतिशत देखें, तो वहाँ वोट प्रतिशत यानी चुनाव में पड़े वोटों का प्रतिशत 2025 में यह 41% था और 2026 के चुनाव में यह घटकर 34% हो गया। तो क्या बीजेपी का वोटर यह सोचकर घर से नहीं निकला कि अगर वे उन्हें वोट नहीं देंगे, तो किसी और को भी नहीं देंगे?

गौरतलब है कि जिस बांकीपुर सीट

पर प्रशांत किशोर की जीत हुई है, यह वो सीट है जिसको लेकर दबी जुबान में अक्सर बीजेपी वाले कहते थे कि यहां कुत्ता बिल्ली भी चुनाव लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा, और वो गलत नहीं कहते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अपना घर। जिस सीट से वो एक दो बार नहीं लगातार पांच बार जीते थे और यहीं से जीतकर वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 15 साल से यहां कमल का बटन लगातार दब रहा था और नतीजा पहले से ही लिखा था और ताना उस आदमी को मारा जा रहा था जिसने 243 सीटों पर लड़कर शून्य जीता था। कई लोगों ने प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाया और प्रशांत तब खुलकर कहते थे कि मैं मरा नहीं, अभी जिंदा हूं। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। मतगणना के दिन गिनती वाले हॉल में राउंड दर राउंड में उनकी बढ़त वही मजाक भारी पड़ता गया। प्रशांत किशोर के समर्थक हर राउंड में दिखते बढ़त पर खुशी से नाच रहे थे और कह रहे थे कि आज सावन के सोमवार के दिन बाबा का आशीर्वाद मिल गया। पहले राउंड में मिला, दूसरे राउंड में मिला, चौथे में मिला, दसवें में मिला। मिलते मिलता चला गया। यह तो वही बात हो गई मानो एक सबसे कमजोर लड़का सीधे आए और पहलवान के अखाड़े में घुसे और जो सबसे मजबूत पहलवान हो उसको पटक दे। एकतरफा मुकाबला। जब जब बिहार को समझने वाले को लगता है कि इसे समझ गए हैं, वह आपको झटका देता है। और बांकीपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

सवाल यह है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना घर कैसे हार गए? और इस हार के मायने क्या हैं? प्रशांत किशोर के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। साथ ही आरजेडी विपक्षी पार्टी, तीसरे नंबर पर चली गई। तो क्या आरजेडी के लिए भी आगे मुश्किले होगी। अब तो पीके के जीत पर तीसरे नंबर पर जाने वाली आरजेडी की नेत्री और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने इसे भाजपा की 'लोमड़ी' की जीत तक कह डाला। बिडम्बना है कि पीके ने सबको सीखना जिताए थे, पर 2025 के चुनाव में अपना नहीं जीत पाए। इसी पर मजाक चल रहा था। अब बात करते हैं कि बांकीपुर भाजपा के लिए इतना पक्का क्यों था? पटना का दिल है भाई बांकीपुर। गांधी मैदान से सटा इलाका। पढ़े लिखे लोग, दुकानदार, नौकरी पेशा। वो इलाका जहां शाम को चाय की दुकान पर राजनीति उबलती है और वोट हमेशा एक तरफ गिरता है। 2010 से यहां एक ही चेहरा जीतता है, नितिन नवीन। सफेद कुर्ता, माथे तिलक, पटना की गलियों में जाना पहचाना आदमी और उससे पहले उनके पिताजी यहीं जीतते थे-नवीन किशोर सिन्हा। यानी यह सीट पार्टी के लिए सीट थोड़ी थी, घर की बैठक थी। यहां कौन सा टेंशन है? दादा परदादा के जमाने से अंगद का पैर। जिसे हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर हुआ ये कि नितिन नवीन की किस्मत अचानक से उछाल मार दी। ऐसा लगा कि सीध े सरस्वती जी आशीर्वाद दे दी। लक्ष्मी जी भी दे दी। शंकर जी भी दे दी। आओ बच्चा। मतलब जिस मोदी जी के सामने शायद वो पहली सीट पर बैठ ना पाते हो, वो कह सकते हैं कि मोदी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अध्यक्ष हैं। मोदी जी कहेंगे हमारे अध्यक्ष हैं। मोदी जी कहते भी हैं कि 'ये हमारे बॉस हैं' और विधायक की छुट्टी लगने लगी। अब दिल्ली दिख रही थी। पार्टी

ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो फिर विधायक कहां रहेंगे? राज्यसभा चले गए और पीछे सीट खाली हो गई। भाजपा तो यह मान के बैठी थी कि भाई घर है हमारा 15 साल का रिकॉर्ड है, जीत पक्की है तो उतार दिया नीरज सिन्हा को। बयान भी आया कि इस सीट से बीजेपी कुत्ता-बिलाई को भी खड़ा कर दे तो वह भी जीत जायेगा। नीरज सिन्हा के सामने वो आदमी था जो बीते वर्ष के चुनाव में शून्य हो चुका था। जिसका सभी ने मजाक उड़ाया था, पीके। हां, यही मजाक था जो सब उड़ा रहे थे कि भाई पीके तो मीडिया वालों के बनाए हुए हैं।

बहरहाल, जब जमे जमाए वोटर का जोश ठंडा हो और बदलाव चाहने वाले वोटर सवेरे सवेरे लाइन में लगे तो पलड़ा अक्सर उधर ही झुकता है। हां, बिहार की राजनीति भी इससे अलग नहीं है और यही कमाल है। और अब इस जीत के झटके समझते हैं। क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर की जो जीत है, उससे सबसे पहला झटका लगा है भाजपा को। क्योंकि बांकीपुर की सीट पर हार सिर्फ एक विधायक की हार थोड़ी ही है। यह फाइल तो उस दफ्तर तक जाएगी, जहां पर मोदी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं नितिन नवीन साहब और संदेश तो जाएगा देश दुनिया में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना घर नहीं बचा पाए। विपक्ष तो इस बात को दो-चार चार महीनों तक चटकारे खा कर मजे लेगा। दूसरी तरफ एक झटका और लगा है तेजस्वी यादव को, वह भी बंपर वाला। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इस पूरी लड़ाई में तीन नंबर पर रही। मतलब पटना की जनता बीजेपी से नाराज थी, ये तो नतीजे बता रहे हैं और उसकी नाराजगी का ठेका जनता ने आरजेडी को नहीं पीके को दे दिया। यानी जो कुर्सी 30 साल से लालू परिवार के नाम पर बुक थी, उस पर एक नए आदमी आकर बैठ गया। यह तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी नहीं है, पूरा का पूरा घंटा घर है जो टंग-टंग बज रहा है। हालांकि उपचुनाव, मुख्य चुनाव जैसा खास नहीं होता, कम वोटिंग होती है, लोगो में गुस्सा होता है, जोश का उबाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि आम चुनाव आते हैं, नतीजे पलट जाते हैं। पहले भी हुआ है। उपचुनाव के शेर आम चुनाव में ढेर। इस एक जीत से पीके मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं आए हैं, सच बात है। लेकिन यह भी सच है कि जहां कुत्ता भी जीत सकता था बीजेपी के टिकट पर, वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीता। यह भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी से आज एक तबका नाराज हुआ, जिसको पीके ने भुनाया और यह जितना बीजेपी को परेशान करना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा तेजस्वी को परेशान करना चाहिए कि हैप्पी बर्थ डे बाहर मत मनाएं, घर में मनाएं। जनता देखती है हमारे लिए कौन कितना समर्पित है। यह कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है और यह कहानी कहती है कि पीके मजाक नहीं है। नितिन नवीन जी को सोचना पड़ेगा कि जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सब जगह मिठाई बांकीपुर में बंटी। लड्डू यहीं बंटे, ढोल यहीं बजा। अपना विधायक देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन गया और आज उसी बांकीपुर ने उस घर से बाहर उस पार्टी को कर दिया। 15 साल का किला था, नौ महीने में साफ। पीके की जीत ने भी बताया कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ना किला, ना मजाक। पीके कहते थे ना कि जिंदा हैं अभी कहानी बाकी है। आज बांकीपुर ने उस कहानी का पहला पन्ना लिखा है, बाकी पन्ने कौन लिखेगा यह 2030 में देखेंगे! ●

कैसे एक साधारण कचरे के डिब्बे को 'बायो-मेडिकल वेस्ट (BMW) बिन' का तकनीकी जामा पहनाकर बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) में करोड़ों रुपए के सरकारी धन की व्यवस्थित लूट को अंजाम दिया गया और कैसे इस पूरे खेल में हर दस्तावेज, हर परचेज ऑर्डर, हर याचिका में दो नाम बार-बार सामने आते हैं-तत्कालीन प्रबंध निदेशक डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे और मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) कुमारी सीमा। पटना हाईकोर्ट में दाखिल दस्तावेजों की गहरी पड़ताल पर प्रस्तुत है शशि रंजन सिंह एवं राजीव कुमार शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट :-

❖ **जब कूड़ेदान बन गया 'वीवीआईपी' और सरकारी खजाना बना निजी तिजोरी :-** बिहार की राजनीति और सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से एक शब्द बार-बार गूंज रहा है-'डस्टबिन घोटाला'। लेकिन यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बिहार के गरीब मरीजों के इलाज के लिए स्वीकृत सरकारी धन की सरेआम लूट की कहानी है। आरोप है कि जिस प्लास्टिक कचरे के डिब्बे की बाजार में असली कीमत महज 1,000 से 1,500 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी, उसे BMSICL ने 15,490 रुपए में खरीदा। जिस छोटे डिब्बे की वाजिब कीमत करीब 1,100 रुपए बैठती थी, उसे 11,474 से लेकर 11,490 रुपए तक में खरीदा गया और इन दोनों ही दामों पर 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से वसूला गया। राष्ट्रीय जनता दल की नेता रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया मंच 'X' पर तंज कसा-'कूड़ेदान छोटा, लेकिन बिल दस गुना बड़ा!' और यह पोस्ट देखते ही देखते बिहार की राजनीति में एक बड़े तूफान में बदल गई।

रोहिणी आचार्य

सुब्रत सेन

लेकिन जिन दस्तावेजों-शिकायतकर्ता का विस्तृत ज्ञापन, BMSICL का पटना हाईकोर्ट में दाखिल काउंटर एफिडेविट, परचेज ऑर्डर रजिस्टर, और महालेखाकार (एजी) कार्यालय की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर यह मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है, उनसे पता चलता है कि यह कोई मामूली 'डस्टबिन विवाद' नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, बहु-स्तरीय भ्रष्टाचार है, जिसमें टेंडर की शर्तों में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, प्रतिस्पर्धा का सिर्फ दिखावा किया गया, कीमतें दस से बारह गुना तक फुला दी गईं और नतीजा निकला-अनुमानित रूप से 276 करोड़ रुपए (जीएसटी सहित) का सीधा सरकारी नुकसान। यह रकम किसी अमूर्त कल्पना का आंकड़ा नहीं, बल्कि खुद BMSICL के अपने परचेज ऑर्डर रजिस्टर से निकाला गया हिसाब है।

❖ **असल में BMW BINS हैं क्या और यह 'तकनीकी सफाई' कितनी टिकाऊ है? :-** यह समझना जरूरी है कि विवाद के केंद्र में मौजूद यह उत्पाद कोई साधारण घरेलू या नगरपालिका कूड़ेदान नहीं है। BMSICL के मौजूदा प्रबंध निदेशक सुब्रत सेन ने सार्वजनिक रूप से सफाई दी है कि यह अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली माइक्रोवेव-आधारित बायो-मेडिकल वेस्ट स्टरलाइजेशन प्रणाली का हिस्सा है, यानी BMW यहां 'बायो-मेडिकल वेस्ट' है, कोई कार ब्रांड नहीं। लेकिन यह सफाई तभी तक टिकती है, जब तक इसकी तुलना बाजार के आम प्लास्टिक कूड़ेदान से न की जाए। असली सवाल यह है : क्या इसी तकनीकी श्रेणी यानी माइक्रोवेव-अनुकूल मेडिकल-वेस्ट बिन की बाजार दर भी दस गुना कम है या नहीं? और दस्तावेज बताते हैं कि हां,

है। शिकायतकर्ता ने जो तुलना पेश की है, वह किसी घरेलू डस्टबिन से नहीं, बल्कि उसी श्रेणी के यानी माइक्रोवेव के लिए बने बिन, बाजार आपूर्तिकर्ताओं की दरों से की गई है। इसलिए 'यह आम डस्टबिन नहीं है' वाली दलील तथ्यों की रोशनी में, महज एक बचाव की चादर भर साबित होती है। असली गड़बड़ी को ढंकने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्थगित करने के लिए।

❖ **टेंडर की साजिश : पात्रता शर्तें अचानक गायब क्यों हुईं? :-** पूरा मामला BMSICL द्वारा जारी टेंडर संख्या BMSICL/2023-24/ME-317 से शुरू होता है। अगस्त 2023 में माइक्रोवेव-आधारित मेडिकल वेस्ट स्टरलाइजेशन यूनिट, कस्टमाइज्ड बायोडिग्रेडेबल बैग, माइक्रोवेव के लिए मास्टर बिन्स और स्टेनलेस-स्टील मास्टर ट्रॉली की खरीद के लिए। प्री-बिड मीटिंग 28 अगस्त 2023 को हुई और इसी के बाद शुरू होता है वह खेल, जिसे शिकायतकर्ता ने 'जानबूझकर की गई पात्रता-हत्या' कहा है।

प्री-बिड मीटिंग के बाद BMSICL ने 'बोलीदाताओं से मिले सुझावों' का हवाला देकर एक करेक्शन नोटिस (Corrigendum-I) जारी किया, जिसमें ठीक वही शर्तें हटा दी गईं, जो किसी छोटी, अनुभवहीन या मिलीभगत वाली फर्म को टेंडर से बाहर रख सकती थीं :-

☞ **टर्नओवर की शर्त पूरी तरह गायब :-** मूल शर्त थी 10 करोड़ रुपए का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर, ऑडिटेड बैलेंस-शीट से प्रमाणित। करेक्शन नोटिस में इसे सीधे 'डिलीट' कर दिया गया।

☞ **अनुभव की शर्त भी उड़ा दी गई :-** पिछले दो वर्षों में कम-से-कम 20 माइक्रोवेव उपकरणों की सरकारी आपूर्ति का अनुभव अनिवार्य था; यह भी 'डिलीट'।

☞ **क्षमता का पैमाना ही बदल दिया गया :-** 80 बेड अस्पताल की क्षमता वाली शर्त हटाकर मानक ही ऐसा बना दिया गया, जो पात्र उपकरणों की पूरी श्रेणी बदल दे।

और यह सिर्फ शर्तें हटाने तक सीमित नहीं रहा, सरकार के

BMSICL

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited, 2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura, Adjacent to State Health Society, Patna 800023, Phone/Fax: +91612 2283287,+ 91612 2283288

Corrigendum-I

Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Limited (BMSICL) had invited E-Bids from the interested parties for the procurement, rate contract and the supply of medical equipment for different Govt. Institutions of Bihar vide Notice Inviting Tender No.- BMSICL/2023-24/ME-317. During and after Pre-bid meeting various suggestions were received from different prospective bidders regarding amendment in technical specification of equipment which were discussed and deliberated on by the experts, who after due deliberation recommended certain amendments in the technical specification of the equipment, which are annexed as Annexure-I of this corrigendum. In order to facilitate maximum participation of bidders the tender schedule is being revised as follows:-

Tender Reference No.	**BMSICL/2023-24/ME-317**
Last date and time of submission of online bids	**18th September 2023 till 17:00 Hrs.**
Last date and time of submission of original documents of EMD, Tender Fee and Document	**19th September 2023 till 14:00 Hrs.**
Date, Time and Place of opening of Technical Bid	**19th September 2023 (at 15:00 Hrs.) on the website of https://eproc2.bihar.gov.in in the office of BMSICL**
Date and time of opening of financial Bids	**To be announced later on https://eproc2.bihar.gov.in**

Note:-

1. **Bidders are advised to refer to the Annexure-I of this corrigendum before submission of bid.**
2. **Those who have submitted their bids are requested to re-submit their bids in accordance with this corrigendum.**

Annexed:- as above

Sd/-
GM (Procurement)
BMSICL

Annexure-I

Name of Equipment - Microwave Based Medical Waste Sterilization System

Sl. No	Technical Specification as per tender		Final Amendment
16	**DOCUMENTS ESTABLISHING BIDDER'S QUALIFICATION**		
	16.1 Pursuant to ITB Clause 12, the bidder shall furnish, as part of its bid, documents establishing the Bidder's qualification to perform the Contract if its bid is accepted. The documentary evidence of the Bidder's qualifications to perform the Contract shall establish to the Purchaser's satisfaction that:		No Change
	SECTION II- GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT		
14	**WARRANTY/ SHELF LIFE**		No Change
	14.2 This warranty shall remain valid for three years after the goods or any portion thereof as the case may be, from the date of commissioning and acceptance at the final destination indicated in the contract.		No Change
	SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT		
	2. No Exemption from payment of EMD, tender fees is permitted except in case of MSME registered manufacturing unit located in Bihar which will be guided by Bihar Industrial Investment Policy, 2016 as amended in 2020 for promoting industrial development in the State for the Technical Qualification, EMD, and TENDER FEES. Copy of the said policy may be seen on the website http://industries.bih.nic.in.		No Change
MEDICAL DEVICE SPECIFICATION			
(NHSRC, Govt. of India Format)			
(Including Information on the following where relevant/appropriate, but not limited to)			No Change
Device Type: Stand Alone Microwave Mobile Medical-waste Disinfection System (MMDS)- 20 lit capacity			Device Type: Stand Alone Microwave Mobile Medical-waste Disinfection System (MMDS)- 35 lit or more capacity
	GENERAL		
1	**USE**		
1.1	Clinical purpose	1. Disinfection of medical waste (med-waste) at point of generation (POG).	No Change
		2. Treats waste for upto 80 bedded hospitals.	Deleted
		3. Disinfects plastics, glass, laboratory waste, Blood Bags, like live or attenuated vaccine, culture plates, cell cultures, Petridishes, vaccutainers, Culture Media bottles, hospital linen etc.	No Change

Page 2 of 9

		4. Compliant to **G.S.R. 343(E). [28-03-2016] : Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (BMWM Rules, 2016)**	No Change
1.2	Used by clinical department/ward	District Hospitals/Sub District Hospitals/Blood banks/Infectious Wards/ICCU units/Genetic Research Labs/Dialysis, All laboratories viz. Microbiology/ Virology Labs/ Genetic Research Labs/ Biochemistry labs/Clinics/CHC's/OT complexes/OPD.	No Change
2	**TECHNICAL CHARACTERISTICS**		
2.1	Technical characteristics (specific to this type of device)	1. Processing capacity: not less than 20-litre/cycle	Processing Capacity: 35 litre/cycle or Higher
		2. Cycle time: 7-30 mins	No Change
		3. Working temperature: 70° - 100°C	No Change
		4. The unit Microwave Generators comprises the following:	No Change
		- HF Output: 1.5 kW	No Change
		- Minimum Frequency: 2450 MHz	No Change
		5. Electrical Requirements:	No Change
		- Inputs Voltage : 230 Volts,50Hz	No Change
		-Current : 16 Amp single phase power line.	No Change
2.2	Technology Automation	1. To mitigate Operator Risk: Funnel movement must be automated with zero human contact	No Change
		2. Front door lock must be electronic to avoid accidental opening of the door during the radiation/treatment of waste.	No Change
		3. Should have safety locks and overheating protection system.	No Change
		4. Should have Zero emission & discharge.	No Change
		5. Specially designed closed loop water ejector system for the microwave chamber to avoid discharge of any fumes/gases to the atmosphere.	No Change
2.3	Disinfection Log	10^5 to 10^7 log	No Change
2.4	User's interface	Touch display panel with push button, lamps/Cautions etc.	No Change
2.5	Software and/or standard of communication (where ever required)	PLC based automatic operation with online temperature and cycle recording with inbuilt printer.	No Change

Page 3 of 9

2.6	Disinfection Cycles	Model quoted must have dedicated pre-programmed disinfection cycles to be operated with one touch of a button on HMI.	No Change
		1. Bio-Medical Waste Disinfection	No Change
		2. Blood Bag Disinfection	No Change
		3. BD-Bactec / Mcctemey bottles disinfection	No Change
		4. Linen Disinfection	No Change
		5. Laboratory Waste Disinfection	No Change
		6. TB Sputum Disinfectionn cycle (validated by TB Authority)	No Change
		7. N-95 Sterilisation	No Change
		8. PPE Kit Sterilisation	No Change
		To ascertain patient & User safety all above 7 cycles must have Test report of efficacy validated from CSIR/ICMR/NCDC, issued at least 1 yr before the date of tender publishing. Self-attested certified copy of the test report to submitted with the techno-commercial offer.	To ascertain patient & User safety all above 7 cycles must have Test report of efficacy validated from CSIR/ICMR/NCDC/CPCB Approved Lab, issued after the date of tender publishing. Self-attested certified copy of the test report to submitted with the techno-commercial offer.
3	**PHYSICAL CHARACTERISTICS**		
3.1	Dimensions (mm)	(HxWxD) 905 mm x 1065 mm x 680 mm	Deleted
3.2	Vapour Emission	Zero emission. Operates with a built in water container & steam condenser.	No Change
3.3	Mobility, portability	Desktop Model model; Ideal for Point of Generation Treatment	No Change
4	**ENERGY SOURCE**		
4.1	Power Requirements	The unit works on a single phase simple 16Amp/1.5 kW power line with stable input voltage of 230V, 50 Hz.	No Change
4.3	Tolerance (to variations, shutdowns)	NA	No Change
4.4	Protection	Standard earthing protection with built in circuit breaker	No Change
4.5	Installed Power	1-1.5 kW	No Change
4.6	Stabilizer	3 KVa Servo Stabilizer with voltage range 160-270V. Output Voltage-230V with +/-2% accuracy. To be provided by the consignee	No Change

Page 4 of 9

	ACCESSORIES, SPARE PARTS CONSUMABLES,		
5.1	Accessories	2 microwaveable plastic, customised Bin : 20 Lit capacity.	2 microwaveable plastic, customised Bin : 35 Lit or higher capacity
6	**ENVIRONMENTAL AND DEPARTMENTAL CONSIDERATONS**		
6.1	Atmosphere / Ambiance (air conditioning, humidity in ideal circumstances)	Capable of operating continuously in ambient temperature of 0 to 50 deg C and relative humidity of 15 to 90% in ideal circumstances	No Change
6.2	User's care, Cleaning, Disinfection & efficacy testing procedure	Instruction provided in Operator's manual	No Change
7	**STANDARDS AND SAFETY**		
7.1	Certificates (pre-market, sanitary, ..); Performance and safety standards (specific to the device type);Local and/or international	1. As per GO no:X.11035/379/2015/DFQC Dated: 20/02/2018, the offered equipment should be ICMED plus	No Change
		2. The quoted model should be from an ISO 9001: 2015, EN -13485 certified company	No Change
		3. Test report of efficacy for all cycles validated from CSIR/ICMR/NCDC, issued at least 1 yr before the date of tender publishing.	Test report of efficacy forall cycles validated fromCSIR/ICMR/NCDC/ CPCB Approved Lab,issued atleast one year before the date of tender publishing.
		4. The equipment should have CE certification and design for client security & service.	The Quoted model must be from ISO 9001:2015 Manufacturer and the product must be have ISO 13485:2016 from NABCB/IAF accredited agency/EU CE with 4 digit Notified Body Number/BIS/US FDA.
7.2	Utility	The product should comply with GSR Notification 343 E and must have dedicated cycles such as blood bag Microbiology Waste, Bactec / Culture Bottles etc so that compliance of records/ cycle can be recorded with the time and date of treatment in compliance to the aforesaid GSR notification.	No Change

Page 5 of 9

8	**TRAINING AND INSTALLATION**		
8.1	Pre-installation requirements: nature, values, quality, tolerance	Stabilized power line of 230 volts with 16 Amp/160 Hz power supply. Critical Medical Equipment. Stabilizer required to improve site power quality. Price to be quoted separately.	No Change
8.2	Requirements for sign-off	User training manual is supplied.	No Change
8.3	Training of staff (medical paramedical, technicians)	Technical training provided for the staff employed at the time of installation.	No Change
8.4	Efficacy Performance	1. Latest Efficacy report, from a Govt. institute/ validation agency expert expert on clinical subjects & authentication, (not older than 1 year from the date of installation) for waste treated using the quoted product, should be submitted at the time of quoting tender & handed over to consignee during installation.	No Change
		2. Efficacy testing of the machine installed, should be done at the consignee location at the time of installation, using ready to use media.	No Change
9	**WARRANTY AND MAINTENANCE**		
9.1	Warranty	2 year warranty	This warranty shall remain valid for three years.
9.2	Maintenance tasks	included in warranty period	No Change
9.3	Service contract clauses, including prices	included in price quoted for warranty period.	No Change
10	**ELIGIBILITY CRITERION**		
10.1	OEM Turn Over	The minimum average annual financial turnover of the OEM/bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be average10 Crores per Annum with certified Audited Balance Sheets. In case of start ups/the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be 3 Crores Per Annum taken into account for this criteria.	Deleted

Page 6 of 9

10.2	Past Performance/ Experience	The OEM {themselves or through reseller(s)}should have regularly, manufactured and supplied same Category Microwave technology Products to any Central/ State Govt Organization / PSU / Public Listed Company for the last 2 Financial Yrs. The quoted product must have atleast 20+ Nos installation in various reputed govt organizations in any one of the the last 2 yrs and should be working satisfactorily. Products with Installations in AIIMS hospitals will be given preference. Order Copies & Performance Certificates enclosed shall be given preference.	Deleted
11	**DOCUMENTATION**		
11.1	Operating manuals, service manuals, other	Yes, supplied at the time of installation	No Change
11.2	Recommendations for maintenance	Yes, supplied at the time of installation	No Change
12	**NOTES**		
12.1	Service Support Contact details (Hierarchy Wise; including helpline number)	24X7 Dedicated Helpline for Customer Support	No Change
12.2	Recommendations or warnings	All instructions are clearly provided on the machine and is included in the user manual. No special uniform is required to operate the machine.	No Change
12.3	Consumables & Accessories	**Customized Biodegradable Bags - 20/45/75 L**	Customized Biodegradable Bags - 35 ltr or higher
		· Specially designed, virgin plastic Microwaveable, non-chlorinated, Bio-degradable, double seam secured edges bags.	No Change
		· All bags are customized with bio-hazard sign and preprinted as per CPCB norms / BMW management rules 2016.	No Change
		· All bags of durable 55 micron thickness, Microwavable Material, ensuring puncture proof and liquid leakage.	No Change
		· Available in CPCB defined colour code of yellow, red, blue and black.	No Change

Page 7 of 9

· Available Capacity: 20 L / 45 L / 75 L or as per customer's requirement.	Available Capacity: 35 Ltr or Higher .
Maser Bins for Microwave	No Change
· Customized Microwave compatible Bins for dedicated utility with OptiMaser.	No Change
· Available Capacities: 20 L / 45 L / 75 L.	No Change
· Models: Maser Bin-10 / Maser Bin-30 / Maser Bin-60	No Change
Maser Trolley - Stainless Steel	No Change
· Customized Maser Trolley for transportation of Maser Bins.	No Change
· Made of 25mm dia. Stainless Steel heavy gauge round pipe, ergonomically contoured for sleek design.	No Change
· Dimensions: 1040mm H x 400mm W x 605mm D.	No Change
· Retractable Bin base platform of 400mmx 360mm, with guided S.S. ring to accommodate Bin and foot operated hydraulic height adjustability.	No Change
· All SS parts, duly buffed for polished finish.	No Change
· Mounted with frictionless, 180mm dia smooth castors wheels & push handles with nylon sleeves for ease of carting.	No Change
Self Contained Biological Indicators (SCBI)	No Change
· The SCBI for monitoring efficacy of Microwave Disinfection Process consists of :	No Change
· a) A thermo-plastic Vial containing a spore disc with 10^8 population of Bacillus atrophaeus spores.	No Change
· b) Modified Tripticas Soybroth (TSB) with a pH indicator as growth medium, encased in a hermetically sealed glass ampoule.	No Change
Process Recorder Print Media	No Change
· Description: Thermal Paper Rolls for print records customized for use with Opti Maser	No Change
· Size: 55mm x 43 mm (dia.)	No Change
· Length of Roll: 25 Mtr.	No Change
· Pack Size: 12 Rolls per packet	No Change

Page 8 of 9

		· Cost-effective thermal paper for ink & ribbon-free system delivering high-quality printing.	No Change
		· This innovative, fine paper is coated with an invisible layer of chemicals that changes color when it's exposed to heat, resulting in a highly accurate, crisp print time after time.	No Change
12.3	Accessories on Purchase	Optiobnal accessories to be quoted separately Microwaveable Bins (For extra quantities) Bin transport trolleys, Digital Servo Stablizer Hub connectivity for Concurrent audits.	No Change

Page 9 of 9

5/21/26, 12:41 PM about:blank

Bihar Medical Service & Infrastructure Corp. Ltd
2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura,
Adjacent to State Health Society,Patna-800014, Bihar

Purchase Order Register (Annual PO) For All Circles Between 22-Feb-2026 and 21-May-2026

S No.	PO No. /Date	Supplier Name	Tender No	Drug Name	Manufacturer Name	Item Code	Po Quantity	Rate	Total Price (INR) Exclusive of Taxes	Total Tax Amt. (INR)	Total Price (INR) Inclusive of Taxes
1	BMSICL/DRUGS/2026-2027/405 (10282600973) / 28-Apr-2026	S S Medical System India Pvt. Ltd.	BMSIC/2023-24/ME-317	Bins for Microwave 45L [S0485] [NON-EDL]	S S Medical System India Pvt. Ltd.	S0485	11000 No.	11474.0000/No.	126214000.00	22718520.00	148932520.00
								Grand Total :	**126214000.00**	**22718520.00**	**148932520.00**
								Grand Total (In Words) :	**Twelve Crore Sixty Two Lac Fourteen Thousand Rupees Only**	**Two Crore Twenty Seven Lac Eighteen Thousand Five Hundred Twenty Rupees Only**	**Fourteen Crore Eighty Nine Lac Thirty Two Thousand Five Hundred Twenty Rupees Only**

5/21/26, 12:42 PM about:blank

Bihar Medical Service & Infrastructure Corp. Ltd
2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura,
Adjacent to State Health Society,Patna-800014, Bihar

Purchase Order Register (Annual PO) For All Circles Between 23-Feb-2026 and 21-May-2026

S No.	PO No. /Date	Supplier Name	Tender No	Drug Name	Manufacturer Name	Item Code	Po Quantity	Rate	Total Price (INR) Exclusive of Taxes	Total Tax Amt. (INR)	Total Price (INR) Inclusive of Taxes
1	BMSICL/DRUGS/2026-2027/406 (10282600974) / 28-Apr-2026	S S Medical System India Pvt. Ltd.	BMSIC/2023-24/ME-317	Bins for Microwave 75L [S0486] [NON-EDL]	S S Medical System India Pvt. Ltd.	S0486	7000 No.	15490.0000/No.	108430000.00	19517400.00	127947400.00
								Grand Total :	**108430000.00**	**19517400.00**	**127947400.00**
								Grand Total (In Words) :	**Ten Crore Eighty Four Lac Thirty Thousand Rupees Only**	**One Crore Ninety Five Lac Seventeen Thousand Four Hundred Rupees Only**	**Twelve Crore Seventy Nine Lac Fourty Seven Thousand Four Hundred Rupees Only**

अपने 'दवा एवं चिकित्सा उपकरण खरीद मैनुअल, 2018' के नियम 3(10) के अनुसार करेक्शन नोटिस के बाद कम से कम 37 दिन का समय बोलीदाताओं को दिया जाना अनिवार्य था। यहां उल्टा हुआ-समय-सीमा बढ़ाने के बजाय घटा दी गई। नतीजा, सात फर्मों ने बोली लगाई, लेकिन शिकायत के अनुसार इनमें से दो-मैसर्स एस.एस. मेडिकल सिस्टम और मैसर्स न्यूजेन एसोसिएट्स कथित तौर पर एक ही दो व्यक्तियों के नियंत्रण में थीं, जिससे 'प्रतिस्पर्धा' महज एक दिखावा बनकर रह गई। 26 अक्टूबर 2025 की तकनीकी समिति की बैठक में न्यूजेन एसोसिएट्स को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया, जबकि उसके बिड दस्तावेजों को कथित तौर पर दोषपूर्ण/फर्जी बताया गया है। ***यानी टेंडर के हर मोड़ पर पात्रता से लेकर मूल्यांकन तक एक ही दिशा में झुकाव साफ नजर आता है-मैसर्स एस.एस. मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की तरफ।***

❖ **आंकड़ों का असली खेल : दस से बारह गुना की खुली लूट :-** अब बात उन आंकड़ों की, जो इस पूरे मामले को शक से यकीन में बदल देते हैं। BMSICL के अपने परचेज ऑर्डर रजिस्टर (1 अप्रैल 2023 से 7 जुलाई 2026) की तुलना जब चार स्वतंत्र बाजार आपूर्तिकर्ताओं (बजट सप्लाइज, मेडइक्विप ट्रेडर्स, हेल्थटेक सॉल्यूशंस और एआरवी सप्लाइज) की दरों से की गई, तो सामने आया :-

उत्पाद	BMSICL दर (प्रति यूनिट)	औसत बाजार दर (प्रति यूनिट)	अंतर
कस्टमाइज्ड बायोडिग्रेडेबल बैग-45 लीटर	69.00 रू०	5.75 रू०	लगभग **12 गुना**
कस्टमाइज्ड बायोडिग्रेडेबल बैग-75 लीटर	98.00 रू०	8.50 रू०	लगभग **11.5 गुना**
माइक्रोवेव के लिए बिन-45 लीटर	11,474.00 रू०	1,162.50 रू०	लगभग **9.9 गुना**
माइक्रोवेव के लिए बिन-75 लीटर	15,490.00 रू०	1,550.00 रू०	लगभग **10 गुना**

यह कोई मामूली दर-अंतर नहीं है-यह वह अंतर है, जो केवल तब पैदा होता है जब कोई सरकारी खरीद तंत्र जानबूझकर आंखें मूंद ले,

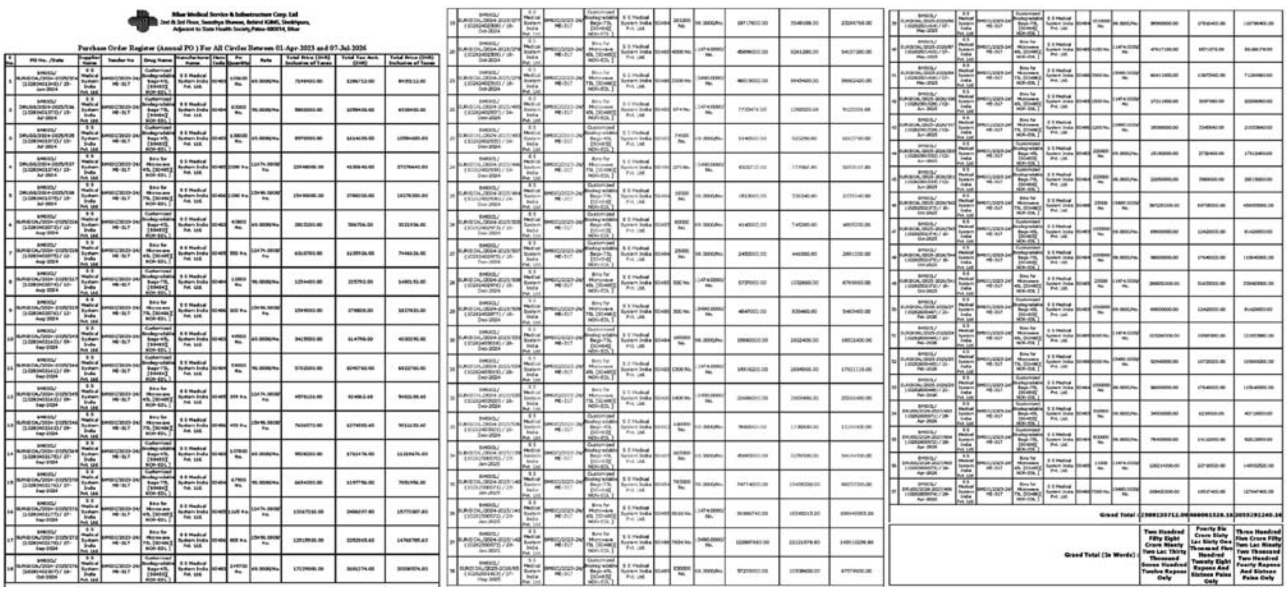

Bihar Medical Service & Infrastructure Corp. Ltd
2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura, Adjacent to State Health Society, Patna-800014, Bihar

Purchase Order Register (Annual PO) For All Circles Between 01-Apr-2023 and 07-Jul-2026

S No.	PO No. /Date	Supplier Name	Tender No	Drug Name	Manufacturer Name	Item Code	Po Quantity	Rate	Total Price (INR) Inclusive of Taxes	Total Tax Amt. (INR)	Total Price (INR) Inclusive of Taxes
								Grand Total	[illegible]	[illegible]	3055292240.16
								Grand Total (In Words) :	Two Hundred Fifty Eight Crore Ninety Two Lac Thirty Thousand Seven Hundred Twelve Rupees Only	Fourty Six Crore Sixty Lac Sixty One Thousand Five Hundred Twenty Eight Rupees And Sixteen Paisa Only	Three Hundred Five Crore Fifty Two Lac Ninety Two Thousand Two Hundred Fourty Rupees And Sixteen Paisa Only

या मूंदने पर मजबूर किया जाए। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2026 के बीच जारी हुए कुल 57 परचेज ऑर्डरों पर यह गणित लागू करें तो :-

विवरण	**राशि (जीएसटी रहित)**	**राशि (जीएसटी सहित 18%)**
BMSICL का कुल भुगतान (57 पीओ)	25,89,23,071 (258.92 करोड़)	30,55,29,224 (305.53 करोड़)
उतनी ही मात्रा की बाजार कीमत	2,47,02,307 (24.70 करोड़)	2,91,48,723 (29.15 करोड़)
सरकारी खजाने को अतिरिक्त नुकसान	23,42,20,764 (234.22 करोड़)	27,63,80,501 (276.38 करोड़)

यही वह आंकड़ा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल 276 करोड़ रुपए की लूट के दावे की बुनियाद है और यह किसी विपक्षी नेता की कल्पना नहीं, बल्कि निगम के अपने रिकॉर्ड से निकला हिसाब है।

❖ **निशाने पर दो नाम : देवरे और सीमा, जिनके कार्यकाल में हुई सबसे बड़ी लूट :-** अब आते हैं इस पूरे प्रकरण के सबसे संवेदनशील हिस्से पर। इन 57 परचेज ऑर्डरों में एक ऑर्डर ऐसा है, जो अकेले पूरे घोटाले की सबसे भारी कड़ी है-**16 अक्टूबर 2025** को जारी हुआ परचेज ऑर्डर, जिसकी कीमत बिना जीएसटी के करीब **84.11 करोड़ रू०** है और जो मैसर्स एस.एस. मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जारी हुआ। दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्ज करते हैं कि यह ऑर्डर उस समय जारी हुआ, जब BMSICL के प्रबंध निदेशक पद पर **डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे, आईएएस (बिहार कैडर, 2011 बैच),** जिन्होंने 10 जून 2025 से 1 जनवरी 2026 तक यह पद संभाला और मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) के पद पर **कुमारी सीमा** तैनात थीं। शिकायत के अनुसार, इसी एक ऑर्डर से बाजार दर की तुलना में सरकारी खजाने को करीब **75.90 करोड़ रू० का सीधा नुकसान** हुआ। यानी अकेले एक हस्ताक्षर, एक फैसले से, इतनी बड़ी रकम राज्य के गरीब मरीजों के हिस्से से निकलकर एक निजी कंपनी की तिजोरी में चली गई।

यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस अवधि (अप्रैल 2024 से आगे) में यह और बाकी बड़े परचेज ऑर्डर जारी हुए, उसी अवधि में BMSICL की कमान इन्हीं दो अधिकारियों के हाथों में थी। शिकायतकर्ता ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की है कि इस विशिष्ट ऑर्डर की परिस्थितियों-क्या यह किसी वास्तविक जरूरत के आकलन पर

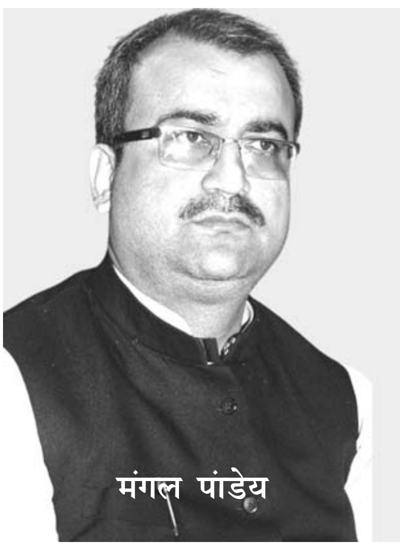

मंगल पांडेय

डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे

कुमारी सीमा

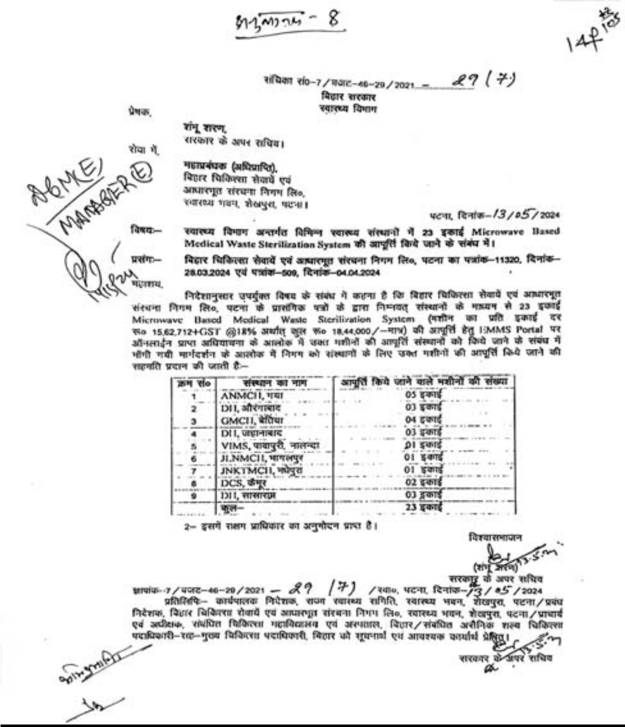

अनुलग्नक - 8

147

संचिका सं0-7/बजट-46-29/2021 - 27 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति),
बिहार चिकित्सा सेवायें एवं
आधारभूत संरचना निगम लि०,
स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना।

पटना, दिनांक-13/05/2024

विषय:- स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 23 इकाई Microwave Based Medical Waste Sterilization System की आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक-11320, दिनांक-28.03.2024 एवं पत्रांक-509, दिनांक-04.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा निम्नवत् संस्थानों के माध्यम से 23 इकाई Microwave Based Medical Waste Sterilization System (मशीन का प्रति इकाई दर रू० 15,62,712+GST @18% अर्थात् कुल रू० 18,44,000/-मात्र) की आपूर्ति हेतु EMMS Portal पर ऑनलाईन प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त मशीनों की आपूर्ति संस्थानों को किये जाने के संबंध में मांगी गयी मार्गदर्शन के आलोक में निगम को संस्थानों के लिए उक्त मशीनों की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	संस्थान का नाम	आपूर्ति किये जाने वाले मशीनों की संख्या
1	ANMCH, गया	05 इकाई
2	DH, औरंगाबाद	03 इकाई
3	GMCH, बेतिया	04 इकाई
4	DH, जहानाबाद	03 इकाई
5	VIMS, पावापुरी, नालन्दा	01 इकाई
6	JLNMCH, भागलपुर	01 इकाई
7	JNKTMCH, मधेपुरा	01 इकाई
8	DCS, कैमूर	02 इकाई
9	DH, सासाराम	03 इकाई
	कुल-	23 इकाई

2- इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-7/बजट-46-29/2021 - 27 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक-13/05/2024

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्राचार्य एवं अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

आधारित था या कृत्रिम रूप से मांग गढ़ी गई थी, की स्वतंत्र जांच हो और साथ ही यह भी जांचा जाए कि इतने बड़े मूल्य के ऑर्डर पर मंजूरी देने से पहले प्रबंध निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) के स्तर पर बाजार-दर सत्यापन (मार्केट रेट वेरिफिकेशन) की न्यूनतम प्रक्रिया भी अपनाई गई या नहीं। एक ऐसे संगठन में, जहां हर बड़ी वित्तीय स्वीकृति अंततः प्रबंध निदेशक के डेस्क से होकर गुजरती है, दस गुना अधिक दर पर 84 करोड़ रुपए का ऑर्डर स्वीकृत होना, बिना किसी स्तर पर सवाल उठे प्रशासनिक लापरवाही से कहीं आगे की कहानी कहता प्रतीत होता है।

पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका (CWJC 4058/2026) में भी इन्हीं दोनों अधिकारियों के नाम प्रमुखता से दर्ज हैं और शिकायतकर्ता ने अपनी मांगों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रस्तावित उच्च-स्तरीय जांच समिति को 'BMSICL के वर्तमान व पूर्व प्रबंधन, जिसमें इसके पूर्व प्रबंध निदेशक श्री निलेश रामचंद्र देवरे, आईएएस और इसकी मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला), कुमारी सीमा शामिल हैं, के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त' रखा जाए। यह मांग स्वयं इस बात का संकेत है कि शिकायतकर्ता को इन दोनों अधिकारियों की भूमिका पर कितना गहरा संदेह है-इतना गहरा कि वे जांच की निष्पक्षता के लिए इन्हें प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रखने की मांग तक कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ. देवरे को 30 दिसंबर 2025 के सरकारी आदेश से BMSICL के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया और यह जिम्मेदारी अन्य अधिकारी को सौंप दी गई, यानी ठीक उसी दौर में जब यह पूरा मूल्य-विसंगति प्रकरण सतह पर आना शुरू हुआ। सवाल यह है कि क्या यह महज प्रशासनिक फेरबदल था या समय रहते हटाई गई एक जिम्मेदारी?

❖ **अस्पताल की जगह गोदाम और दवा के मद से भुगतान :-** स्वयं BMSICL अपने काउंटर एफिडेविट में स्वीकार करता है कि याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि टेंडर की शर्तों के विपरीत, जिनमें माल की सीधी आपूर्ति अस्पतालों तक करने की बात कही गई थी, सामान क्षेत्रीय गोदामों (रीजनल वेयरहाउस) में भेजा गया, न कि सीधे उन अस्पतालों में जहां इसकी जरूरत थी। यह डायवर्जन आपूर्तिकर्ता को अंतिम-मील परिवहन लागत बचाने में मददगार साबित हुआ। एक लागत जो टेंडर की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को स्वयं वहन करनी थी, जबकि इसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ा। दवाओं और मेडिकल उपकरणों के लिए बने गोदामों में 'कूड़ेदान' जैसी वस्तुओं का इस तरह अनियमित रूप से स्टॉक होना और वह भी बगैर उचित कंसाइनी अनुदेश के केवल लॉजिस्टिक लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर बनाई गई एक व्यवस्था प्रतीत होती है, जिसमें जवाबदेही को धुंधला रखा गया। **इसके साथ एक और गंभीर आरोप है-फंड डायवर्जन** का। शिकायत और याचिका, दोनों में यह दावा किया गया है कि यह पूरी खरीद बगैर उचित बजट आवंटन के की गई और दवाओं की खरीद के लिए निर्धारित धनराशि को इन 'बायो-मेडिकल वेस्ट' उत्पादों के भुगतान में मोड़ दिया गया यानी जो पैसा गरीब मरीजों की जीवनरक्षक दवाओं पर खर्च होना था, वह प्लास्टिक के डिब्बों की फुलाई गई कीमतों में झोंक दिया गया। BMSICL इसे 'गलत' बताते हुए कहता है कि वर्क ऑर्डर स्वास्थ्य विभाग से 13 मई 2024 को मिली लिखित अनुमति के बाद ही जारी हुआ, लेकिन एक 'लिखित अनुमति' का होना यह साबित नहीं करता कि खर्च की गई राशि की मात्रा और दर, दोनों उचित थीं।

❖ **23 मशीनों का ऑर्डर, आपूर्ति सिर्फ पांच की : बाकी क्यों गायब? :-** इस पूरे प्रकरण की एक और परत जो शिकायत में शामिल है, बेहद चौंकाने वाली है। आरोप है कि बिहार सरकार ने इसी फर्म को 23 माइक्रोवेव आधारित स्टरलाइजेशन मशीनों की आपूर्ति का आदेश दिया था, लेकिन इनमें से महज पांच मशीनें ही वास्तव में आपूर्ति की गईं। बाकी 18 मशीनें कहां गईं? क्यों नहीं पहुंचीं? आरोप है कि इसका सीधा जवाब यह है कि छोटी-मूल्य वाली वस्तुओं-डिब्बों और बैगों में जितना कृत्रिम मुनाफा बार-बार, अलग-अलग पर्चेज ऑर्डरों के जरिए निकाला जा सकता था, वह बड़ी, आसानी से जांची-परखी जा सकने वाली मशीनों की वास्तविक आपूर्ति में संभव नहीं था। यदि यह सच साबित होता है, तो यह इस पूरी योजना की असली मंशा उजागर करता है। उद्देश्य उपकरण उपलब्ध कराना कभी था ही नहीं; उद्देश्य था बार-बार दोहराए जाने वाले, कम-जांचे जाने वाले छोटे आइटमों के जरिए सरकारी खजाने से लगातार भुगतान निकलवाना। यही वजह है कि बिन और बैग के लिए 57 अलग-अलग पर्चेज ऑर्डर जारी होते रहे, जबकि जिस मूल मकसद के लिए टेंडर निकाला गया था, वे मशीनें अधूरी आपूर्ति में उलझी रहीं। इस बिंदु की स्वतंत्र, दस्तावेज-आधारित जांच अब सबसे जरूरी मांगों में से एक है।

❖ **महालेखाकार (एजी) की ऑडिट रिपोर्ट : चूक या जानबूझकर अनदेखी? :-** इस पूरे मामले की एक और परेशान करने वाली परत है महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के कार्यालय द्वारा की गई ऑडिट है। पत्रांक संख्या-128/25-26 के इस निरीक्षण प्रतिवेदन में BMSICL के अप्रैल 2024 से नवंबर 2025 तक के लेखों की जांच 30 दिसंबर 2025 से 30 मार्च 2026 के बीच हुई, यानी ठीक वही अवधि जिसमें 57 के 57 परचेज ऑर्डर जारी हुए। इस रिपोर्ट में कई अनियमितताएं दर्ज हैं-प्राइस एस्केलेशन बिलों पर गलत सेंटेज वसूली से 82.40 लाख का नुकसान, बिना पर्याप्त दस्तावेजों के सिक्योर्ड एडवांस, सीएसआर मद में

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना | PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) BIHAR, PATNA | Birchand Patel Marg | सत्यमेव जयते

Reply has not been furnished by the management during Exit meeting.

Reference Number :

OBS-2433813

Subject:

Irregularities in Finalization of procurement of Microwave Based Medical Waste Sterilization system Tender

Detailed Observation:

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited invited tender for the procurement, Rate contract and Supply of Microwave Based Medical waste sterilization system for different Government Health Institution of Bihar Vide NIT No. BMSICL/2023-24/ME-317 dated 16.08.2023 . Government Medical College & Hospital, Madhepura and ANMCH Gaya have requested BMSICL to provide the same.

In NIT BMSICL specified the procurement quantity by 09 nos. with note that the quantity of equipment mention above may vary during the rate contract period depending upon the requisition from different health institution of Bihar.

In NIT all eligibility criteria including device specification were set as per Format of NHSRC (National Health System Resource Centre)

As per NIT Schedule pre-bid meeting was called on 28.08.2023 vide letter no. 4262 dated 18.08.2023. In pre bid meeting total 11 nos. of bidders participated with their queries and as per their queries many of the changes have been made and corrigendum was issued on 13.09.2023 with proposed changes in different parts of tender.

Further as per minutes of TSC meeting held on 05.09.2023 following clauses were deleted:

Clause no. 1.1(2) treats waste for upto 80 beded

Page 50 of 86

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना | PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) BIHAR, PATNA | Birchand Patel Marg | सत्यमेव जयते

- Clause no. 10.2 past performance/experience as described in eligibility criteria and
- Clause no 3.1 Dimension (mm) as described in physical characteristics in technical specifications.

During test check of the records following irregularities were observed :-

1. As per the Manual for the procurement of Drugs equipment/ device 2017 which was notified by the Health Department, Government of Bihar vide its notification no. 870(2) dated 08.10.2018 Tender for equipment/ devices should be finalized by 75th day i.e. issue of LOI to L1 Bidder. As per procurement manual pre bid meeting should have been held on 7th day i.e 23.08.2023 but the meeting was held on 12th day from the date of NIT i.e. 28.08.2023.
2. After pre bid meeting TSC meeting was held on 05.09.2023 under the chairmanship of Director in Chief, Health Department, Government of Bihar with final amendment and corrigendum was issued on 13.09.2023 and technical bid was open on 20.09.2023 i.e. by 34th day but as per manual it should be by 37th day, 3 days before technical bid was opened.
3. Technical evaluation committee was held on 26.10.2023 wherein two bidder viz. M/s Neuzen Associates Pvt. Ltd and M/s S. S. Medical System (I) Pvt. Ltd. were declared qualified i.e. by 70th day with decision to recommend for demonstration of the equipment. As per manual committee evaluated the bid by delay of 10 days. During scrutiny of records, it was also observed that document submitted by M/s Neuzan Associates Pvt. Ltd. relating to installation of equipment shows Forsta Medtech which shows ambiguity of performance as required in Tender.
4. Both the qualified bidders demonstrated their equipment on 27.12.2023 i.e. by 133 days from NIT whereas manual says the demonstration should be by 60th day total delay period was 73 days.
5. Financial Committee meeting held on 09.01.2024 wherein M/s S. S. Medical System (I) Pvt. Ltd. was declared L1 with quoted rate of 1563254.23 per unit without GST. After price justification vendor agreed to supply the equipment @ 1562711.86 per unit without GST. Bidder also quoted the price of accessories and consumables which are being used in equipment. Letter of Intent/award was issued on 24.01.2024 vide letter No. 8906. As per manual LoI should be issued by the 75th day but the same was issued by delay of 161 day from the date of NIT.

Page 51 of 86

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना | PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) BIHAR, PATNA | Birchand Patel Marg | सत्यमेव जयते

6. Company deleted clause 1.1(2) " Treat waste for upto 80 bedded hospital", clause 3.1 "Dimension of equipment" and clause 10.1 "OEM turnover". All the eligibility criteria was set by NHSRC, Govt. of India.

All the changes were made as per the minutes of pre bid meeting but why it was accepted? It was not available in the records of the company.

7. Clause 3 of Special condition of contract of NIT " The bidders are expected to quote their best rates for the equipment. The rates quoted by the bidder shall remain valid for two year from the date of signing of contract/ issuing of notification of award (whichever is earlier) Similarly as per clause 3.2 of letter of award " The rate contract period of this equipment is valid for two years from the date of signing of agreement which may be extended upto further period of one year with mutual consent of both the parties executing the agreement" but the company signed the agreement "for the period of five years with provision of extension upto 10 years on mutual consent or till the life of these equipment provided, if at any point of time the prices of the consumables goes down the benefit of the different shall automatically accrue to the BMSICL" which is beyond the period defined in NIT as well as letter of Intent.

As per clause of NIT agreement period should have been for two years i.e. upto 06.02.2026 .

In view of the above irregularities, it seems that company was incurious to finalize the tender within stipulated time as defined in the Manual. As per records of the company it was also noticed that company hired M/s Piramal swasthya to evaluate the bid who also fail to examine the document as per tender criteria. Company procured Rs. 2645190320 value of consumable and accessories till date from M/s S. S. Medical System (I) Pvt. Ltd.

Facts and figure please be confirmed and reply of the same please be furnished to Audit.

Reply has not been furnished by the management.

Reference Number :

Page 52 of 86

मनमानी, डीपीआर पेनल्टी में अनुचित रियायत। लेकिन इस विस्तृत 86 पन्नों की रिपोर्ट में जो ठीक उसी अवधि और उसी संस्था को कवर करती है। BMW बिन्स और बायोडिग्रेडेबल बैग की खरीद में दस से बारह गुना अधिक कीमत की भारी-भरकम अनियमितता का कोई जिक्र तक नहीं है। यह चूक और गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि दस्तावेज यह भी बताते हैं कि ऑडिट टीम ने खुद इसी अवधि में BMSICL की मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) कुमारी सीमा के साथ आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की थी। सवाल लाजमी है **:** जब ऑडिट अधिकारी सीधे उसी अधिकारी से बात कर रहे थे, जिसके हस्ताक्षर से करोड़ों के ये परचेज ऑर्डर जारी हुए, तब इतने बड़े पैमाने की मूल्य-विसंगति ऑडिट की नजर से कैसे बच गई? शिकायतकर्ता ने इस पर सीधा सवाल उठाते हुए मांग की है कि इस चूक के लिए जिम्मेदार ऑडिट अधिकारियों-सचिन कुमार सिंह, अमर किशोर, प्रदीप कुमार और रवींद्र कुमार के आचरण की भी स्वतंत्र जांच हो। यह केवल एक ऑडिट टीम की तकनीकी असफलता नहीं, बल्कि यह संदेह पैदा करता है कि क्या निगरानी तंत्र की आंखों में भी धूल झोंकी गई।

❖ **पटना हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन :-** याचिका, CWJC संख्या 4058/2026, याचिकाकर्ता कौशलेश कुमार ने बिहार सरकार व अन्य के विरुद्ध दाखिल की है और अभी विचाराधीन है। इसी में BMSICL ने अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है। इस याचिका में टेंडर संख्या BMSICL/2023-24/ME-317 से जुड़ी अनियमितता, प्रयोगशाला एम्पैनलमेंट व गुणवत्ता जांच में गड़बड़ी, एक अधिकारी की संपत्ति संबंधी शिकायतें और एक अन्य परियोजना में निर्माण गुणवत्ता के आरोप सहित इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने 16 अक्टूबर 2025 के परचेज ऑर्डर पर भुगतान रोकने, एफआईआर/विजिलेंस/सीबीआई जांच दर्ज करने तथा विभागीय व वसूली कार्रवाई की मांग की है।

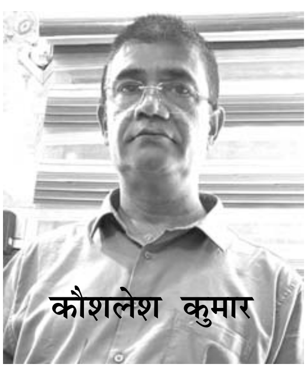

कौशलेश कुमार

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.4058 of 2026

Kaushlesh Kumar

... ... Petitioner/s

Versus

The Union of India & Ors.

... ... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Sanjeev Kumar Mishra, Advocate
For the State	:	Mr. S.D. Sanjay, Advocate General Mr. Mohit Agarwal, AC to AG
For the BMSICL	:	Mr. Lalit Kishore, Sr. Advocate Mr. Ayush Kumar, Advocate Mr. Kanishka Shanker, Advocate
For the UOI	:	Mr. Abhishek Kumar, Advocate

CORAM: HONOURABLE THE ACTING CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE RAJESH KUMAR VERMA
ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

7 10-08-2026 As prayed for, by learned counsel for the State as well as B.M.S.I.C.L., further four weeks' time is granted to comply with the order dated 13.07.2026.

2. Put up this case on 07.09.2026.

(Sudhir Singh, ACJ)

(Rajesh Kumar Verma, J)

Vanisha/anushka

U

WEB COPY

❖ **BMSICL का बचाव पक्ष : 'पूरी फाइल देखे बिना निष्कर्ष निकालना गलत' :-** निष्पक्षता की दृष्टि से BMSICL का पक्ष भी सामने रखा जाना चाहिए, भले ही वह कमजोर क्यों न लगे। निगम की ओर से अदालत में दाखिल जवाब में कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया-प्रकाशन, प्री-बिड बैठक, करेक्शन नोटिस, तकनीकी मूल्यांकन और मुख्य अवार्ड प्रक्रिया, यह सब वर्ष 2023 में ही पूरी हो चुकी थी, यानी डॉ. देवरे के प्रबंध निदेशक बनने (जून 2025) से बहुत पहले। यह दलील टेंडर की मूल डिजाइन तक तो सीमित तर्क दे सकती है, लेकिन 16 अक्टूबर 2025 के 84.11 करोड़ रुपए के उस विशिष्ट परचेज ऑर्डर पर खामोश है, जो इन्हीं अधिकारियों के कार्यकाल में जारी हुआ। निगम ने 75-90 करोड़ या संचयी रूप से 200 करोड़ रुपए के नुकसान के आंकड़ों को 'अनऑडिटेड एक्स्ट्रापोलेशन' बताते हुए खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन यह गणित तो खुद निगम के अपने परचेज ऑर्डर रजिस्टर और खुले बाजार की दरों से निकाला गया है, किसी अनुमान या कल्पना से नहीं। वर्तमान प्रबंध निदेशक सुब्रत सेन का सार्वजनिक बयान भी यही दोहराता है कि यह खरीद उनके पूर्ववर्ती के कार्यकाल में हुई। यह तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी संस्थागत भ्रष्टाचार तभी संभव होता है जब उस समय के जिम्मेदार पदाधिकारी-चाहे वे आज पद पर हों या न हों, अपने कार्यकाल के फैसलों की जवाबदेही से बच नहीं सकते। पद बदल जाने से जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती।

बीएमडब्ल्यू बिन्स घोटाला

❖ **सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला मामला :-** यह विवाद अगस्त 2026 के मध्य में सोशल मीडिया पर उस समय भड़का जब रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा-'सम्राट सरकार का एक और झोल... डस्टबिन भी हुआ अनमोल। बिहार में डस्टबिन भी 'वीवीआईपी' हो गया!!' इसके बाद बिहार के कई प्रभावशाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिनमें मनीष कश्यप और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी शामिल हैं, इस मुद्दे को उठाने लगे। पत्रकार मनीष कश्यप ने दानापुर अनुमंडल अस्पताल से जुड़े दस्तावेजों के हवाले से दावा किया कि वहां 45 लीटर के प्लास्टिक डस्टबिन की कीमत 11,000 रुपए और 75 लीटर वाले की कीमत 15,490 रुपए तक चुकाई गई। रिपोर्टों के अनुसार यह मामला मूल रूप से एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा उठाया गया, जिसे बाद में स्थानीय पत्रकारों और सोशल मीडिया प्रभावितों ने आगे बढ़ाया। राजनीतिक स्तर पर विपक्षी राजद ने इसे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कार्यकाल से जोड़ते हुए करीब 300 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया, जिसका आंकड़ा कुछ रिपोर्टों में बढ़कर लगभग 700 करोड़ रुपए तक होने की भी बात कही गई। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि केवल सोशल मीडिया पर बिल वायरल कर देने से घोटाला साबित नहीं हो जाता। एक ऐसी दलील, जो तब तक जायज थी, जब तक खुद निगम के अपने दस्तावेज और अदालत में दाखिल काउंटर एफिडेविट इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर रहे थे।

नीरज कुमार

गौरतलब है कि यह विवाद बिहार में स्वास्थ्य और अवसंरचना क्षेत्र में जारी बड़े भ्रष्टाचार जांच के परिदृश्य में सामने आया है। इसी वर्ष बिहार की विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने BMSICL के एक उप-महाप्रबंधक के ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 96 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का पता लगाने का दावा किया और एक अलग टेंडर घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व एसवीयू ने बिहार के कई आईएएस अधिकारियों समेत दर्जन भर अफसरों पर कार्रवाई की, जिसमें BMSICL से जुड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए। यह दिखाता है कि BMSICL कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा संस्थान बन चुका है जहां बार-बार वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं।

❖ **जवाबदेही से बच निकलना अब मुश्किल : जांच की मांग और कानूनी आधार :-** शिकायतकर्ता ने इस पूरे प्रकरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 465/468/471 (जालसाजी व फर्जी दस्तावेज का प्रयोग) तथा धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) अथवा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के समतुल्य प्रावधानों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 व 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के दायरे में बताया है। स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि प्रस्तावित जांच समिति डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे और कुमारी सीमा, दोनों के 'प्रभाव से पूरी तरह मुक्त' होकर काम करे, ताकि इनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) स्तर की स्वतंत्र जांच, बाजार-दर आधारित फॉरेंसिक ऑडिट, अवैध रूप से भुगतान की गई पूरी राशि की वसूली तथा संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के निलंबन/ब्लैकलिस्टिंग की मांग की गई है।

यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि अंतिम रूप से किसी को 'दोषी' ठहराने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय और जांच एजेंसियों को है। यह आलेख किसी व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों, आरोपों और सवालों की एक ईमानदार, बेबाक प्रस्तुति है। लेकिन जो तथ्य सामने हैं 84.11 करोड़ रुपए का एक अकेला ऑर्डर, ठीक उसी कार्यकाल में जब देवरे और सीमा निगम की कमान संभाल रहे थे; ऑडिट टीम की सीमा से सीधी बातचीत के बावजूद विसंगति का ऑडिट रिपोर्ट में गायब होना; और खुद शिकायतकर्ता की यह मांग कि जांच को इन्हीं दोनों अधिकारियों के 'प्रभाव से मुक्त' रखा जाए। यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं, जिसमें इन दोनों नामों की जवाबदेही तय किए बिना जांच अधूरी रहेगी। यदि निर्दोष हैं, तो पारदर्शी जांच में यह साबित होना उन्हीं के हित में है; और यदि दोषी पाए जाते हैं, तो बिहार के गरीब मरीजों की जीवनरक्षक धनराशि के इस दुरुपयोग के लिए सबसे कठोर कार्रवाई ही न्यायोचित होगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेजे गए ज्ञापन का जवाब अभी लंबित है, जबकि पटना हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है।

अंततः यह तय करना अदालत और जांच एजेंसियों का काम है कि इस पूरे प्रकरण में आपराधिक साजिश थी या प्रशासनिक विफलता, लेकिन इतना तय है कि 276 करोड़ रुपए के इस 'BMW बिन्स' विवाद ने बिहार की सार्वजनिक खरीद व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसमें नामित अधिकारियों की जवाबदेही से बच निकलना अब आसान नहीं होगा।●

भरत तिवारी पर गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान हुआ गिरफ्तार

सीएम सम्राट का ऐलान भरत तिवारी के परिजनों को मिलेगा मुआवजा और सरकारी नौकरी

● अमित कुमार

न्यायालय की शरण में न्याय पाने की उम्मीद लगाये भरत तिवारी के परिजनों के लिए उस वक्त बेहद खुशी भरा होगा जब उनके बेटे भरत को पहली गोली मारने वाले एसटीएफ जवान अक्षय कुमार जब गिरफ्तार किया गया। बता दें कि चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने एक बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। परिजनों के भारी आक्रोश और लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के बाद, प्रशासन ने आखिरकार बड़ा कदम उठाते हुए भरत तिवारी पर गोली चलाने के आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर अड़ा हुआ था। वे आरोपी एसटीएफ जवान की तुरंत गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बना रहा थे। परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपी जवान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। इस संवेदनशील मामले में बढ़ते जनाक्रोश और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन हरकत में आयी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच को तेज किया गया। शुरुआती सबूतों और बयानों के आधार पर एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को हिरासत में ले लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है ताकि एनकाउंटर के समय की वास्तविक परिस्थितियों, आत्मरक्षा के दावों और गोलीबारी की वजहों का पूरी तरह से पता लगाया जा सके। इस गिरफ्तारी को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। दरअसल, भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। ग्रामीणों और परिजनों की माने तो 17 जून को पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। पूरे गांव में आक्रोश का माहौल था। पुलिस ने एनकाउंटर में दावा किया था कि भरत तिवारी के पास हथियार थे, वे पुलिस टीम पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उनकी मौत हुई। हालांकि, भरत तिवारी के उस दौरान के वीडियो में देखा गया कि भरत तिवारी सरेंडर करने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने गोली चलाकर उनका एनकाउंटर कर दिया। परिजनों और लोगों का भी कहना है कि भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उस पर गोली चलाई गई।

गौरतलब है कि भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में बिहार की आरा सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए मुख्य दंडाधिकारी (CJM) ने 11 आरोपियों के

खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया, साथ ही कोर्ट ने भोजपुर एसपी से इस मामले में अंतरिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) को 12 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में भरत तिवारी के पक्ष से केस लड़ रहे अधिवक्ता के बयान के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि इस मामले में फिलहाल कोई नॉन बेलेवल वारंट जारी नहीं किया गया। बल्कि इस मामले में जो मिसलेनियस फाइल किया गया था, उसके सभी बिंदुओं पर भोजपुर एसपी मिस्टर राज से कांड का अंतरिम रिपोर्ट मांगी है, फिलहाल गैर जमानती वारंट जैसा कोई बात नहीं है।

दरअसल सुनवाई के बाद भरत तिवारी के अधिवक्ता से पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आज ये कोर्ट के द्वारा नॉन बेलेवल वारंट किया है पर अधिवक्ता ने कहा कि आज हमने एफआईआर नंबर-178/2026 में जो है क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन लगाया था, नॉन बेलेवल वारंट के लिए। साथ-साथ जो अभी तक कितना गिरफ्तार हुआ है, क्या जांच रिपोर्ट है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एवीडेंस जो रिकॉर्ड हुए हैं और जो मोबाइल में जो एवीडेंस हैं और चौदह सौ करोड़ का घोटाला है जो सारा प्राथमिक अभियुक्त जो थे जैसे डीएसपी राजेश कुमार शर्मा, दूसरा एसएसओ राजेश मालाकार, तीसरा जो है अक्षय कुमार अरेस्ट हो गया है, चौथा विकास कुमार पुलिस है, पांचवा रविंद्र है, अंकित आर्यन है, रामचंद्र है, हरिशचंद्र है। ये सारे पुलिस वाले हैं जो कि हत्याकांड में शामिल थे और इसके अलावा जो चौदह सौ करोड़ का घोटाला और हत्या का जो मास्टरमाइंड, जो अप्राथमिक जिसका नाम आया है। गवाहों के जो मुख्य जो शिकायत करते हैं, जो आशा देवी हैं उन्होंने एसडीएम को अपने गवाही में मास्टर माइंड बताया है। सभी अपराधियों के लिए ग्यारह प्रार्थना था मेरा कि स्टेटस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एवीडेंस, मोबाइल एवीडेंस, इंवेस्टीगेशन रिपोर्ट और इसके साथ नॉन बेलेवल वारंट है, यह सारी प्रार्थना को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने स्वीकार कर लिया हैं और 12 तारीख अगला डेट है।

बताते चले कि ये पूरा मामला भरत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने साजिश के तहत भरत तिवारी को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा था। अदालत की ओर से वारंट जारी किए जाने के बाद मृतक भरत तिवारी के परिवार में इंसाफ मिलने की नई उम्मीद जगी है। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भरत की मां और भाई ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने अन्याय किया था, अब अदालत से उन्हें न्याय मिलने का रास्ता साफ हुआ है। भरत की मां ने मांग की कि अदालत सभी दोषी अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए, ताकि उनके कलेजे को ठंडक पहुंचे।

राज
तत्कालिन भोजपुर एसपी

बहरहाल, भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर की चर्चा राज्य ही नहीं देश में गूंज रही है, ऐसे में भोजपुर एसपी राज का तबादला रोहतास कर दिया गया है। भोजपुर जिले के एसपी आईपीएस अधिकारी राज का बतौर पुलिस अधीक्षक करीब 23 महीने का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने 15 सितंबर 2024 को भोजपुर के 107वें एसपी के रूप में कमान संभाली थी। इस दौरान उन्हें तनिष्क आभूषण शोरूम लूटकांड समेत कई गंभीर आपराधिक घटनाओं की चुनौती का सामना करना पड़ा था। हालांकि, पुलिस ने अधिकांश गंभीर मामलों का सफल उद्‌भेदन करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके नेतृत्व में मिनी गन फैक्ट्री समेत करीब तीन सौ अवैध हथियारों और दो गुना कारतूस की बरामदगी हुई। एसपी राज के कार्यकाल में करीब चार पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हुई। इनमें सिर्फ एक मुठभेड़ को लेकर विवाद भी सामने आया, जिसमें एसटीएफ की भूमिका पर सवाल उठे। अब तबादले के बाद आइपीएस राज को रोहतास जिले की कमान सौंपी गई है। पदभार संभालने के बाद उनके सामने जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करना प्रमुख चुनौती होगी। इसके अलावा अवैध बालू कारोबार पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था को बेहतर करना भी उनके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

दिलचस्प बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। बता दे कि भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर से पहले मंच से उसे गिरफ्तार करने की बात कही थी, एनकाउंटर के बाद से ही सीएम सम्राट के लिए भरत तिवारी केश सर का दर्द बना हुआ था। ऐसे में सांसद मनोज तिवारी के साथ भरत के परिजनों से सीएम सम्राट की मुलाकात हुई थी और उन्होंने न्याय और आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया था। न्यायिक प्रक्रिया की पहली पहल में एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे आगे अन्य आरोपियों पर न्यायिक कार्रवाई होने की आश परिजनों में जगी है। दूसरी तरफ कहा गया है कि सरकार की ओर से सहायता मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। भरत तिवारी की मौत की परिस्थितियों को लेकर उठे सवालों के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। इस मामले की न्यायिक जांच पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में की जा रही है। जांच टीम घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं और एनकाउंटर की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों और घटना से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जांच टीम ने मामले से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। हालांकि आर्थिक सहायता के तौर पर परिवार को कितनी राशि दी जाएगी, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। ●